असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

04 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 04 जुलाई, 2019 ई0

त्रयोदश सत्र 13 आषाढ़, 1941 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल । अल्प-सूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गए)

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति है और जल-स्तर गिर गया है....

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पूरा बिहार सूखे की चपेट में है....

अध्यक्ष : कल भी न इसपर बात हुई थी !

श्री सत्यदेव राम : हमलोगों की मॉग है कि बिहार को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप मॉग कर लिये न !

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सुखाड़ से बिहार को निजात दिलाया जाय, पूरे प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अवधेश बाबू, आप कार्य स्थगन के समय में उठाइयेगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : उठायेंगे उसी समय लेकिन हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है...

अध्यक्ष : इसी विषय पर न 13 तारीख को सबका विमर्श है !

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, वह दूसरा इशू है । 12 बजे इसपर थोड़ा समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये हर दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं । हम तो समझते हैं कि ये जो माननीय सदस्य हैं, उनको पूरी तरह से मालूम है कि कार्य

स्थगन किस परिस्थिति में लाया जाता है । हर दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद रहे हैं ।

(व्यवधान)

जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोग हैं, ये सीनियर मोस्ट मेम्बर हैं, इस महत्वपूर्ण सवाल पर हल्का करने में लगे हैं । कार्य स्थगन पर चर्चा नहीं हो रही है, आप ध्यानाकर्षण में लाइये, सरकार जवाब भी देगी, चर्चा भी होगी । अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 13 तारीख को सभी माननीय सदस्य आइये और उसमें सभी विभाग के लोग बैठेंगे, पूरी तरह से विचार-विमर्श होगा । सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारे कदम उठाये हैं, उसको देखिये । इनको कुछ देखने से मतलब नहीं है, खाली सदन में आना है, अखबार और मीडिया का खबर बनाना है । अगर मीडिया के खबर बनने से राज्य में पानी आ जाय, राज्य सुखाड़ से निपट जाय, ऐसी स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठिये ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 । श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी .. श्री आलोक कुमार मेहता जी । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-3 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है ।

सामान्यत: यह देखा जा रहा है कि राज्य के कुछ जिलों में (खासकर पटना तथा मगध प्रमंडल के जिले) किसानों द्वारा फसलों के अवशेष विशेषकर धान/गेहूँ के कटनी के उपरान्त फसल अवशेष को खेतों में ही जला दिया जाता है ।

सरकार द्वारा फसल अवशेष को खेतों में न जलाने के लिए राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त के पद रिक्त होने की स्थिति में विकास आयुक्त इस कार्य समूह के अध्यक्ष मनोनीत हैं । इसी प्रकार, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया है ।

कृषि विभाग द्वारा राज्य में प्रकाशित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों में कटाई के उपरान्त फसल अवशेष को न जलाने से संबंधित विज्ञापन कई बार प्रकाशित करवाया गया है । साथ-ही, राज्य में प्रसारित होने वाले विभिन्न

रेडियो चैनल्स के माध्यम से फसल न जलाने से संबंधित रेडियो जिंगल का प्रसारण तथा विभिन्न टी0वी0 चैनल्स के माध्यम से टी0वी0 स्पॉट का प्रसारण करवाया गया है ।

इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारियों को कृषि निदेशक के स्तर से फसल कटाई के उपरान्त उन्हें खेतों में नहीं जलाने के प्रति जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने हेतु निदेशित करने के लिए पत्र दिया गया है ।

कृषि विभाग के व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम यथा- किसान चौपाल, किसान पाठशाला तथा खरीफ महाभियान, 2019 के माध्यम से भी किसानों को फसल अवशेष को न जलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष जलाने के बदले अवशेषों को खेतों में ही प्रबंधन कर उसे खाद के रूप में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नवीनतम कृषि यंत्रें यथा- हैपी सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर पर 80 परसेंट तथा रीपर कंबाइंडर पर 60 परसेंट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है ।

महोदय, हमलोग राज्य के अन्नदाता किसान भाई-बहनों से अपील कर रहे हैं कि खेत की मिट्टी करे पुकार, मत जलाओ लार-पुवार । महोदय, फसलों के अवशेष खुट्टी, पुआल, भूसा आदि को खेतों में न जलाया जाय ।

क्या आप जानते हैं कि खेतों में फसल अवशेष को जलाने से कितना नुकसान होता है ? मिट्टी के तापमान में वृद्धि होती है जिसके कारण मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन नष्ट होते हैं । फलस्वरूप खेत की उर्वरता कम होती है । मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, मित्र कीट, केचुआ आदि मर जाते हैं, जो खेती के लिए जरूरी है । मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं । मिट्टी में नाईट्रोजन की की कमी होती है, जसके कारण फसल उत्पादन घटता है । पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है । ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ।

क्या करें किसान भाई-बहन ? यदि धान की कटाई हार्वेस्टर से की गई हो तो खेतों में फसल के अवशेष को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु स्ट्रॉ बेलर/स्ट्रॉ रीपर मशीन का उपयोग करें । सरकार इसके लिए अनुदान दे

रही है । फसल के अवशेषों को खेतों में जलाने के बदले वर्मी कम्पोस्ट बनाने, मिट्टी में मिलाने, मल्चिंग से खेती आदि का व्यवहार कर मिट्टी को बचायें । हैपी सीडर से गेहूँ की बोआई करें ।

महोदय, हमलोग लगातार यह आग्रह कर रहे हैं - खेत में खुंटी नहीं जलायेंगे, धरती माँ को बचायेंगे । खेत में खुंटी, डंठल नहीं जलाना है । प्रदूषणमुक्त बिहार बनाना है । महोदय, अभियान कृषि विभाग का लगातार चल रहा है गाँव-गाँव में। हम अपील करना चाहेंगे विपक्ष के साथियों से भी कि इस अभियान में आप भी सहयोग करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्या अभियान वे चला रहे हैं, उसके बावजूद खेत में कृषि अवशेषों के जलाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत कमी नहीं आई है । इसको प्रभावी बनाने के जो उपाय हो सकते हैं, वह किया जाना चाहिए । आज इसका सीधा संबंध पर्यावरण से है और पर्यावरण का मतलब कि जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ये सारी चीजें चेन रिलेशन है इसका, श्रृंखला संबंध है इन चीजों का ।

अध्यक्ष : आलोक जी, आपका कोई पूरक प्रश्न या कोई सुझाव हो तो दे दीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : वही सुझाव दे रहा हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन तमाम पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको नियंत्रित करने में, उस क्षेत्र में अन्वेषण करने के लिए क्या कोई अलग से बॉडी बनाई जा रही है या फिर कोई अलग से कानून बिहार के अन्दर बनाने की योजना है?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, जैसा कि सदन को पता है कि 13 तारीख को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सुखाड, बाढ़, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विधान सभा का नया जो सेन्ट्रल हॉल पार्लियामेंट की तर्ज पर बना है, वहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है । सभी सदस्यों से आग्रह होगा कि अपना सुझाव निश्चित तौर पर देंगे और सरकार ने कमिटी बनाई है, अभी हम कानून नहीं बनाये हैं । महोदय, हमारा प्रयास है कि अवेयरनेस के माध्यम से हम किसान भाईयों को जागृत कर रहे हैं, उसमें अपेक्षा है कि आप सब भी सहयोग दें तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम सफल होगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय.....

अध्यक्ष : क्या है ? इसमें अब कुछ है नहीं ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह पर्यावरण से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है और पर्यावरण की महत्ता क्या है, आये दिनों यहाँ बिहार के लोग....

अध्यक्ष : मंत्री जी और सरकार भी मान रही है । आप अपना पूरक या सुझाव दीजिये न ।

श्री आलोक कुमार मेहता : यह जो गैस इवॉल्यूशन का मामला था जिसमें गाड़ियों को चेक करके पर्यावरण से क्लीयरेंस का मामला था । यह सबका सब मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है । सारे नियम-कानून बनाये गये लेकिन इनफोर्समेंट जो होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । आपका जो जागरूकता अभियान है, वह अंतिम पंक्ति तक गया कि नहीं......

अध्यक्ष : आप कृषि विभाग से जुड़ा जो मामला है, आप गाड़ी से गैस इमीशन का विषय जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, यह कहाँ से इसका जवाब देंगे ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं उसका जवाब सरकार से चाहता हूँ....

अध्यक्ष : इसी के लिए न सरकार 13 तारीख को व्यापक सभी विभागों से संबंधित जो पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे हैं, भूगर्भीय जल-स्तर जो लगातार घट रहा है, उसका मुद्दा है या फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, सारे मुद्दों पर समेकित रूप से विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए सभी माननीय सदस्यों के संबंधित क्षेत्रों की जो अलग-अलग किस्म की समस्याएँ इन विषयों से जुड़ी हुई हैं, उसकी समीक्षा के लिए तो भर दिन की गोष्ठी और विमर्श कार्यक्रम है । उसमें आप सभी सुझाव दे सकते हैं ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : इसके बाद इनका पिछला सारा नाकामी खतम हो जायेगा ?

अध्यक्ष : अब इसपर हो गया ।

टर्न-2/आजाद/04.07.2019

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि राज्यस्तर पर प्रधान सचिव और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के निगरानी में कमिटी बना दी गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनके राज्यस्तरीय प्रधान सचिव के स्तर से या जिला स्तरीय जिला पदाधिकारी के स्तर से इसपर कौन सी कार्रवाई हुई और इसपर कोई जॉच वगैरह हुई है या नहीं हुई, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, लगातार बैठक हो रही है और इसके लिए अभियान चल रहा है, गांव-गांव में जा रहे हैं और 13 तारीख को तो इसपर विस्तार से चर्चा होगी ।

अध्यक्ष : अब इसमें कोई दम नहीं हैं । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री ललित कुमार यादव : ललित जी, आप सभी जानते हैं कि यह जागरूकता का प्रश्न है, जो किसान जलाते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किसान पर एफ0आई0आर0 किया जाय । इसमें कार्रवाई से क्या मतलब है, इसमें जागरूकता से ही इसका निदान हो सकता है ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-4(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : महोदय, यह हस्तांतरित है लघु सिंचाई विभाग को ।

अध्यक्ष : यह लघु सिंचाई विभाग को हस्तांतरित है, लघु सिंचाई विभाग का जो दिन नियत होगा, अगली तिथि को उस दिन आयेगा ।

अब तारांकित प्रश्न ।

तारांकित प्रश्न सं0-239(श्रीमती पूनम देवी यादव)

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : चलिए । ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-240(श्री आबिदुर रहमान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद्, अररिया के वार्ड नं0-5 में किशोर श्रीवास्तव के घर से घोपडिया तक की सड़क की कुल लम्बाई 2.8 कि0मी0 है । इसमें से घनी आबादी वाले घोपडिया बस्ती में राज्य योजना के तरफ स 1.2 कि0मी0 पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही कराया जा चुका है । शेष 1.6 कि0मी0 में ईट सोलिंग सड़क पूर्व से ही निर्मित है। इसके आगे 0.36 कि0मी0 सड़क पर पी0सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी है । इसे अगले तीन माह में पूर्ण करा ली जायेगी । अंतिम छोर पर कम आबादी वाले क्षेत्र में 0.74 कि0मी0 सड़क कच्ची है, जिसे निधि की उपलब्धता के आलोक में पक्कीकरण करा दिया जायेगा ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि यह दो स्टेशन को जोड़ती है और सड़क कहीं पर है और कहीं पर नहीं है । किसी तरह से इसको देखवाकर के इसको जल्द करवा दिया जाय ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने तो बोल ही दिया कि इसको करवा दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-241(श्री विजय शंकर दूबे)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-242(श्री ललित कुमार यादव)

श्री मदन सहनी,मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय,महोदय ......

अध्यक्ष : क्या समय नहीं दिया जाय ?

श्री ललित कुमार यादव : समय नहीं महोदय, मेरा भी अधिकार है महोदय, हम महोदय माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये समय कब तक लेंगे ?

अध्यक्ष : अगला जो वर्किंग डे होगा ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : अगले वृहस्पतिवार को ।

श्री ललित यादव : ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0-243(श्री हेम नारायण साह)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगत सड़क निर्माण का प्राक्कलन एवं प्रस्ताव कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज से पत्रांक-125 दिनांक 5.3.2019 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ है । योजना की कुल लागत 2 करोड़ 97 लाख 80 हजार रू0 है । चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वप्रथम योजना के प्राक्कलन पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर राशि की उपलब्धता के आलोक में योजना स्वीकृत कर निर्माण किया जायेगा ।

श्री हेम नारायण साह : महोदय, जब से देश आजाद हुआ, नगर पंचायत में रोड है, दो वार्ड में आज तक रोड बना नहीं है । कुछ जगह ईट सोलिंग है और कुछ कच्ची है .....

अध्यक्ष : श्री हेमनारायण जी, जब देश आजाद हुआ था तब वह नगर पंचायत था ?

श्री हेम नारायण साह : जी, नहीं था ।

अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ, तब से नगर पंचायत में रोड नहीं है ।

श्री हेम नारायण साह : महोदय, जब से नगर पंचायत हो गया तब से नगर पंचायत का सुविधा भी उस वार्ड को मिलना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से आपके आसन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि कब तक बन जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, हमारी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाय।

तारांकित प्रश्न सं0-244(श्रीमती अमिता भूषण)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बस पड़ाव में यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध है । बेगूसराय नगर निगम बोर्ड के निर्णय के आलोक में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले का ......

अध्यक्ष : माईक पर बोलिए अमिता जी ।

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले का का बस पड़ाव जिसकी राजस्व वसूली की रफ्तार तो प्रदेश में सबसे तीव्र है पर सुविधाओं के मामले में सबसे नीचे है । सालाना सवा करोड़ की आमदनी वाले बस पड़ाव में यात्रियों के लिए पर्याप्त शौचालय उपलब्ध नहीं है और जो शौचालय है भी, उसके लिये यात्रियों को भुगतान करना पड़ता है । पानी की आपूर्ति भी वहां ढंग से नहीं है । ट्रैफिक कंट्रोल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बुडको के माध्यम से 4.5 करोड़ रू0 खर्च कर भवन बनाया गया था, जो बारिश में टपकती है और उसको ढंकने के लिए पॉलिथिन का इन्तजाम किया गया है । लाईट वहां जलती नहीं है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि वे इसको देखवा लें, जो भी जवाब आया है, वह सही नहीं है ।

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-245(श्री सुदामा प्रसाद)

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । भोजपुर जिला अन्तर्गत पीरो नगर पंचायत में वर्ष 2003 में 1 करोड़ 85 लाख 92 हजार रू0 की योजना स्वीकृत की गई थी लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि योजना में उच्च प्रदायी नलकूप का डिसचार्ज कम हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है ।

नये उच्च प्रदायी नलकूप का निर्माण कर जलमिनार के माध्यम से योजना को चालू करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पानी तो चला नहीं और ये कह रहे हैं बाधित है । यह तो शुरू हुआ ही नहीं है, इसलिए मेरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री जी कि इसको कब तक शुरू करायेंगे और इसके लिए जो जवाबदेह लोग हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई करेंगे ?

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि वहां जलमिनार का निर्माण हो चुका है लेकिन दो बार बोरिंग फेल होने के बाद, दूसरी बार 2015 में फिर बोरिंग लगाया गया लेकिन जल की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थिति के कारण पर्याप्त मात्रा में वहां जल अप्राप्त है । इसलिए नई तकनीक के आधार पर नया डी0पी0आर0 तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि उच्च प्रदायी नलकूप का निर्माण कराकर उस जलमिनार के माध्यम से लोगों को जल दिया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, वहां पर पानी चला है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅं ?

अध्यक्ष : सुदामा जी, आप मंत्री जी का जवाब सुनिये, वे कह रहे हैं कि हमलोग दो बार बोरिंग कराये हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, प्रोपर लेयर नहीं मिल रहा है इसलिए बोरिंग फेल हो जा रहा है । अब नयी तकनीक से नई बोरिंग कराकर के जलमीनार जो बना है, उसके माध्यम से वह कराने का विचार रखते हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, एक समय सीमा तय कर दिया जाय ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, ...

अध्यक्ष : कहां अशोक जी, आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इसको कब तक पूरा करा देंगे, इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाय सर ।

अध्यक्ष : कुछ बताईए मंत्री जी ।

श्री विनोद नारायण झा,मंत्री : महोदय, इसकी प्रक्रिया चल रही है, हम शीघ्र करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-3/ज्योति/04-07-2019

तारांकित प्रश्न संख्या-246(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : महोदय,1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है । समाहर्ता मुजफ्पुर के पत्रांक 1857 दिनॉक 2-7-2019 के प्रतिवेदनानुसार उक्त अंचल में कुल लंबित वादों की संख्या 5035 है जो विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है ।

3- सभी लंबित आवेदनों को जमाबंदी रजिस्टर -2 एवं औन लाईन जमाबंदी से जॉच की जा रही है । जांचोंपरान्त शीघ्र निष्पादित कर दिया जायेगा। राजस्व कर्मचारी की कमी है । अंचलाधिकारी , मुशहरी से कारण पृच्छा करते हुए तुरत निष्पादन का निर्देश दिया गया है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूॅ कि समय सीमा तय करें कि काफी लोग वहॉ परेशान है ब्लौक का चक्कर लगाते लगाते ।

अध्यक्ष : क्या पूछीं ।

श्रीमती बेबी कुमारी : समय सीमा तय करें कि कबतक निष्पादन किया जायेगा ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या को अपने उत्तर के दौरान यह बताया है कि कर्मचारियों का अभाव है तब भी कारण पृच्छा किया गया है वहॉ के अंचलाधिकारी से और तुरत इस काम को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी ...

अध्यक्ष : मंत्री जी देखवा रहे हैं शीघ्रता से करवा देंगे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी के कार्यालय में नहीं बैठने के कारण इतनी परेशानी हो रही है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करें ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि कर्मचारियों का अभाव है । मेरी बात सुन ली जाय । उसके लिए मैंने उनके बहाली की दिशा में अधियाचना भेजी है हमने लगातार, कल भी जवाब दिया था इन प्रश्नों का तब भी मैंने कहा है कि जल्द से जल्द यह काम पूरा किया जायेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार कर्मचारी कब बहाल करेगी यह तो बतावे ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कर्मचारियों का अभाव है । इस संबंध में मैंने बहाली के संबंध में अधियाचना भेजी है, बहाली की कार्रवाई प्रारम्भ हो गयी है । जब बहाल होकर आयेंगें तो सभी स्थानों पर कर्मचारियों की पदस्थापन कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 247 (श्री विजय शंकर दूबे)--अनुपस्थित

तारांकित प्रश्न संख्या 248 (श्री सत्येदव राम)-

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, मैरवा के पूरे बाजार के जल निकासी एवं अगल बगल के गांव का पानी मुख्य नाले से होकर निकलता है ।

2-आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त नाले के कुछ भाग कच्चा भी है, शेष कच्चे नाले का डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है । राशि की उपलब्धता के आलोक में नाला उड़ाही कर पक्कीकरण योजना पूरा करा दिया जायेगा ।

3-वर्णित खंड 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि कुछ नाले पक्के हैं और कुछ कच्चे हैं तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि राशि की उपलब्धता के आलोक में तो अब यह राशि कब उपलब्ध होगी ?

अध्यक्ष : वही पता नहीं है ।

श्री सत्येदव राम : इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वह राशि कबतक उपलब्ध होगी ?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : राशि उपलब्ध तो जब हमलोगों को मिलने वाला है, मिलेगा तो उससे करवा देंगे ।

श्री सत्येदव राम : कबतक राशि मिलने वाली है ? ये एक टाईम निर्धारित करें ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाईये बहुत देर से आप खड़े हैं ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, इस नाले का निष्पादन कबतक माननीय मंत्री जी करा देंगे ?

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को संरक्षित कीजिये, मंत्री को संरक्षित मत करिये यह परिपाटी अच्छी नहीं है ।

अध्यक्ष: आप भोला जी, बिना परिपाटी समझे परिपाटी का जिक्र क्यों कर रहे हैं ? भोला जी, यहाँ सदन में हम सदस्य को ही संरक्षित करते हैं, नहीं संरक्षित करते तो दूसरे प्रश्न में अनावश्यक आपको मौका कैसे देते ?

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, माननीय मंत्री जी बतावें वे कबतक पूरा करायेंगें , कबतक नाले का कार्य पूरा करा देंगे ?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, इस फायनेन्शियल ईयर में हम उसको करवा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-249 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड में मधेपुर पश्चिम मधेपुर पूर्वी ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा फुलपरास प्रखंड स्थित फुलपरास एवं सिासवा बड़ही ग्रामीण जलापूर्ति योजना आंशिक रुप से चालू है । सभी घरों में नल के साथ जलापूर्ति हेतु कार्रवाई निम्नवत् है ।

1-मधेपुर पश्चिम जलापूर्ति योजना में नल के माध्यम से हर घर में पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 69 लाख 16 हजार 3 सौ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है । संवेदक का चयन कर लिया गया है । एकरारनामा के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

2-मधेपुर पूर्वी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत हर घर नल से जल के माध्यम से पवेय जल उपलब्ध कराने हेतु 69 लाख 85 हजार 7 सौ रुपये की योजना की स्वीकृति कर दी गयी है । कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

3-फुलपरास जलापूर्ति योजना के सभी घरों में नल के माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 55 हजार 470 रुपये की योजना स्वीकृत कर दी गयी है और कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

4- सिसवा बड़ही जलापूर्ति योजना के सभी घरों में नल के माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ 44 लाख 55 हजार की योजना स्वीकृत कर दी गयी है इसके क्रियान्वयन हेतु निविदा निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या 250(श्री महबूब आलम)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । नगर पंचायत, बारसोई में कनीय अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर नगर प्रबंधक एवं कार्यपालक सहायक पदस्थापित हैं । आधारभूत संरचना अंतर्गत नगर सरकार भवन और सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करा दी गयी है और शीघ्र ही इसका काम पूरा कराया जायेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । महोदय, अभी एक कार्यपालक सहायक हैं । अभी जिला कलक्टर ने एक महीना, डेढ़ महीना पहले एक इंजीनियरिंग जे.ई. उनको दिया है लेकिन उसके किरानी उसके सहयोग के लिए और जो कर्मी की जरुरत है इसके अभाव में 5 करोड़ रुपया अन्य मदों में दो साल से पड़े हुए हैं और नगर पंचायत का अस्तित्व में आए हुए तीन साल चले गए लेकिन एक भी काम शुरू नहीं हुआ क्या मंत्री जी जवाब देंगे ?

टर्न-4/04.7.2019/बिपिन

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: महोदय, इसी के लिए हमलोग पद जो रिक्त है, उसपर भी स्टाफ को दे रहे हैं और काम शीघ्र करा देने की बात हमने कही है और वह काम पूरा कराया जाएगा ।

श्री महबूब आलम : पत्र लिखने से नहीं न होगा महोदय । ये कर्मी कब उपलब्ध करा रहे हैं, समय-सीमा तय करें । तीन साल हो गया महोदय । महोदय, विकास का रूपया खर्च नहीं हो पा रहा है । तीन साल से पड़ा हुआ है महोदय ।

अध्यक्ष : उसको मंत्री जी देख लीजिए और एप्रूव करा दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं.-251 (डॉ0 विनोद प्रसाद यादव)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत शेरघाटी स्थित बस पड़ाव में एक डीलक्स शौचालय-सह-स्नानागार नवनिर्मित है । पुराने शौचालय के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

3. नगर निकाय से प्रस्ताव होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर आधुनिक सुविधायुक्त बस पड़ाव निर्माण योजना ली जाएगी ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सभी प्रश्नों का स्वीकारात्मक उत्तर दिए हैं लेकिन जो मेरे प्रश्न में था कि वहां पर बस पड़ाव में जो भवन है, जर्जर है, और उसमें यात्री को ठहरने में असुविधा है और एन.एच.-2 से होकर कलकत्ता, रांची, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बसें चलती हैं महोदय और चूँकि एन.एच.-2 पर होने के कारण शेरघाटी बस पड़ाव का जो नगर पंचायत शेरघाटी के अंतर्गत आता है, काफी महत्वपूर्ण है । यात्रियों को रात्रि में काफी कठिनाई होती है महोदय । तो मैं माननीय

मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए क्या शेरघाटी नगर पंचायत स्थित बस पड़ाव में अत्याधुनिक सुविधा वाला बस पड़ाव बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: महोदय, मैंने कहा है कि निधि की उपलब्धता पर इसपर विचार करके कराया जाएगा ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: महोदय, निधि की उपलब्धता, चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने-जाने में जो वहां पर असुविधा हो रही है....

अध्यक्ष : इसलिए मंत्री जी देखेंगे, निधि की व्यवस्था करेंगे ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: निधि की उपलब्धता तो निरंतर हो, महोदय, इसमें कोई समय-सीमा माननीय मंत्री महोदय बताएं कि कब तक इसको निर्माण करा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष : इसको शीघ्र दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं.-252 (श्री गुलाब यादव)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । पूरे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आच्छादित पात्र परिवारों को अन्त्योदय एवं प्रविक्ता प्राप्त राशन कार्ड प्रचलन में है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमंडल में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31,373 एवं अद्यतन 9144 कुल 40,517 आवेदन पत्र नया राशन कार्ड निर्गमन, प्रत्यर्पण एवं विद्यमान राशन कार्ड में संशोधन हेतु आर.टी.पी.एस. काउन्टर के माध्यम से प्राप्त किया गया । अभी तक कुल 3294 पात्र परिवारों को राशन कार्ड मुहैय्या कराया गया है । प्राप्त आवेदनों के जांच के क्रम में पाया गया कि कई ऐसे भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो कि एच.एच. कार्डधारी परिवार के सदस्य हैं तथा परिवार विखंडन हेतु आवेदन दिया है एवं कई ऐसे आवेदन भी हैं जिन्हें पूर्व में राशनकार्ड निर्गत है परंतु पूर्व से निर्गत राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्य द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है जिसके कारण 14,250 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा शेष बचे 22,973 आवेदन पत्रों की जांच की कार्रवाई पूर्ण होने पर पात्र परिवारों को नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा ।

श्री गुलाब यादव: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीब आदमी को कार्ड मिला नहीं है, न उनको कोई फैसिलिटी मिलता है । गरीब बच्चे मर जाते हैं भूखे, तो उस राशन कार्ड में कोई सुविधा नहीं है । मंत्री जी कब तक पूरा कम्प्लीट करा देंगे । कहते हैं आवेदन इतना अभी तक प्राप्त हुआ है । कब

तक ? समय-सीमा तय करें कि कब तक राशन कार्ड हमारे यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : जांच चल रहा है । जल्द ही राशन कार्ड वितरण करवा देंगे ।

श्री गुलाब यादव : समय-सीमा तय कर दीजिए मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: एक से डेढ महीना के अंदर दिलवा देंगे ।

श्री गुलाब यादव : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं.-253 (श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि टाटा इंडिकॉम मोबाइल टावर मौजा टिकारी के सर्वे वार्ड सं0 7 के खाता संख्या 122 खेसरा सं0 67(घ) नया रकबा 105 और जो सर्वे खतिहान में है, में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, पिता राम प्रसाद सिन्हा, उसैक कुमारी सिन्हा, पति राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा के नाम पर दर्ज है, पर अवस्थित है । प्रश्नगत भूमि का नया सर्वे खतिहान का अंतिम प्रकाशन हो चुका है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । अंचल अधिकारी, टिकारी ने पत्रांक 66 दिनांक 18.2.2008 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि से निर्माणाधीन टावर को हटाने का नोटिस किया था तथा नया सर्वे में रैयती भूमि होने के कारण अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त भूमि के खतिहान में रैयती खाता खुलने के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में स्वत: वाद सं0 565/2008 दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

3- उपरोक्त खंड-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, खंड-2, 2008 में अंचलाधिकारी, टिकारी के द्वारा उक्त टावर को 48 घंटे में हटाने का नोटिस दिया गया था लेकिन भू-माफियाओं के द्वारा चूंकि यह जमीन नगर पंचायत की जमीन है और ये राजेन्द्र प्रसाद जिनका नाम बता रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जी, ये नया सर्वे में अपना खतिहान खोलवा लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि नया खतिहान सरकारी जमीन का किसी व्यक्ति के नाम पर जिस भी पदाधिकारी ने खोलाने का काम किया है, क्या उसके विरूद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत भूमि का नया सर्वे खतिहान का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और खतिहान में रैयती खाता खुलने के विरूद्ध सक्षम न्यायालय ने स्वत: वाद संख्या 565/2008 दायर किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

उपरोक्त खंड-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि नगर पंचायत, टिकारी इस जमीन के विरूद्ध टाइटल में भी जाने का प्रस्ताव वहां पर पारित हुआ है । जब नगर पंचायत टिकारी टाइटल में जा रही है तो निश्चित तौर पर यहां पर भू-माफियाओं के द्वारा इसमें किसी प्रकार का नया सर्वे कराने के लिए कोई-न-कोई उपाय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच जो नया सर्वे जिसके नाम से किया गया है, उस पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं ?

अध्यक्ष : अभी तो साबित हुआ नहीं कि गड़बड़ी हुई है, तो कार्रवाई कहां से होगी।

तारांकित प्रश्न सं.-254 (श्री उपेन्द्र पासवान)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, बेगुसराय के पत्रांक 851 राजस्व दिनांक 01.7.2019 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बेगुसराय जिलान्तर्गत नावकोठी, प्रखंड, बखरी प्रखंड, गढ़पूरा प्रखंड एवं डंडारी प्रखंड के अंचल में निमित्त अमीन पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में दूसरे अंचल से आवश्यकतानुसार अमीन की प्रतिनियुक्ति कर कार्यों को निष्पादित कराया जाता है ।

टर्न : 05/कृष्ण/04.07.2019

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : 3. सभी जिलों में अमीन के कुल स्वीकृत पद 1881 के विरूद्ध पद रिक्त रहने के कारण अमीन के कुल 1522 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 9.08.2017, पत्रांक 348 दिनांक 10.04.2018 द्वारा अधियाचाना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् को भेजी गयी है। प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजन शीघ्र कराने हेतु विभाग एवं राजस्व पर्षद् के बीच समन्वयन स्थापित कर उच्च स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् से अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र कर ली जायेगी ।

श्री उपेन्द्र पासवान : अध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल के सभी प्रखंड गढ़पुरा, नावकोठी, बखरी सभी अनुकम्पा पर चल रहे हैं । पिछले सत्र में ही हमने

डी0सी0एल0आर0 से संबंधित मुद्दे उठाये थे और माननीय मंत्री आश्वासन दिये थे कि बहुत जल्द डी0सी0एल0आर0 के पद पर प्रतिनियुक्ति कर दिया जायेगा । लेकिन वहां दो सवा दो वर्षों से आज तक डी0सी0एल0आर0 का पद रिक्त है । कार्यपाालक दंडाधिकारी का पद रिक्त है ।

अध्यक्ष : आप अंचल और अमीन का प्रश्न करके डी0सी0एल0आर0की पोस्टिंग कराना चाहते हैं ?

श्री उपेन्द्र पासवान : महोदय, एम0ओ0 का भी पद रिक्त है । सभी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप जो प्रश्न किये हैं उस पर न आईये । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य इसमें आप की मजबूरी को समझते हुये अमीन की नियुक्ति और अमीन का पदस्थापन छोड़कर कहे हैं प्रश्न में कि कुछ दिनों के लिये प्रतिनियुक्ति कर दीजिये ताकि कुछ काम निकल जाय । ठीक है न ? यही आप का प्रश्न है तो आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री उपेन्द्र पासवान : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अंचल अमीन को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी को मदद करने के लिये यही आप प्रश्न में पूछे है कि प्रतिनियुक्ति कर दिया जाय । आप न पदस्थापन मांग रहे हैं, न नियुक्ति मांग रहे हैं । प्रतिनियुक्ति मांग रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री शक्ति सिंह यादव : सदन में दो तरह का उत्तर दे रहे हैं । कहा कि अधियाचना भेजा हूं और वह प्रक्रिया शुरू हो गयी है । अभी अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है, उसमें विभाग से मिल करके काम करेगा तो दो तरह की बात आयी सदन में। सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद मेरे उत्तर को गंभीरतापूर्वक सुनने का कष्ट नहीं करते हैं । अगर उत्तर समझ में आता तो ऐसी बात नहीं करते ।

अध्यक्ष : बैठिये । आप वरिष्ठ मानते हैं तो कैसे दो तरह से बोलेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 255(श्री सदानन्द सिंह)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ के पत्रांक 896 दिनांक 2.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बबलू कुमार गुप्ता के घर से दीप साह गुप्ता के घर तक नाली निर्माण योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कार्य के विरूद्ध 4 लाख 17 हजार 347 रूपये का भुगतान किया गया है ।

2. अस्वीकारात्मक है । उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

3. अखबार में प्रकाशित समाचार के आलोक में इसकी विभागीय जांच कराकर प्रतिवेदन से सदन को इसी सत्र में अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, सिर्फ एक पूरक प्रश्न पूछता हूं । क्या माननीय मंत्री इसकी जांच प्रमंडलीय आयुक्त से करा लेंगे और जांच कराकर जो आपने आश्वस्त किया है उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे ? महोदय, इसमें सूचना के अधिकार के तहत भी सूचना मांगी गयी है और उसमें संपुष्टि हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । आपने भी कहा है कि जांच करायेंगे । माननीय सदस्य एक वरीय अधिकारी से जांच कराने को कह रहे हैं तो आप जांच करा दीजिये ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, जांच करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 256 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : 1.अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समहाहर्त्ता, सीवान के प्रतिवेदनानुसार भू-हदबंदी अन्तर्गत अर्जित भूमि गोरियाकोठी सह छितौनी खाता नंबर-8 से 7 बंदोबस्त पदाधिकारियों को दिनांक 23.07.1976 को वाद संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7/1976-77 के तहत कुल रकबा 3 एकड़ 96 डिसमिल का भूमि हदबंदी बंदोबस्त पर्चा दिया गया है। भू-हदबंदी अंतर्गत प्रश्नगत भूमि के अर्जन के विरूद्ध राजस्व पर्षद, बिहार में दायर वाद संख्या-900/1976 के द्वारा दिनांक 13.07.1976 आदेश पारित किया गया है । याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर वाद के अन्तर्गत न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सीवान द्वारा उक्त भूमि/भूखंड को दिनांक 28.12.1985 को अधिसेस भूमि से विमुक्त कर दिया गया ।

अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि/भूखंड जो भूमि हदबंदी अधिशेष भूमि से विमुक्त हो चुकी है । इस पर वितरित पर्चा के पर्चाधारियों को दखल-कब्जा दिलाना विधि-सम्मत नहीं है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बंदोबस्ती पर्चा 1975-76 की है और उस समय के भारत सरकार के कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम जी अपने हाथ से गोरियाकोठी में दिया था तो क्या उस समय के अंचलाधिकारी, डी0सी0एल0आर0 और ए0डी0एम0 सब पागल थे कि उन्होंने जो बंदोबस्ती पर्चा बनाकर दिया, उसमें हमारे भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जगजीवन बाबू ने दिया और 43 वर्ष बीत गये, आज तक दखल-कब्जा नहीं कराया गया । इन्होंने कहा कि 1985 में एक घोषणा किया गया कि भू-हदबंदी में नहीं आता है तो उस समय जो सर्वे हुआ था, उस समय क्या भू-हदबंदी नहीं देखा गया था । महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार, जो 1975-76 में जो बंदोबस्ती पर्चा दिया गया, वह दलितों को दी गयी थी तो क्या सरकार दखल-कब्जा दिलाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : सरकार ने जो कहा उसको आपने ध्यान से नहीं सुना । उन्होंने कहा कि जिस जमीन को सरप्लस घोषित करके सीलिंग से बांटा गया था, वह आदेश निरस्त हो गया है और वह जमीन अब सरप्लस श्रेणी में नहीं है । इसलिए अब उस पर कब्जा दिलाना संभव नहीं है । इसके आलोक में आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरप्लस जमीन मानकर सीलिंग से जो पर्चा दिया गया था और उसको निरस्त कर दिया गया, किस के द्वारा यह फैसला दिया गया है, क्या फैसला की कॉपी उपलब्ध करा सकते हैं ?

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1976-77 के तहत कुल रकबा 3 एकड़ 88 डिसमिल का भू-हदबंदी बंदोबस्त पर्चा दिया गया था । भू-हदबंदी के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि के अर्जन के विरूद्ध राजस्व पर्षद, बिहार में दायर वाद संख्या-900/76 द्वारा दिनांक 13.07.1076 को स्थगन का आदेश पारित किया गया । याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर वाद के अन्तर्गत न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, सीवान ने उक्त भूमि/भूखंड को दिनांक 128.12.85 को अधिसेस भूमि से विमुक्त कर दिया गया ।

अत: उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत भूमि/भूखंड जो भू-हदबंदी अधिसेस भूमि से विमुक्त हो चुका है, पर वितरित पर्चा के पर्चाधारियों को दखल-कब्जा दिलाना अब विधि-सम्मत् नहीं है ।

श्री सत्येदव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 2018 में मालिक के द्वारा दायर अपील में अपर समाहर्त्ता,सीवान के न्यायालय से रद्द कर दिया गया ? क्या बंदोबस्त पर्चाधारियों का जमाबंदी आज तक कायम है ? अगर कायम है तो हदबंदी से वह जमीन कैसे अलग हो गया ? इसे स्पष्ट किया जाये कि किस नियम के तहत जब कि आज भी जमाबंदी उसके नाम से कायम है और जो अपील दायर किया गया था, ए0डी0एम0 के यहां, 2018 में ए0डी0एम0 ने रद्द कर दिया है, ए0डी0एम0 को कोई अधिकार नहीं है कि जमाबंदी को रद्द कर सके । आप पुन: जवाब दें कि क्या 2018 में मालिक के अपील को रद्द किया गया है और अगर रद्द किया गया है तो आप गरीबों के पक्ष में कौन-सी कार्रवाई करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उस आलोक में इसकी फिर से जांच करा दीजिये ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : जी अच्छा ।

टर्न-6/अंजनी/दि0 04.07.19

तारांकित प्रश्न सं0-257(श्री कुमार सर्वजीत)

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्षों में अल्प वर्षापात के कारण 25 पेयजल समस्याग्रस्त जिलों के भूजल स्तर के नियमित मोनेटरिंग की जा रही है । भूजल स्तर के गिरावट के कारण इन जिलों में पेय जल की समस्या से निपटने हेतु इंडिया मार्क-टू, थ्री, चापाकलों में राइजर पाईप बढ़ाने, साधारण चापाकल को विशेष चापाकलों में बदलने तथा चापाकलों की मरम्मती का कार्य सतत् रूप से करायी जा रही है । इसके अतिरिक्त सभी समस्याग्रस्त जिलों में आवश्यकतानुसार टैंकर से भी जलापूर्त्ति की जा रही है । प्रभावित जिलों में नये चापाकलों का निर्माण कार्य भी कराया जाता है । मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल-जल योजना के तहत विभाग द्वारा जहानाबाद के 28 वार्ड, औरंगाबाद के 78 वार्ड, नवादा के 113 वार्ड, सासाराम के 132 वार्ड, भोजपुर के 96 वार्ड, कैमूर के 92 वार्ड

तथा बक्सर के 73 वार्ड में निविदा कराकर विभाग द्वारा जलापूर्त्ति के लिए निविदा की कार्रवाई करायी जा रही है । शेष वार्डों में पंचायती राज विभाग और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग द्वारा पेय जल का कार्य कराया जा रहा है । मार्च, 2020 तक सभी घरों में नल से जल द्वारा पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि जो इतने जिला हैं, उतने जिलों में जो गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है पानी का तो क्या माननीय मंत्री महोदय जो इनको विभाग के बजट में पैसा मिला है और वह पूरा पहाड़ी इलाका है, उसमें से क्या अलग से इन जिलों में बड़े पैमाने पर पेय जल की व्यवस्था कराना चाहते हैं कि नहीं ? दूसरा जो इन्होंने कहा कि नल जल योजना में पंचायतों में जो टेंडर हुआ है विभाग के द्वारा, उस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि चूंकि हम गया से आते हैं, गया का इन्होंने नहीं बताया कि कितना वहां पर नल जल योजना शुरू कराया है, तो विभाग के द्वारा जितने नल जल योजना का टेंडर हुआ है, उसमें ये कबतक शुरू करा देंगे और अपने बजट के पैसे से इन इतने जिलों में अलग से पैसा देकर पेय जल समस्या को दूर करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : इसको शीघ्र करा दीजिए ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर का भी इसमें जिक्र आया है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, हमलोग गया जिला से आते हैं और गया जिला झारखंड का सीमावर्ती जिला है और हमलोगों के विधान सभा के सटे ही पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है । अभी पूरे क्षेत्र में पीने के पानी का पूरा घनघोर संकट है । महोदय, जहां-तहां मंत्री महोदय का टैंकर से भी व्यवस्था किया गया है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि गया जिला के शेरघाटी विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी, बोध गया इन सब इलाकों में, दर्जनों गांवों में टैंकर से पानी दिया जा रहा है, कोई स्थायी समाधान नहीं है । चूंकि प्रत्येक वर्ष जब गर्मी का मौसम आता है, इस साल तो सुखाड़ है, सुखाड़ के बिना भी जब गर्मी का मौसम आता है..........

अध्यक्ष : आप जल्दी पूछिए न ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,कोई स्थायी समाधान उसके लिए क्या करना चाहते हैं?

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, आजतक चापाकल नहीं गड़ा है । माननीय मंत्री जी से हम हमेशा मिलने का काम किये, बताने का काम किये कि मेरे यहां चापाकल नहीं गाड़ा गया है विधायक निधि के फंड से । मैं माननीय मंत्री जी से तीन बार मिला, इनके सचिव से भी मैंने मिलने का काम किया लेकिन 2014-15 और 2015-16 का जो विधायक को अनुशंसा करना था चापाकल का, मेरे अनुशंसा देने के बाद भी

नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यकाल का चार साल समाप्त होने जा रहा है अभीतक 2014-15, 2015-16 का चापाकल नहीं गाड़ा गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अवधेश जी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बतायें कि क्यों नहीं चापाकल गाड़ा गया?

अध्यक्ष : आपकी सूचना ग्रहण कर ली गयी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे गया जिला में.....

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए, सब लोग गया जिला के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से पानी का लेयर भाग रहा है, तीन जिले में जहां लेयर 15 से 20 फीट भागा है, डीप बोरिंग कराकर उन ग्रामीण दलितों को आप पानी मुहैया कराने का कोई नया फार्मुला बनाये हैं या आप उसपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कृपया सदन को बता दीजिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो बताये हैं कि नया मेथड राइजर वाला लगाकर करा रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-258(श्री ललित कुमार यादव)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने के लिए आवागमन के कम में एन0एच0-57 और रेलवे लाईन पार जाना पड़ता है जो डेढ़ किलोमीटर के अन्दर ही है । परन्तु दुर्घटना के संबंध में अबतक कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में ब्रहमपुरा, भटपुरा पंचायत की जनसंख्या 8709 है । सामान्यत: 1900 की जनसंख्या पर एक जनवितरण प्रणाली विक्रेता के नियुक्ति के प्रावधान के आलोक में इस पंचायत मे कुल चार जनवितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत हैं । उपभोक्ताओं के निवासस्थान से दूरी के आधार पर इन जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के बीच अनुपातिक जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र आवंटित है । मानक जनसंख्या नहीं रहने के कारण भटपुरा में जनवितरण प्रणाली की दूकान स्थापित नहीं की गयी है । रेलवे लाईन एवं एन0एच0-57 के पार के उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु उसी तरफ संबंधित एक जनवितरण प्रणाली विक्रेता के व्यापारस्थल स्थापित कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निदेशित किया गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की गंभीरता को देखिए । ये फोर लेन और रेलवे लाईन, इसको माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और वहां पर दो व्यक्ति की दुर्घटना हो गयी है और उस गांव की आबादी पांच हजार है । आपको 19.6.2017 को आवेदन भी दिया था, वैंकेसी भी निकली थी, उस गांव के आवेदक का नहीं करके दूसरे गांव के जिस गांव में तीन डीलर पहले से हैं तो यदि सरकार गंभीर है, संवेदनशील है तो समय-सीमा एक सप्ताह या एक महीना के अन्दर उसी गांव के संतोष शर्मा का जो लंबित आवेदन है, उसको निष्पादित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने बताया कि वहां पंचायत की आबादी 8700 है तो एक गांव की आबादी पांच हजार कैसे हो सकती है । एक भटपुरा में....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिस गांव की बात है, वहां नहीं है और उसके एक एप्लिकेंट भी हैं । उसका मामला देखवा लीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : वह तो हम देखवा लेंगे । महोदय, मैंने तो वहां पर व्यवस्था भी कर दिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, दो व्यक्ति की मौत हो गयी है रेलवे लाईन और फोर लेन क्रोस करने के दौरान और आप कह रहे हैं कि देखवा लीजिए । आसन से निदेश होना चाहिए ।

अध्यक्ष : क्या कहें कि नहीं देखवाइए ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन से निदेश होना चाहिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, हमने तो वहां पर व्यवस्था भी कर दिया है ।

अध्यक्ष : आपके हित में कह रहे हैं कि इसको देखवाने के लिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, 19.6.2017 से संतोष शर्मा का आवेदन लंबित है, आसन से इस संबंध में निदेश होना चाहिए ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम चाहते हैं कि 19.6.2017 से आवेदन जो लंबित है और माननीय मंत्री यह बतला रहे हैं कि 8700 उस पंचायत की आबादी है, मैं इनके जवाब को चुनौती देता हूँ, अभी उस पंचायत की 11,000 आबादी है, वर्तमान में जो इनका सर्वे रिपोर्ट आया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-259 । माननीय मंत्री, आप कुछ बता रहे हैं ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि लोगों को रेलवे लाईन और एन0एच0 नहीं पार करना पड़े तो उस गांव में हमने व्यवस्था कर दिया है और हमने अनुमंडल पदाधिकारी को कह दिया है कि वहां के लोगों को दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े, इतना व्यवस्था हमलोगों ने कर दिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आवेदन लंबित है, उसका भी मैंने जिक्र किया है....

श्री मदन सहनी, मंत्री : वहां पर तो बहाली की प्रकिया पूरी हो चुकी है ।

अध्यक्ष : अब आ गये न, यही बात हम पहले कहे थे कि आवेदन लंबित है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप तो सरकार को संरक्षित कर रहे हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, आवेदन जो लंबित है, उसको करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : असल में हम वही बात कहे न, तब ललित जी कहे कि आप यह क्या कह रहे हैं तो उस बात को हम छोड़ दिये ।

अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, आपने मुझे पुकारा है।

अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया ।

मो0 आफाक आलम : महोदय, इस प्रश्न को पुट कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : चलिए, तो यह पुट हो गया ।

अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । कार्यस्थगन प्रस्ताव ।

टर्न-7/राजेश/4.7.19

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 04 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री राजेश कुमार, श्री सदानंद सिंह, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री ललित कुमार यादव, श्री भाई वीरेन्द्र, श्री सुदामा प्रसाद एवं श्री सत्यदेव राम । आज दिनांक- 04 जुलाई, 2019 को सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

मा0 सदस्य श्री राजेश कुमार, आपको नहीं बोलना है क्या ? पहला मूवर वे हैं । श्री अवधेश कुमार सिंह बोलिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह कोई सरकार के पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है । आज पूरे राज्य की जो स्थिति है सुखाड़ और जल स्तर जो नीचे गिर गया है, उसमें सत्ता पक्ष के यहां नहीं गिरा है, विपक्ष के यहां गिरा है, ऐसी बात नहीं है, यह दोनों तरफ की समस्या सामान है । इसपर आपने अपना पहला नियमन में बोले हैं कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक बैठक बुलाये है, मगर अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी का इस राज्य में सबसे बड़ा ओहदा है, जिसका हमलोग सब सम्मान करते हैं । मगर इस प्रश्न पर सदन में आसन को मुखातिब करना चाहते हैं कि नियमन, वाद-विवाद, मतदान में कार्य स्थगन प्रस्ताव को रद्द किया जाता है, मगर अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है । आपने चमकी बुखार पर आपका जो पावर था, आपने यूज किया,इसलिए इसमें भी आप अपने पावर को यूज करते हुए सदन में ....(व्यवधान)

अध्यक्षः हमने इसी पावर का यूज करते हुए इसे अमान्य कर दिया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः वाह यह तो पावर नहीं हुआ । यह तो मिसयूज ऑफ पावर हुआ ।

अध्यक्षः चलिये । अब शून्यकाल ।

श्री ललित कुमार यादवः आज इतना बड़ा जल संकट है,आपने कार्य स्थगन को अमान्य कर दिया ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, यह तो पूरे प्रदेश का मामला है यह कोई पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है।

अध्यक्ष: आप सही कह रहे हैं लेकिन बैठ जाईये । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

शून्यकाल

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार । आप अपने शून्यकाल को पढ़िये । अगर आप नहीं पढ़ियेगा, तो हम आगे बढ़ जायेंगे ।

(मा0 सदस्य द्वारा शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अमीत कुमार ।

श्री अमीत कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी बैरगनिया प्रखंड के बेगाही में करूर्णाकर चौधरी की अपराधियों द्वारा 27.01.2019 को हत्या कर दी गयी, लेकिन स्व0 चौधरी के हत्यारों की गिरफ्तारी आजतक नहीं हो सकी है, जो प्रशासन की विफलता है । स्व0 चौधरी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कर मुआवजा का भुगतान किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ0 विनोद प्रसाद यादव ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के चिताबकला पंचायत का गलत प्रतिवेदन के कारण किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा धान के फसल का बीमा की राशि नहीं दिया गया है, जबकि सुखाड़ राहत का मुआवजा दिया गया है ।

जॉच कराकर किसानों को धान का फसल बीमा राशि दिलाने की मॉग करता हूॅं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ0 मो0 नवाज आलम ।

(मा0 सदस्य द्वारा शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम-प्रखण्ड के कसेरूआं में कैमूर पहाड़ी से आनेवाली गीताघाट आश्रम के पास गदहिया नदी में चेकडैम नहीं रहने से 2500 एकड़ कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाता है ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त नदी पर चेकडैम निर्माण बनावें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/4-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	60 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 36,52,30,15,000/-(छतीस अरब, बावन करोड़, तीस लाख, पन्द्रह हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं एवं

जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय ।''

महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से चाहूंगा कि भोला यादव जी बोलें ।

अध्यक्षः भोला यादव जी बोलिये।

श्री भोला यादवः अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे कि किसान और आम आवाम का जुड़ाव है । इस विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट का साईज बढ़ाया तो लगा जो बड़ी बड़ी काम होने वाली है, बड़ा प्रस्ताव आया है, बड़ी बड़ी योजनाएं ली जायेगी । ये बजट का साईज तो बढ़ा लेकिन ये ढाक के तीन पात पर कहावत को चरितार्थ किया है । इस विभाग में सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट हो गया है ,बजट को पान के पत्ते की तरह छिरिया दिया गया है और पूरा बजट का पैसा लूट खसोट में ही चला गया । ये लोग कभी कहते हैं कि बांध को चूहा तोड़ दिया तो कभी ये बालू भरे बोरे से बोल्डर पीचिंग करते हैं । महोदय ये विभाग को दो भागों में बांटा है महोदय, एक है बाढ़ प्रक्षेत्र और दूसरा है सिंचाई प्रक्षेत्र । मैं बताना चाहता हूॅं, बाढ़ प्रक्षेत्र में इनका मुख्य काम है तटबंधों की मरम्मत और इनका जो तटबंधों के मरम्मत के नाम पर प्रत्येक वर्ष जो बजट बनता है, यदि एक-एक बांध के बजट को देखा जाय और तीन वर्ष का यदि उस मरम्मत मद के खर्च को जोड़ दिया जाय तो उससे एक नया बांध बन जायेगा, उसके पैरलर एक बांध बन जायेगा लेकिन दुर्भाग्य है उसी बांध को सालों साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों करोड़ रू0 डकार रहे हैं । यह विभाग के और ठीकेदार के बीच जो मिलीभगत है उसका परिणति है महोदय । मैं बताना चाहता हूॅं पिछले बार जो बाढ़ आयी थी इसमें ये लोग चूहे को दोष दिये थे कि चूहा ने बांध को कुतर दिया जिसके कारण बांध टूट गया । मैं उस चूहे को दोष नहीं देना चाहता हूॅं, ये सब कहीं न कहीं भूलावे वाली बात है, रियल में चूहा जो है इसकी जांच होनी चाहिए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन के धर्म को पालन करते हुए लगता है इसके जांच से डरते हैं और इसकी जांच नहीं कराना चाहते हैं । महोदय, यदि

जांच हो जाय तो असली चूहा सामने आ जायेगा महोदय । हम चाहेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मिथिलांचल के एक सुलझे हुए व्यक्ति सिंचाई विभाग का प्रभार लिये हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूॅ और उनसे आग्रह करना चाहता हूॅ कि आप नये रीति रिवाज से इस विभाग को चलाईए । आपके अन्दर वह गुणवत्ता है जो आप तरीके से चला सकते हैं लेकिन यदि दवाब में काम कीजियेगा, पिछली परिपार्टी पर काम कीजियेगा तो आपका भी वही हाल होगा जो आपसे पूर्व मंत्री पर इल्जाम लगता था कि बोल्डर पीचिंग के नाम पर बालू बोरा में भरकर बोल्डर पीचिंग का बिल भंजाते हैं । आपके विभाग में यह बहुत बड़ी कमी है, हमलोगों का भी शासनकाल था उस समय में भी बोल्डर पीचिंग होता था और उस समय जिन नदियों के किनारे बोल्डर पीचिंग हुआ, वह नदी अभी भी नदी के कटाव के कागार पर नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूॅ जो आपके विभाग में बोल्डर पीचिंग के नाम पर बालू प्लास्टिक के बारे में भरा जाता है और उसको भर कर के बिल बनाया जाता है बोल्डर पीचिंग का और तीन महीना के अन्दर वह वोरा सड़ कर के बालू फिर नदी में विलीन हो जाता है, इस चीज को नोट कीजिये औॅर जांच कराई। यदि आपके पास उतना पत्थर नहीं है जिससे कि आप बोल्डर पीचिंग कर सकते तो आप ईंट का कैरेट बनाईए और लोहे की जाली में ईंट का कैरेज बनाईए । अध्यक्ष महोदय भी लम्बे समय तक सिंचाई मंत्री रहे हैं, इसका अनुभव उन्हें प्राप्त है, हो सके तो इनसे परामर्श कीजिये और परामर्श लेकर के जिस खर्च में बोरा में बालू भरते हैं उसी खर्च में आप ईंट भर के लोहे के कैरेट में दीजियेगा तो वह वषों वर्षो तक चलेगा और उसको दखने की जरूरत नहीं पड़ेगी । महोदय, मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूॅ आपको, आपकी जितनी भी बांधे हैं दो तरह की बांध है एक लम्बी बांध है और जिसकी चौड़ाई काफी अधिक है और एक छोटी बांध है जिसकी चौड़ाई काफी कम है तो जो छोटी बांध है उस बांध को ग्रामीण कार्य विभाग को दे दीजिये और जो बड़ी बांध हैं उसको आप पथ निर्माण विभाग को दे दीजिये, वह विभाग उस पर सड़क बना देगा यह लोकोपयोगी कार्य होगा इससे लोगों को चलने का भी सहुलियत होगा और चूहा का जो बहाना है वह खत्म हो जायेगा । आपके इंजीनियर लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे चूंकि उनको लूट का रास्ता बंद हो जायेगा । मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूॅ, आपके विभाग को इसके लिए धन्यवाद देता हूॅ । हमने लिखा था एक भरौल से रतनोपट्टी सड़क है, उसको आपने ग्रामीण कार्य विभाग को दिया,

ग्रामीण कार्य विभाग से कार्य स्वीकृत भी हो गया, ग्रामीण कार्य मंत्री यहां हैं उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूॅं । आपके विभाग से आ गया और ग्रामीण कार्य विभाग में स्वीकृत भी हो गया और उसका शिलान्यस भी मेरे द्वारा करवा दिया गया लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पड़ोस के जो विधायक जी हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनको कहीं कहीं पेट में दर्द हुआ, वे माननीय मंत्री जी से मिलकर उस काम को रोकवा दिये जांच के नाम पर, यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है । जब आप कार्य योजना में इसे शामिल किये, टेंडर निकाले, सब चीज हो गया तो किसी कहने पर यदि इस तरह का काम करते हैं तो इससे घिनौना काम और कुछ नहीं हो सकता है, इसकी जितनी निंदा की जाय वह कम है । (क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/04.07.2019

...क्रमशः...

श्री भोला यादव : यह राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह जनता का काम है । वहाॅं की जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है ।

महोदय, मैं अगली बात कहना चाहता हूॅं, आपका दूसरा काम है नदी के कटाव को रोकना । उसमें कटाव को रोकने के लिए आप बंडाल निर्माण का भी काम कराते हैं । आप वर्षा शुरू होने से पहले बंडाल का निर्माण कराइये। आपके विभाग में एक बहुत बड़ी परिपाटी चली है, हमने विभाग में क्वेश्चन भी किया है, क्वेश्चन का जवाब क्या आता है जानते हैं ? महोदय, क्वेश्चन का जवाब आता है कि जब बाढ़ आयेगी, कटाव होगा तो रोधात्मक कार्रवाई की जायेगी, यह क्वेश्चन का जवाब आता है। दुर्भाग्य है । जब हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास सब कुछ है, बजट है तो हम उसका पहले तैयारी क्यों नहीं करें ? जो काम 100 रू0 में होगा, बाढ़ आने पर उसी काम का 500 रू0 भुगतान होता है, पैसे का अपव्यय है । मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूॅं महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूॅं । महोदय, एक नेयाम गाॅंव है हमारे विधान सभा क्षेत्र में...... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहाॅं बातचीत में लग गये ?

श्री भोला यादव : माननीय मंत्री जी, उसी 15 साल की उपज हैं कि आप मंत्री हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, यह जल संसाधन विभाग की माॅंग का दिन है, आप ग्रामीण कार्य की बात बैठे-बैठे न करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं यह बता रहा था कि उस गॉव की स्थिति यह है कि उस गॉव में नदी की धारा इस तरह से मोड़ ले ली है जो किसी भी दिन वह गॉव नदी की धारा में विलीन हो जायेगा । मैं इस संबंध में हरेक विधान सभा सत्र में कहीं न कहीं निवेदन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से इस बात को रखते आया हूँ, माननीय मंत्री जी को लिखते आ रहा हूँ लेकिन जब भी प्रश्न आता है तो यही बात कहा जाता है । मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कार्य योजना बनाइये और कार्य योजना में उस चीज को शामिल कीजिये । यदि आपके पास पत्थर नहीं है तो ईंटा का कैरेट बनाकर बोल्डर पीचिंग कीजिये । बंडाल का निर्माण वर्षा से पहले कीजिये जिससे कि आपका यह कटाव बच सके, गॉव बच सके, गॉव बचेगा तभी आप और हम राजनीति करेंगे, अन्यथा जब गॉव नहीं बचेगा तो हम और आप कहॉ हैं ?

महोदय, दूसरा है जल संचय । जल संचय का आज सबसे बड़ी समस्या है । आज पूरा बिहार जल के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है । खास करके सबसे बड़ा जल संकट हमारे विधान सभा क्षेत्र बहादुरपुर में हुआ है । बिहार में किसी जगह यदि जल की समस्या हुई तो बहादुरपुर में सबसे पहले हुई। इस मामले से हमारे माननीय मंत्री जी भी अवगत हैं चूंकि वह भी कहीं न कहीं वहीं से आते हैं । आज स्थिति यह है कि जितनी भी हमारे यहॉ नदियॉ हैं, हमारे क्षेत्र के अन्दर 7 धाराएँ बहती हैं और इस तरह से दरभंगा में देखा जाय तो कई धाराएँ हैं । यदि छोटी-छोटी नदियों को स्लुईस-गेट के माध्यम से, बॉध के माध्यम से जिस तरह से गंगाजी को हरिद्वार में बॉधा गया है और स्लुईस-गेट से हमलोगों को पानी दिया जाता है । जो मुख्य पानी है वह सिंचाई में जाती है और जो बचा-खुचा पानी है, छलक कर हमलोगों के पास आती है और उसी को हमलोग विभिन्न नदियों से मिलकर जो पानी आता है उसको गंगाजल के रूप में स्वीकार करते हैं । लेकिन रीयल में देखिये तो छः महीने तक गंगाजी का पानी हमलोगों को दर्शन नहीं है । महोदय, आप तो खुद इस विभाग के जानकार हैं, आप खुद जाकर देखे हैं, तो उसी तरह से मेरा सलाह होगा कि सरकार बजट में इस चीज का उपबंध करे, जितनी छोटी-छोटी नदियॉ हैं, उनपर बॉध बनावे, स्लुईस-गेट दे, जितनी पानी की जरूरत है, बाढ़ के समय में निकल जाय लेकिन उसके पानी को रोका जाय ताकि आगे उससे पटवन का काम हो सके, लोगों का जल की जो समस्या है उसका निदान हो सके। उसके अलावा जितनी.....

अध्यक्ष : और बोलना है ?

श्री भोला यादव : सर, अभी तो हमें और बोलना है ।

अध्यक्ष : ऐसा करें भोला बाबू, आप 5 मिनट में, 2 बजकर 20 मिनट में समाप्त कर दीजियेगा क्योंकि दल के द्वारा आवंटित समय आपको 20 मिनट है....

श्री भोला यादव : हम 2.05 में शुरू ही किये हैं, सर ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । आप 2.02 से शुरू किये हैं.....

श्री भोला यादव : 2.05 से हम शुरू किये हैं, 10 मिनट अभी बोले हैं ।

अध्यक्ष : सुन लीजिये न पहले पूरी बात । आप 2.20 बजे इसलिये समाप्त कर दीजिये....

श्री भोला यादव : 20 मिनट आवंटित है ।

अध्यक्ष : हॉ, आपको 20 मिनट समय आवंटित है ।

श्री भोला यादव : 2.05 में हम शुरू किये हैं ।

अध्यक्ष : नहीं, 2.02 में आप शुरू किये हैं ।

श्री भोला यादव : नहीं सर, 2.05 से । 2.25 तक हमको दीजिये ।

अध्यक्ष : होता क्या है कि आगे बोलने वाले ज्यादा समय ले लेते हैं....

श्री भोला यादव : नहीं लेंगे, सर ।

अध्यक्ष : विभिन्न दलों द्वारा जो नाम दिया जाता है, पीछे वाले छूट जाते हैं ।

श्री भोला यादव : ज्यादा समय नहीं लेंगे, सर । हम अपने तरीके से कंक्लुड कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

संजय जी, हमारे क्षेत्र में आप क्यों इतना दखल दे रहे हैं ? आप इतने बड़े क्षेत्र के भागीदार हैं तब हमारे क्षेत्र में जबरन कब्जा कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : भोला जी, आप अपनी बात कहिये ।

श्री भोला यादव : ग्रामीण कार्य मंत्री जी पर अभी भी दबाव दे रहे थे । दुर्भाग्य है । आपको अपने क्षेत्र की चिन्ता नहीं है, मेरे क्षेत्र की चिन्ता है ।

अध्यक्ष : आप अपने समय को जाया कर रहे हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरा कहना है कि जितनी बड़ी नदियॉ हैं, उन नदियों को छोटी नदियों से जोड़िये और जब छोटी नदियॉ सूखने के कगार पर हों तो बड़ी नदियों से पानी उसको दीजिये जिससे कि पटवन की समस्या का निदान हो सके । मेरा और कहना है, आज के डेट में, पहले हमारा दरभंगा जिला तालाब का शहर माना जाता था, आज की तिथि में स्थिति यह है कि हमारे लोग, हमारे माननीय लोग बड़े-बड़े तालाब को भरकर उसमें आवासीय बना दिये हैं । तालाब की

स्थिति इतनी विकराल हो गई है, जिस जगह पर 100-100 तालाब था, वहॉं पर अब 25 भी तालाब नहीं बचा है । तालाब का कहीं न कहीं अतिक्रमण हो रहा है, महोदय । जितने भी तालाब हैं, पईन हैं, आहर हैं, उसकी उड़ाही होनी चाहिए । जलाशय में पानी रहेगा तो उससे पटवन होगा ।

महोदय, अभी बिहार में भूगर्भ जल की सबसे बड़ी समस्या हो गई है । दरभंगा जिला का हम बता रहे हैं, जब हमलोग 8वॉं-9वॉं क्लास में पढ़ते थे, उस समय भूगर्भ जल की स्थिति यह थी कि 20 फीट पर पानी उपलब्ध था । आज 250 फीट से नीचे जल स्तर चला गया है । मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भूगर्भीय जल कैसे संरक्षित हो, वर्षा के पानी को कैसे संरक्षित किया जाय, इस पर कार्य होना चाहिए । मंत्री महोदय, इस चीज को नोट करेंगे । भूगर्भ जल में सबसे बड़ी बात यह है कि जल संचय कुऑं का होना अति-आवश्यक है । हरेक आधा किलोमीटर पर जल संचय कुऑं का निर्माण होना चाहिए और उसका डायवर्सन जब वर्षा आये तो जल संचय कुऑं में जल जाय ताकि सीधा लेयर में चला जाय । इस पर कार्य योजना होनी चाहिये, बजट एक बड़ा भाग आप इसपर खर्च कीजिये । यदि उपर में आप जल संरक्षित नहीं कर सकते तो कम से कम नीचे तो जल संरक्षित कीजिये ताकि लेयर बना रहेगा । इसलिये आपको जल संचय का जो कुऑं के माध्यम से लेयर पर पहुँचाने का काम करना चाहिए ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज जल संकट की स्थिति यह है कि आम आदमी के अलावा जानवर-पक्षी.....

अध्यक्ष : संजय सरावगी जी, आज आपके जोड़ा भाई वीरेन्द्र जी तो हैं नहीं, तब आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री भोला यादव : महोदय, जल संकट की स्थिति यह है कि पक्षी को भी पानी पीने का प्रोब्लेम हो गया है, पक्षी के लिए भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, सत्तापक्ष को थोड़ा खराब लग रहा होगा लेकिन एक कहावत है - निंदक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय,

बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ।

माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि निंदा इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि आपका बजट लोकोपयोगी नहीं है । ...क्रमशः...

टर्न-10/आजाद/04.07.2019

..... क्रमशः ......

श्री भोला यादव : आपका बजट कहीं न कहीं लूट-खसोट का बजट है, इसी ओर मैं आपको इंगित करना चाह रहा हूँ । मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि औराई विधान सभा में टैफड डैम बना था 6 महीना पहले, वह टूट गया । आपके कार्य का गुणवत्ता इतना खराब है कि वह टैफड डैम समाप्त हो गया । आप इस डैम के माध्यम से भी पानी संचय कर सकते थे, लेकिन आपकी योजना सही नहीं रहने के कारण समाप्त हो गयी है ।

सभापति महोदय, मैं राजकीय नलकूप के बारे में बताना चाहता हूँ, अभी माननीय मंत्री जी उपलब्ध नहीं हैं, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि नलकूप सिंचाई योजना के तहत राज्य में क्रियाशील होने वाले योग्य 9192 राजकीय नलकूप में 4804 नलकूप चालू है और शेष नलकूपों की मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है । वर्ष 2019-20 में 3654 नलकूप चालू हो जायेगा । महोदय, वित्त मंत्री अभी यहां उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन केबीनेट के और सदस्य हैं । मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं, कुल 4804 नलकूप चालू है, आप इसकी सूची जारी कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यह झुठ का पुलिन्दा है । दरभंगा जिला में 200 से ज्यादा नलकूप है, एक भी नलकूप चालू नहीं है । हमारे गांव में भी नलकूप है, उस गांव की स्थिति यह है कि उस नलकूप में स्टार्टर के चलते, फ्यूज के चलते, मोटर के चलते, बिजली के कनेक्शन के चलते नलकूप आपका चालू नहीं है । आपके विभाग में इच्छाशक्ति का घोर अभाव है और यदि इच्छाशक्ति होता महोदय तो आज वह सब नलकूप चालू हो जाता । बड़ा बीमारी नहीं है, आपका ऑपरेटर नहीं है, आप बड़े पैमाने पर स्थानीय ग्रामीण को ऑपरेटर नियुक्त कीजिए, वह उसका देख-रेख करेगा, उसका संरक्षण करेगा और वह चालू हो जायेगा लेकिन आप चालू कराना नहीं चाहते हैं और आप लोगों को पानी नहीं देना चाहते हैं ......

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : भोला बाबू, अब आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री भोला यादव : नहीं सर, मेरा अभी समय है । महोदय, आप जब आसन पर आये हैं, आपसे हमारी अपेक्षा है, आप पुराने मित्र भी रहे हैं ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ, अब मैं कनक्लूड कर रहा हूँ, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बागमती नदी गुजरती है और बागमती नदी में रतनपुरा के पास, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर भी फोन के द्वारा आग्रह किया था कि आप इसको देखवा लीजिए । रतनपुरा कब्रिस्तान कटाव के कगार पर है, मस्जिद कटाव के कगार पर है, सैदपुर का मस्जिद कटाव के कगार पर है, डगरौल, रामपुर, गुरारी, भवानीपुर, ऊचौली, नेयम यह सब गांव कटाव के कगार पर है । महोदय, इसको देखवा लीजिए और इसको बोल्डर पीचिंग करवा दीजिए .....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : भोला बाबू, अब समाप्त कीजिए ।

श्री भोला यादव : महोदय, दो मिनट । तरालाही एक पंचायत है, जिसमें चाँदी एक गांव है, वहां पर जो पुल एन0एच0 पर बन गया है, उस पुल का धारा इस तरह से है कि सीधा गांव में मारता है । यदि उस सुरक्षा बॉंध का बोल्डर पीचिंग नहीं हुआ, बांध को प्रोपर तरीके से नहीं बनाया गया तो गांव कट जायेगा । कमला नदी में दूनी गांव के पास एक भूतही बांध है, उस भूतही बांध पर इसी सदन से सूलिस गूट के लिए माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था लेकिन अभी तक आपके इंजीनियर देखने तक नहीं गये हैं...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : हो गया भोला बाबू, अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री भोला यादव : इसको आप कीजिए और मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को, अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और आपको भी धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : भोला बाबू, अब आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

(व्यवधान)

शांति-शांति । एक मिनट आपलोग बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री गुलाब जी, श्री भोला बाबू बैठ जाईए । माननीय सदस्य, आप सबलोग बैठ जाईए ।

माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता । माननीय सदस्य को बोलने दीजिए न ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र .....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जायं । शांति-शांति । माननीय सदस्य श्री निरंजन बाबू, आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वर्ष 2019-20 के अनुपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन में बोलने का आपने जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आपलोग इनकी बात को सुनें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने न्याय के साथ विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का तथा माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का, माननीय लघु जल संसाधन मंत्री महोदय का एवं विधि विभाग का और मैं इस सदन से बिहारीगंज की अवाम जनता को भी यहां से उनका भी हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और मधेपुरा जिला के सम्पूर्ण वासी का, आम जनता का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, जिन्होंने इस सदन में भेजने का काम किया है ।

सभापति महोदय, यह विभाग अतिमहत्वपूर्ण विभाग है जल संसाधन विभाग, भारत कृषि प्रधान देश है और 85-86 प्रतिशत जो किसान हमलोग हैं, उनका कार्य इसी जल संसाधन विभाग से होता है जो कि खेती पर निर्भर करता है । मैं कोशी इलाका से आता हूँ और कोशी बराज भीमनगर से ही कोशी कमीश्नरी के हर एक जिले में जो नहर प्रणाली निकली है, उसमें कोशी का ही वीरपुर-भीमनगर से जल प्रवाहित होता है । महोदय, राज्य में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की दिशा में जल संसाधन विभाग राज्य में सदैव प्रयत्नशील है । जल संसाधन विभाग बाढ़ नियंत्रण एवं जल-निस्सरण के जनोपयोगी काम को संपादित करता है । भौगोलिक एवं जलवायु जनित स्थितियों के कारण वर्षा ऋतुओं में जब राज्य की नदियों में एक तरफ भीषण कटाव एवं बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न होती है और दूसरी तरफ खरीफ फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है । हरेक मौसमी फसल में चाहे वह रब्बी का हो, खरीफ का हो, समयानुसार जल संसाधन विभाग के द्वारा नहर प्रणाली के द्वारा खेत में ससमय पानी पहुँचाया जाता है । आज जितना भी नहर प्रणाली है, सबों में ससमय सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा दी जाती है । महोदय, जल संसाधन

विभाग जहां बड़ी योजनायें तथा छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है ।

महोदय, ह्‌ासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन, गाद एवं क्षरण के कारण सिंचाई योजनाओं की क्षमता का स्वाभाविक ह्‌ास होता है, जिसका नियमित पुनर्स्थापन विभाग के द्वारा कराया जाता है । इस वर्ष चौसा पम्प नहर द्वारा वियर योजना, अपर किऊल जलाशय योजना, पूर्वी कोशी नहर योजना, अमरा वितरणी, सैदपुर वितरणी, कर्मनाशा सिंचाई प्रणाली, पटना मुख्य नहर, आरा मुख्य नहर, चन्दन जलाशय योजना, सोन पश्चिमी समानान्तर लिंक नहर, कुंदर बराज योजना, बदुआ जलाशय योजना, पश्चिमी गंडक नहर आदि का पुनर्स्थापन किया जा रहा है जो कि विभाग के द्वारा अंतिम चरण में है । महोदय, सिंचाई उपलब्धि 2018 के खरीफ फसल में 20.4 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान की गयी है, जो अब तक का रेकोर्ड कार्य है । महोदय, बाढ़ प्रबंधन की नई योजना का भी जो इसी विभाग से कार्य कराया जा रहा है । इस वर्ष सीतामढ़ी जिला में रातो नदी पर तटबंध का निर्माण कार्य ...... क्रमशः ......

टर्न-11/ज्योति/04-07-2019

क्रमशः

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, सिंचाई उपलब्धि की बात मैं बता रहा हूँ । वर्ष 2018 के खरीफ फसल में 20.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान की गई है जो अब तक का रिकार्ड है । महोदय, बाढ़ प्रबंधन की नई योजना का शिलान्यास / उद्‌घाटन -इस वर्ष सीतामढ़ी जिला में रातो नदी पर तटबंध निर्माण कार्य, लखनदेई नदी की पुरानी घार का पुनर्स्थापन कार्य एवं मनुषमारा जल निस्सरण योजना का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा फरवरी 2018 में सम्पन्न हुआ । पुनः बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3(ए) के तहत बागमती दायें तटबंध, कोशी नदी पर नगरपाड़ा तटबंध गंगा नदी पर बदलाघाट नगरपाड़ा तटबंध के उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं पककीकरण कार्य का शिलान्यास मार्च 2018 में तथा कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पककीकरण कार्य का शिलान्यास मई, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संपन्न हुआ । नवम्बर, 2018 में पुनपुन बायां तटबंध के दीदारगंज से गौरीचक तक सड़क के पक्कीकरण कार्य को प्रारम्भ किया गया है ।

महोदय, तटबंध का निर्माण कार्य भी हो रहा है । राज्य में कुल 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । अबतक 3770 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कार्य कर 39.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की गई है। अगले पॉच वर्षों में 1676 किलोमीटर अतिरिक्त तटबंध का निर्माण करने के लिए विभाग क्रियाशील है जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार का महानंदा तटबंध भी प्रमुख है । इससे 23.16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान हो रही है ।

बाढ़ 2019 के पूर्व बाढ़ की विभीषिका से बचाव की तैयारी के लिए तटबंधों को नदी के कटाव से सुरक्षित रखने की योजना युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है । बाढ़ 2019 के पूर्व पूरा करने हेतु 136 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है । बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली प्रारंभ किया गया है । इसके द्वारा 72 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी वेब पोर्टल एस.एस. एस. एवं बाढ़ बुलेटिन के माध्यम से दी जाती है । सुपौल में एक भौतिक प्रतिमान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिससे बाढ़ प्रबंधन के कार्य में सहायता मिलेगी ।

महोदय, वर्ष 2019-20 में वास्तविकता समय आधारित जलीय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली को विकसित किया जाना है । इससे बाढ़ पुर्वानुमान को बेहतर करने में मदद मिलेगी । जल संसाधन विभाग अन्य बहुत कार्यों पर बेहतर काम कर रहा है जिससे बाढ़ के खतरे से आम जन का बचाव हो सके।

सभापति महोदय, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा भी राज्य में जितना भी खराब नलकूप था सबों को सही कराया जा रहा है इसका प्रमाण है मैं पिछले वर्ष भी हमारे क्षेत्र में दो चार पॉच नलकूप खराब पड़ा हुआ था जिससे कि किसानों की समस्या दूर नहीं हो रही थी । उसमें हम दो चार नलकूप के लिए हम लघु जल संसाधन विभाग में प्रश्न काल के दौरान अपना संज्ञान दिए थे सदन के माध्यम से तो मेरा सब काम इस विभाग द्वारा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा भी किया गया है । हमारे क्षेत्र में तुलसिया है, पड़ौकिया है, सरौनी में वगैरह वगैरह में जहॉ भी मैं प्रश्न काल के दौरान संज्ञान दिया था वह कार्य उसका हो चुका है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में ये सब उत्कृष्ट कार्य जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है । लघु जल संसाधन विभाग के भी माननीय मंत्री द्वारा भी सभी कार्य को किया जा रहा है । यह तो राज्य की जनता देख रही है । आज लोक सभा

चुनाव में किए गए कार्य का ही फलाफल है कि इतनी अपार जबर्दस्त मैनडेट हमलोगों को मिला है ।

महोदय, मैं अपना कुछ क्षेत्रीय सुझाव भी टाईम लगेगा उसमें रखना चाहता हूॅ । मेरे विधान सभा बिहारीगंज में कुछ क्षेत्रीय कार्य है जो कि आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं । इसके पहले भी मैं समय समय पर आकृष्ट किया हूॅ और सुनवाई भी हुई है इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभाग द्वारा दो तीन काम है जिस पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ । हमारे विधान सभा में ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत झिटकिया कलौतहा पांचायत के वार्ड नं0 4 में नहर पर चचरी का एक पुल है दोनों तरफ से......

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : एक मिनट समय लेंगे, हम अपनी बात रखेंगे । हम अपने कन्कलुड कर रहे हैं दोनों तरफ से सड़क बनी हुई है उसपर हम चाहेंगे एक छोटा सा पुल हो जाय। ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत ही सूखासन पांचायत के कमलपुर गोसाई टोला स्थित वार्ड नं0 2 तथा वार्ड नं0 6 के बीच बेलदौर प्रशाखा नहर वितरणी के दोनों तरफ ग्रामीण सड़क बना हुआ है, एक पुल उस पर भी हो जाय, हम बाद में माननीय मंत्री महोदय से जाकर अनुरोध करेंगे और लोक सभा चुनाव में दोनों के बारे में हमने कहा था इस विभाग के विश्वास पर कि पहले भी मेरा काम होते आया है, उनलोगों को मैं आश्वासन भी दे चुका हूॅ और अब तो बरसात का समय आ गया है श्रीमान् इसलिए ग्वालपाड़ा प्रखंड के बभनगामा बिंदटोली, अरार-डफरा भित्ता टोला एवं मुरलीगंज प्रखंड के तिलकोरा तथा वृन्दावन में जो सुरसर नदी का जो कटाव होता है हर एक वर्ष काम हुआ है सभापति महोदय, और इस बार चाहेंगे कि बराबर काम होता है, उसमें बोल्डर पीचिंग की व्यवस्था कर दी जाय जो कि परमानेंट सौल्यूशन हो जायेगा, विभाग भी शांत हो जायेगा और हम लोग भी शांति से घूमेंगे । एक मांग है कि किशनगंज जिला प्रखंड ठाकुरगंज के पौआखाली बाजार तथा पूरन फूलगाछी के कटाव निरोधक कार्य में भी काम कराया जाय ।

श्री अशोक कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूॅ बोलने के लिए । सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिल से बधाई देता हूॅ और माननीय मंत्री जल

संसाधन का अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने जो बजट लाया है किसानों के हित में लाया है । महोदय, जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व है कि वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का रख रखाव और जो अपना इष्टत्तम लक्ष्य है बिहार का 53.53 करोड़ उस लक्ष्य को हासिल करना । आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि विभाग ने कड़ी मेहनत करके जल संसाधन विभाग ने 30.4 लाख हेक्टेयर का सृजन क्षमता बनाने का काम किया है और सृजन क्षमता ही नहीं महोदय, जो हमारा ह्रासित इलाका था, उसपर लगभग एन.डी.ए. की सरकार ने 3 लाख हेक्टेयर उस ह्रासित क्षेत्र को भी नहरों का रख रखाव करके मरम्मत करके उसे हासिल किया है । महोदय, सर्वप्रथम मैं कदवन जलाशय योजना की चर्चा करना चाहता हूं जो अब इन्द्रपूरी के नाम से जाना जाता है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सरकार को कि जो काम हमारी पिछली सरकारें नहीं कर सकीं । यह काम होना चाहिए था आज से 20 साल पहलजे, 25 साल पहले तो जिसतरह की संकट है महोदय, पूरे देश में जल का बिहार भी उससे अछूता नहीं है लेकिन किसी ने कदवन जलाशय की चिन्ता नहीं की है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे स्वयं गए और इस इलाके को देखें और देखने के बाद बड़े ही त्वरित गति से उसपर काम हो रहा है । तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों की कमिटी बन गयी । यह जलाशय महोदय, रोहतास जिला के मटियांव गांव के पास बनने जा रहा है और इसमें महोदइय, 14 फरवरी 1917 को इन्द्रपुरी जलाशय योजना के परामर्शी द्वारा तैयार की जाने वाले डिटेल डी.पी. आर. के समीक्षा की योजना है, टास्क फोर्स का गठन हो गया है और विभाग का संकल्प है कि 2020 तक इसको डी.पी.आर. बनाकर सी.डब्लू.सी. में दिल्ली भेज दिया जायेगा और सहमति मिलने के बाद कदवन जलाशय बनेगा जो आज इन्द्रपुरी के नाम से जाना जाता है । मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि जब हमारा कदवन बन जायेगा तो पूरा शाहाबाद और मगध का इलाका पूरे बिहार को खिलाने का काम करेगा इतनी हमारी पैदावार होगी और हमारे किसान इतने आत्मनिर्भर होंगे । माननीय सदस्य भोला बाबू कह रहे थे कि बजट जब बना तो लगा कि बड़ा बड़ा काम होगा । कहीं काम दिखायी नहीं देता मैं उनसे कहना चाहता हूँ ।

क्रमशः

टर्न-12/04.7.2019/बिपिन

श्री अशोक कुमार : क्रमशः मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आँख खोलकर देखिए । 1975 की योजना, सभापति महोदय, दुर्गावती जलाशय योजना जो उग्रवादी और आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ था, वह इलाका, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज हमारा दुर्गावती जलाशय एन.डी.ए. की सरकार में बनकर किसानों के खेत को पानी दे रहा है और एक भी उग्रवादी और आतंकवादी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और वह पर्यटन का दर्जा ले रहा है महोदय ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं, देखना चाहिए कि क्या पियरा पंप कैनाल बन रहा है कि नहीं, जयपुरा पंप कैनाल बन रहा है कि नहीं तेजी से, निकरिस में पंप कैनाल तेजी से बन रहा है कि नहीं । धरहर पंप कैनाल बन रहा है कि नहीं । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभापति महोदय इस सरकार को कि इसके वरिष्ठतम पदाधिकारी यहां तक कि विभाग के प्रधान सचिव नदियों के किनारे-किनारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर घूमते हैं और योजना लाते हैं, कैबिनेट से कराकर योजना को जमीन पर उतारने का काम करते हैं महोदय । जो आपने हमें विरासत दिया था जल संसाधन में महोदय, 27 हजार लाख हेक्टेयर इनका विरासत दिया हुआ था हमारा जो अविभाजित बिहार था महोदय, इनका बजट देख लीजिए 2005 का महोदय, 2005 का बजट इनका साढ़े तीन सौ करोड़ व्यय करते थे अविभाजित बिहार में और आज हमारी सरकार और हमारा विभाग लगभग तीन हजार करोड़ रूपया जल संसाधन पर खर्च कर रहा है महोदय । आपको गंगा का बटेश्वर स्थान पंप कैनाल देखना चाहिए । 1978 की योजना थी जिसको सरकार ने चालु किया । निश्चित रूप से सरकार बधाई के पात्र हैं महोदय और यह सरकार काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है और सरकार का जो लक्ष्य है महोदय, सरकार अपने लक्ष्य पर चल रही है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य संजय सरावगी जी, बातचीत नहीं ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, समय बहुत कम मिला है । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं । आप नए हैं, युवा हैं, आप काम करने वाले हैं । जमानिया पंप कैनाल के विषय में कहना चाहता हूं महोदय । जमानिया पंप कैनाल की लाइनिंग की नहर बन गई है, सारी वितरणिया लाइनिंग की बना ली गई है सभापति जी लेकिन...

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य गंभीरता को समझ रहे हैं और जल संसाधन पर बोल रहे हैं । शांति बनाए रखिए । बातें ध्यान से सुनिए ।

श्री अशोक कुमार : उसके जो 56 और 57 जलवाहा हैं महोदय, वह पंप कैनाल फिलिंग पर बना है महोदय । कहीं 20 फीट ऊंचा, कहीं 15 फीट ऊंचा और उससे हमारे कच्चे जलवाहा निकले हैं सभापति महोदय । हमारे पंप में और कैनाल में, नहर में पानी रहते हुए किसानों के खेत को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि जलवाहा के सिस्टम को भी पक्का बना दीजिए, आपका सिंचन क्षमता बढ़ जाएगा और किसानों के खेत को पानी मिलने लगेगा । मुझे यकीन और विश्वास है सभापति महोदय....

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य शक्ति सिंह जी ।

श्री अशोक कुमार: दूसरी बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । अप्रैल, 1998 का लड़मा पंप कैनाल चालु है ....

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य बैठ जाइए । माननीय सदस्य अत्री मुनि जी बैठ जाइए । आप तो गंभीर सदस्य हैं, बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आसन से कहा जा रहा है । टोका-टोकी नहीं करें ।

श्री अशोक कुमार: सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा । लरमा पंप कैनाल 60-60 क्यूसेक की तीन मोटर है । 1998 अप्रील से चालु है । एक घंटा पार हो चुकी है चलकर । 20 साल उन मोटर और पंप का लाइफ समाप्त हो गया है जो समाप्त हो गया है । आए दिन रोज ब्रेक डाउन होते रहते हैं मोटर और पंप महोदय और सरकार 82 करोड़ से उसी पंप कैनाल के नहर पर लाइनिंग का काम करा रही है और ऐसा नहर का काम हो रहा है कि मैं माननीय सदस्य शक्ति भाई से कहना चाहता हूं कि आप 15 साल में जो नहीं कर सके, इस सरकार ने रामगढ़ में तीन और चार साल में किया है, चल कर देखने का काम करिए । इसलिए उस पंप कैनाल के मोटर और पंप को बदलने का आपसे अनुरोध करते हैं, उसे बदल दीजिएगा तो किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिलना शुरू हो जाएगा ।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं । इसी सदन में गैर-सरकारी संकल्प में, माननीय मंत्री जी जरा ध्यान आकृष्ट करेंगे, इसी सदन में गैर-सरकारी संकल्प में सरकार ने स्वीकार किया है कि रोहतास जिला में परिखन के डेरा के पास एक पंप

कैनाल लगाकर करगहर रजवाहा में गिराकर और किसानों के खेत को पानी दिया जाएगा । डी.पी.आर. की मांग की गई है । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि डी.पी.आर. मंगाकर उस योजना की भी स्वीकृति देने की कृपा करें और आप काम करते रहिए और जैसे ये जीरो पर आउट हुए हैं, इस बार भी जीरो पर इनलोगों को हमलोग फिर आउट करेंगे, काम के बदौलत आउट करेंगे और जनता ने मन बना लिया है ।

तीसरी बात सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सोन का सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतर और सस्ता सिस्टम है । आप सोन के सिस्टम को पक्कीकरण करा दीजिए और जिस दिन सोन का सिस्टम पक्कीकरण हो जाएगा, पूरा शाहाबाद और मगध के किसान खुशहाल हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जो आज हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है ....

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप कंक्लुड करिए ।

श्री अशोक कुमार : जो हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है सभापति महोदय, जैसे लाइनिंग होगा नहर का, हमारी क्षमता 20 प्रतिशत नहर की बढ़ जाएगी । लोग भू-गर्भ का जल निकालना बंद करेंगे । हमारा नीचे का भू-जल भी मेंटेन रहेगा और किसानों के खेत में पानी भी मिलेगा ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप कंक्लुड करिए ।

श्री अशोक कुमार : इसलिए सोन के सिस्टम का लाइनिंग कराया जाए । सोन के सिस्टम को पक्कीकरण किया जाए । इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं एक बार सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार । 10 मिनट ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, आज के इस बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, सरकार जो यह प्रस्ताव लाई है, मेरा मानना है कि इस 2019-20 का माननीय वित्त मंत्री जी का जो यह बजट भाषण है, देखने में पुस्तक जितनी अच्छी है और उतने अच्छे से हमलोगों ने आशा भरी निगाहों से देखा था कि इसमें कुछ बिहार की जनता के लिए और जनता के अनुकूल कुछ इस बजट में है लेकिन जितना सुन्दर यह पुस्तक आई है, इस बजट का यदि आकलन इनके भाषण से हम करें तो यह 2018-19 और 2019-20 के बजट के व्यय के प्रावधानों में बजट 6. 22 दशमलव पिछले वित्तीय वर्ष से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अंतर है और सरकार यह ढिंढोरा पीट रही है कि हम जल संसाधन के लिए बहुत बड़े कार्य योजना बना रहे हैं

और हम समझते हैं कि यदि जनहित में बना रहे हैं तो विपक्ष में होने के नाते भी आपका मैं पीठ थपथपाने का काम करता लेकिन किसी ऐंगल से यह जल संसाधन ऐसा श्रोत है कि इस विभाग का परिकल्पना जिसने भी पहले किया होगा, वह जल संसाधन के श्रोत को देखते हुए आज से, 1962 से जब हम अपना स्वाधीनता बाद में आए और इसका प्राक्कलन हुई होगी तो वर्तमान में जितनी भी आपकी बराजें हैं, जहां से आप जल संग्रह करते हैं और जहां से आपको जल की प्राप्ति होती है और किसानों के खेत और खलिहानों तक जल पहुँचाते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप 1962 के बाद सरकार बजट लाई और यह वर्त्तमान सरकार 15 साल रही, 15 साल के लेखा-जोखा में क्रमशः

टर्न : 13/कृष्ण/ 04.07.2019

श्री राजेश कुमार (क्रमशः) हमारा मानना है कि सरकार ने बजट में केवल प्रावधान किया है, अच्छी-अच्छी बातें पुस्तक में दिखाई है लेकिन पानी के मामले में, जल संसाधन के मामले में पहले हम जितना क्यूबिक फीट जल संग्रह करते थे, आज चाहे वह प्राकृतिक कारण हो, चाहे हमारा जल स्रोत का बदलाव हो, इसमें सरकार की योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है । महोदय, इस योजना में यदि हम बात करें, इस योजना में जब हम उदाहरण दें इन्द्रपुरी बराज का, चाहे मोहम्मद गंज बराज का, बिहार सरकार जिस बराज में, जो हमको 1962, 1977, 1980 और 1983 से लेकर जिस मोहम्मद गंज बराज में जितना क्यूबिक फीट पानी, जब झारखंड और बिहार एक साथ था, जल का बंटवारा हमारी यह सरकार नहीं करा पायी है । महोदय, यह मेरा अनुभव है । वर्तमान स्थिति में झारखंड सरकार से और बिहार सरकार से जो आपका मापदंड है, जितना क्यूबिक फीट पानी संग्रह आपको मिलना चाहिए, क्या वह यह सरकार दिलाने में सक्षम है ? क्या हम किसानों को पानी दे रहे हैं ? यदि यह देखा जाय तो जो हमारे किसानों को पानी झारखंड से होते हुये बराज से हमको जितना पानी मिलना चाहिए मोहम्मद गंज बराज से, उत्तर कोयल नहर में आप नहीं दे पा रहे हैं । ये सारी योजनायें जो आप बजट में लाये हैं, सिंचाई संग्रह योजना, ये सारे के सारे सिफर हैं, महोदय, इसलिए मैं सारे योजनाओं को सिफर कह रहा हूं कि इसके पीछे मेरा तर्क है । तर्क यह है कि क्या हमारा 1977, 1973, 1978 में जो बिहार, जिस समय झारखंड हमारे साथ था, हम बिहार के थे और बिहार में हमारे किसानों

को जो पानी मिल रहा था, क्या आज बिहार सरकार किसानों को पानी दे पा रही है, नहीं दे पारी रही है । इसके लिये मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। पिछली बार आपकी एक योजना आयी थी सुखाड़ के मद्देनजर 19.49 करोड़ की, आई0एम0ए0 4200 नये चापाकल के निर्माण कार्य की सूची जो जल संग्रह के लिये बनायी गयी थी, पशुओं के लिये भी किया गया था, आज आप मात्र 1500 जगहों में कैट्ल ट्रैप आंकड़ों में दिये हैं । लेकिन आज के दिन आप चले जाईये उत्तर बिहार के भागों में, दक्षिणी बिहार के भागों में, वहां पशु पानी के बगैर मरे हैं, चारा के बगैर मरे हैं । आप यदि जल संसाधन के पुराने परम्परागत स्रोतों को भी सिंचित नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि यह सरकार लंबी-चौड़ी बजट दे रही है, उसको देने का कोई मतलब नहीं है । चूंकि जब आप पुरानी दिये हुये चीज को बचा नहीं सकते तो केवल सदन में बैठ करके चिन्ता व्यक्त करके, बाहर निकल करके और डिबेट में भाग ले करके चल जाने से किसानों का काम नहीं होनेवाला है ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहना है कि जो हमारा परम्परागत जल संचय योजना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा कि हमने कहा कि 1962 के बाद जो परम्परागत स्रोत थे, नदी, पहाड़, नाले, बारिश का पानी जो पहाड़ पर होते थे, उसके माध्यम से दे करके, रोहतास में जगजीवन नहर का जो निर्माण हुआ, आज वह हमारे किसानों के लिये स्वर्ण के समान है । लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहता हूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सरकार की कहीं से कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखती है । बजट में आप प्रावधान किये हैं, सदन को मैं बताना चाहूंगा कि बांका जिले के बाबू महल गांव में किसान 0.32 परसेंट एकड़ में फैले अपने खेत में वह खेती कर रहा है । उन्होंने अपने गांव में छोटे-छोटे तालाब बनाकर बरसाती पानी जमा करके अपने गांव के बीच में बांध बना करके उन्होंने खेती किया है । वह अपने 32 एकड़ जमीन में पपीता , अमरूद और अन्य खेती की सुविधा उपलब्ध वह करवा रहा है । तो क्या सरकार इस क्षेत्र में कोई कारगर योजना नहीं बनायी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का । चूंकि कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार पिछले 6 सालों में 2 लाख हेक्टअर सिंचित क्षेत्र में पानी की कमी आयी है और कुल सिंचित क्षेत्र के 35 लाख 20 हजार हेक्टेअर है, इनमें 10 लाख 11 हजार हेक्टेअर क्षेत्र नहर से है और 1 लाख 17 हजार हेक्टेअर तालाब से है और 23

हजार हेक्टेअर क्षेत्र कुआं से है जिसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । महोदय, कुआं जल का एक ऐसा स्रोत है, जो भूगर्भीय जल संग्रह के लिये सबसे पुराना परम्परागत योजना था । आज मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप उन कुओं का सर्वे करायें जो आज भी जीवित है और उसका जीर्णोद्धार करायें । यदि उन कुओं का जीर्णोद्धार कराते हैं तो उसके आस-पास के वातावरण का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी है, वह कुओं में संग्रह होता है और वह सालो साल नहीं सूखता है । उससे पशु को भी पीने का पानी, मनुष्य को भी पीने का पानी और सिंचाई के लिये भी वह पानी देने में समर्थ होता है।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : अब आप एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महादय, मैं दो मिनट में अपने क्षेत्र की कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर अपनी बात समाप्त करता हूं । महोदय, देव प्रखंड अंतर्गत बरन्डा रामपुर पंचायत है, उस पंचायत में एक बूढ़ा-बूढ़ी बांध का प्रस्ताव है, महोदय, प्राकृतिक पानी जो बह जाता है, उसके संग्रह के लिये मैंने एक प्रस्ताव दिया था और सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है और 3 करोड़ 80 लाख रूपया सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में है । दूसरी तरफ कुटुम्बा प्रखंड के पंचयात डुमरा में कनौडा माईनर का भी प्रस्ताव सरकार स्वीकृत की थी, लेकिन आवंटन नहीं मिला है और कुटुम्बा प्रखंड के ही बरहेटा माईनर में 200 करोड़ का ....

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत। आपका समय 14 मिनट है ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान मांग के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, दल ने आदेश दिया कि जनता के हित की बात अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं । हमने पूछा कि कौन हैं मंत्री, कहां से पढ़े हैं तो लोगों ने कहा कि जे0एन0यू0 के छात्र हैं । महोदय, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि जे0एन0यू0 के छात्र के सामने अगर मैं बोलूंगा, मुझे थोड़ी भरोसा जगी कि वे मेरी बात को सुनेंगे । इसके पहले भी मुझे बोलने के लिये कहा गया था तो हम ने पूछा कि कहां से पढ़े हैं तो लोगों ने कहा कि गर्म दल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं । तब हम ने कहा कि नहीं बोलेंगे । जो व्यक्ति गर्म दल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और जो व्यक्ति जे0एन0यू0 का छात्र रहा हो, हमको भरोसा है और हमने जो जानकारी हासिल

की । हमने पूछा मंत्री जी कौन-से दल से हैं कहा कि भाजपा छोड ़करके जदयू में आये है तो और मुझे खुशी हुई, तब तो लगता है कि जहां पर मानवता नहीं हो, उस दल को छोड़ कर आये हैं तो निश्चित रूप से वह बात सुनेंगे । महोदय, बड़ी खुशी हुई, कल इस विभाग में क्या हुआ था, हमको पता नहीं है

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : आप उधर ध्यान नहीं दे, आसन की ओर देखकर अपनी बात जारी रखें । शांति, शांति । आप आसन को देखकर बोलें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय मंत्री जी से आप के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, इनके द्वारा बिहार में बहुत सारी योजनायें चलायी जा रही हैं । चूंकि ये नये आये हैं, बिहार में जितनी योजनायें चल रही है, उसको ये कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं ? लगातार जब विपक्ष बोलता है तो लोग क्या कहते हैं कि 15 वर्षों की सरकार है । 15 साल की सरकार में बाढ़ आती थी कि नहीं आती थी । आप की सरकार में बाढ़ आती है कि नहीं आती है । आप की सरकार में चूड़ा और मीठा बंटता है कि नहीं बंटता । हमारी सरकार में बंटता था कि नहीं बंटता था । भई, मेरी सरकार जंगल राज थी, आपकी कौन-सी सरकार है । महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 36 अरब रूपया मांगा है कि हमको 36 हजार रूपया चाहिए । 36 अरब रूपया प्राप्त करके भी अगर आप चूड़ा और गुड़ बांटते हैं, इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है ? जब मेरी सरकार थी ।

(व्यवधान)

हां, हां । चिकेन मटन । आप आदी हैं । महोदय, आदत है । जब विकास की बात होती है । यह कोई हमारी बनावटी बात नहीं है ।

क्रमश :

टर्न-14/अंजनी/दि0 04.07.19

श्री कुमार सर्वजीत : क्रमशः....... जब 15 साल की सरकार थी तो आप देखिए कि कितने पैसे खर्च होते थे । बाढ़ आती थी, आज की सरकार में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं बाढ़ आती है कि नहीं आती है । लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि पहले के मंत्री बेगूसराय, मुंगेर, हमलोग तरसते थे कि किसी तरह गया, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद आये, एक नजर देख ले कि वहां के गरीब-गुरबा, दलित कहां से पानी पीता है । नहर में पानी है कि नहीं है । सपना था हमलोगों का, अवधेश बाबू बैठे है। इन्होंने कहा कि ललन बाबू को मैं ले जाता हूँ, सदन में

नहीं हैं, माफ करियेगा, हमने कहा कि ले चलिए । गया की हालत बहुत खराब है, नहर में पानी नहीं रहता है, हमने कहा कि खाना तो आप खिलायेंगे, गरीबों का पैसा है वह । अनाज जो है, बिना पानी का, कड़ी मेहनत करके जो किसान ने उपज किया है, आप वैसे लोग को ले जा रहे हैं खिलाने के लिए । दस हजार लोग वहां पहुंचे, मांग रखा और कहा कि तिलैयाढ़ाढ़र योजना अगर शुरू हो जाती है तो सिंचाई की दिक्कत नहीं होगी । मंत्री जी आप ध्यान देंगे, हमको पूरा भरोसा है कि चूंकि लोग कहते हैं कि संजय जी, माननीय मंत्री महोदय जहां से बिलोंग करते हैं, बचपन में नहर का पानी देखते थे और मछली भी पकड़ते थे, खेलते थे, आज उनसे हमें पूरा भरोसा है कि जब वे आज की हालात को देखेंगे तो उनको भी दर्द होगा कि जिस जगह पर हम खेलते थे, जिस जगह पर पानी की धारायें बहती थी, आज वहां पर किसान अपनी आंसू को बहा रहा है । हमको पूरा भरोसा है कि वे हमारी बात को समझेंगे और जो जनता की मांग है उसको पूरा करेंगे । झारखंड में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार और भारत देश में, हिन्दुस्तान में आपकी सरकार है....

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, हम कुछ कहना चाहते हैं कि...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अवधेश बाबू बैठ जायें । माननीय सदस्य आप अपनी बात जारी रखिए । माननीय सदस्य अवधेश बाबू बैठ जायें । सूचना आप बाद में दे देंगे । आप बैठिए न । माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखिए ।

(व्यवधान)

समय सबका तय है, आपको जो भी बात कहनी हो, आपके सदस्य इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं, वे अपनी बात को कहेंगे । आप बैठ जायें । आप अपनी बात को जारी रखें । सर्वजीत जी, आप आसन की ओर देखकर अपनी बात जारी रखिए । आपकी पार्टी का समय तय है और आपके माननीय सदस्य सदन में बोल रहे हैं, इसलिए आपकी जो बातें हैं, उनके द्वारा आप कहवाइए । बैठ जाइए, अवधेश बाबू ।

श्री अवधेश प्रसाद सिंह : मेरा प्वाइंट ऑफ औरडर है...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आप बैठ जाइए । कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बात जारी रखिए । कुमार सर्वजीत जी, आप अवधेश बाबू की ओर नहीं देखिए, आप आसन की ओर देखिए और अपनी बात को कहिए ।

(व्यवधान)

आप अपनी बात को कहिए न । आपको तय नहीं करना है, आप अपनी बात कहिए । आप अपनी बात को जारी रखिए । कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बात को जारी रखिए, आपका समय घट रहा है । आप अपनी बात जारी रखिए समय बीता जा रहा है न । आप अपनी बात जारी रखिए सर्वजीत जी । कुमार सर्वजीत, आप अपनी बात को जारी रखिए । आपका समय बीता जा रहा है ।

(व्यवधान)

अवधेश बाबू, आप बहुत ही वरीय सदस्य हैं, बैठ जाइए । मेरा आग्रह है कि आप बैठ जाइए ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : मैं नहीं बैठूंगा ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : मेरा आग्रह है कि आप बैठ जायें । कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बात जारी रखिए । कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बात जारी रखिए, आपकी बात माननीय मंत्री और आसन सुन रहा है । आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, तिलैयाढ़ाढ़र जिस तरह से सुखाड़ उत्पन्न हुआ है पूरे मगध प्रमंडल में, एक भी ऐसा कोई नहर नहीं है......

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : इस तरह से आसन पर टिप्पणी नहीं करें । हम बार-बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी आसन पर नहीं करें । आप बैठ जायें । आपकी पार्टी को समय आवंटित है, उसमें अपनी बात को कहें । माननीय सदस्य, कुमार सर्वजीत जी, आप अपनी बात को जारी रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, झारखंड में सरकार भाजपा की, बिहार में सरकार आप दोनों की, देश में सरकार भाजपा की और हम उम्मीद करते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि एक बार माननीय मंत्री जी समय दें, गया में, औरंगाबाद में, नवादा में, जहानाबाद में हालात को देखें कि वहां पर किस तरह से हालात उत्पन्न हैं । न जानवर पानी पी सकता है, न आदमी को पीने का पानी है, इसलिए महोदय हम एक सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि झारखंड से वह पानी आता है और वह पूरे गया जिला में इतने बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा पहुंचायेगा और यह लम्बी मांग है, बहुत दिनों से यह मांग चलती आ रही है कि तिलैयाढ़ाढ़र परियोजना चालू की जाय । महोदय, गया भगवान बुद्ध की धरती है, विष्णु की धरती है, जो साथी यहां पर बैठे हैं, सबको एक-न-एक

दिन गया के विष्णुपद में आना पड़ता है और वहां पर हमलोगों ने सुझाव दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था, जीतन राम मांझी जी भी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, उनको भी हमलोगों ने सुझाव दिया था कि फल्गू नदी का पानी बड़े पैमाने पर बर्बाद होता है । वहां पर वीथोशरीफ में हमलोगों ने आग्रह किया था कि फल्गू नदी में वहां पर बांध बनाया जाय ताकि पूरे गया में जल संचय हो सके । अगर यह बात मानी जाती, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि अगर हमलोगों की बात मानी जाती, वीथोशरीफ बांध को अगर बनाया जाता, मुझे नहीं लगता है कि गया में यह हालात उत्पन्न होता । आज एक-एक बुंद पानी के लिए जिस तरह से गया के लोग तरस रहे हैं, अगर सरकार के द्वारा वीथो बांध बना दिया जाता तो पूरा-का-पूरा पानी वहां पर रूकता, किसान उससे खेती करते, जलस्तर हमारा बचता । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप आयें और आकर देखें, देश-विदेश न जाने हजारों ऐसे कंट्री हैं, जहां से लोग आते हैं गया में पिंड दान करने के लिए आते हैं । भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आते हैं और जब देखते हैं विदेश के लोग कि इतनी बड़ी नदी और इतनी पवित्र स्थल पर उस नदी में एक बुंद पानी नहीं है। हमलोगों को भी शर्म आता है । मारीशश एक छोटा सा देश है हमलोगों को भी मौका मिला है जाने के लिए, हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि आप सरकार से अनुमति लीजिए और वहां की प्लानिंग को देखिए । चारों तरफ से समुद्र है और वह शहर छोटा-सा पूरे समुद्र के पानी को रोक रखा है और अपने अन्दर जितना खारा पानी जो था, उससे सिंचाई, उससे पीने का पानी सारी व्यवस्था वह करता है । इसलिए हम मांग रखते हैं और साथ-साथ सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जल संकट को देखते हुए बड़े पैमाने पर आहर-नहर की सफाई होगी । हम लघु जल संसाधन विभाग से, माननीय मंत्री जी से भी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि आप भी आयें और मगध प्रमंडल को देखें । मगध प्रमंडल जिस तरह से सुखाड़ के चपेट में है, पानी के बिना लोग तरस रहे हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर आहर-नहर की सफाई होनी चाहिए । हम प्रेम से ही आग्रह करेंगे ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप कन्क्लुड करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, एक लाईन सिर्फ रह गया है, वहां पर बाराचट्टी भी है विधान सभा क्षेत्र, वहां पर भी एक दारो बांध है और माननीय मंत्री जी, जब आप देखेंगे

गया को, बाराचट्टी को, बोध गया को तो आपको तरस आयेगा वहां के लोगों को देखकर, यह हालात उत्पन्न हुआ है ।

.....क्रमशः....

टर्न-15/राजेश/4.7.19

श्री कुमार सर्वजीत : क्रमशः ... तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ मुंगेर जैसे हालात नहीं हों और आप जिस जगह से आते हैं, हम बहुत ही उम्मीद के साथ आग्रह किया हूँ मैं आपसे कि आईये गया की धरती पर, विष्णु की धरती पर और आकर देखिये और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाॅं पर इंसानियत मर चुकी है, तो कम से कम जगाने का प्रयास कीजिये, लोगों को पानी पिलाने का काम कीजिये, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करा दीजिये, हम इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री सुबोध राय, 10 मिनट ।

श्री सुबोध राय: सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग आज संयोगवश दोनों ही विभागों पर एक साथ चर्चा करने का मौका मिला है । सभापति महोदय जो प्रतिवेदन है,उसके आधार पर मैं भी कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर, रोडमैप के आधार पर, राज्य में जल संसाधन विभाग की ओर से और लघु जल संसाधन विभाग की ओर से जितने काम किये गये हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं और किसानों के हित में है लेकिन अभी भी हमारी कमियाॅं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार-बार यह कहते रहे हैं, वे जहाॅं भी गये हैं, वहाॅं भी उन्होंने कहा और चुनाव में प्रचार के दरमियान भी उन्होंने जनता के सामने इन बातों को रखा कि हमने बहुत काम किया है और एक-एक योजना के बारे में, एक-एक कामों के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने, दोनों ने ही अपनी बातों को जनता के सामने खुलकर रखा और यह भी बताया कि आगे हमें करना क्या है ? उन कमियों को पूरा करने के लिए और किसानों के दर्द को खत्म करने के लिए, उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए आगे क्या योजनाएँ हैं,उनपर भी प्रकाश डालने का काम किया । महोदय, हमारे दोनों विभागों ने अनेकों काम किये हैं, चाहे वह कैमूर का इलाका हो, चाहे वह भोजपुर का इलाका हो, चाहे वह उत्तर बिहार का इलाका हो या हमारे कहलगाॅव क्षेत्र का सवाल हो,बहुत सारे काम किये गये हैं, मैं इन कार्यों के लिए

अपने महान विभूतियों को जिन्होंने इस कार्य को सम्पन्न किया है, चाहे वह अधिकारी हों, मंत्री हो और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और जनता इन लोगों को और ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका दें, इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ । महोदय, लेकिन हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएँ हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में मैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो सुलतानगंज विधान सभा क्षेत्र है, सुलतानगंज विधान सभा क्षेत्र में हमारी कई योजनाएँ जैसे गंगा पंप नहर योजना से आपने बटेश्वर स्थान में काम करने का काम किया, इस बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करके आपने दिखाया है लेकिन हम आपको कहेंगे कि सुलतानगंज विधान सभा क्षेत्र में गंगा पंप नहर योजना वह बहुत ही छोटी योजना है, जो कमरगंज के क्षेत्र में है, उसको थोड़ा और विस्तृत किया जाय, तो इससे हजारों एकड़ जमीन किसानों की धान की जमीन सिंचित हो सकती है और बड़े पैमाने पर और उससे लाभ मिल सकता है, अभी उसमें पुराने जो तीन बड़े-बड़े पंप लगाये गये हैं, 60 एच0पी0 के, 50 एच0पी0 के और 20 एच0पी0 के, गंगा का जलस्तर जब ऊंचा होता है, तो उससे उस पानी से सिंचाई का काम होता है महोदय लेकिन उसके बाद के दिनों में वह सूखा रहता है, नाली भी जो बने हैं जो पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और ये पुराने जमाने के बने हुए हैं,उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और जो बड़े-बड़े हॉर्सपावर लगाये गये हैं,उसको और ज्यादा पावरफूल बनाना चाहिए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हर साल गंगा की बाढ़ से सुलतानगंज से ले करके बल्कि हम तो यह कहेंगे कि बक्सर से ही ले करके मुंगेर होते हुए और हमारा जो पूरा कन्सटिच्यूऐंसी जो है, उसके साथ 8 पंचायत से ले करके पूरा जो है कहलगॉव, भागलपुर, पीरपैती तक बड़ा ही जबरदस्त प्रभावित होता है गंगा के बाढ़ से, लाखों लोगों को घर से बर्बाद हो करके, तबाह हो करके, सड़कों के किनारे शरण लेना पड़ता है, कैंपों में शरण लेना पड़ता है और अरबों रुपये का सामान लोगों को हर साल राहत देना पड़ता है । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबों के सामने उन्होंने बराबर चर्चा किया है, यहॉ भी सदन में अनेक सदस्यों ने चर्चा किया है जल संचय की बात, वाटर हार्वेस्टिंग की बात, तो गंगा का पानी इतना बर्बाद होता है, हर साल गंगा का

पानी एन0एच0-80 को पार करके हमारे सुलतानगंज के पूरे इलाके में, रेलवे लाईन के उत्तर और दक्षिण हजारों बीघा किसानों के फसलों को बर्बाद करता है और लोगों के घर द्वार को भी बर्बाद करता है, अगर उस पानी के संचय का इंतजाम किया जाय, उसके लिए रिजरवायर बनाये जाये, बड़े-बड़े डैम बनाये जाये, तो हम समझते हैं कि उस पानी को लिन पिरिएड में किसानों के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई की भी बात पूरी हो सकती है । उसीतरह से हम आपसे कहेंगे कि हमने इस संबंध में आपके इंजीनियरों से बात-चीत भी की थी जो जल संसाधन विभाग के हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उपर से हम बड़े पाईप को ला करके इस काम को करेंगे, तो हमको काफी ज्यादा खर्च पड़ेगा लेकिन अगर हम इसको अन्डरग्राउन्ड कर दें, तो न तो यह किसानों की जमीन पर से गुजरेगी, न कोई क्षतिपूर्ति ही देनी पड़ेगी और कॉस्ट भी हमारा कम होगा और इससे हम बड़े-बड़े रिजरवायर बनाने में मदद भी मिलेगी, तो मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से कि आपको उन इंजीनियरों से सलाह-मशविरा करना चाहिए, हम माननीय मत्री जी को यह बात कहना चाहते हैं ।

अब हम लघु जल संसाधन विभाग के हमारे जो माननीय मंत्री जी है, उनसे हम कहेंगे कि हमारे इलाके की कई योजनाएँ हैं, जो वीयर के निर्माण से संबंधित है, क्षतिग्रस्त वीयर के जीर्णोद्वार का सवाल है, सभी का डी0पी0आर0 भेजा गया है और कुछ का सर्वे चल भी रहा है, तो हम माननीय लघु जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वे अपने इंजीनियरों को कहें कि वे इसमें जल्दी करें और वे इस साल जो वित्तीय वर्ष है, उसमें इस काम को पूरा करने का कहें । अंत में सभापति महोदय, हम कहेंगे कि तिलकपुर और हमारे किशनपुर पंचायत के लाखों एकड़ जमीन जो बाढ़ में डूब जाती है, तो इसके लिए रिंग बॉध बनवाने का काम जल संसाधन विभाग करें, साथ ही मंझली बॉध, हर साल जब बाढ़ आता है, तो उसमें बहुत ही भारी क्षति होती है, तो उसका भी सुदृढ़ीकरण का काम कराने का काम करें और जो भी योजनाएँ हमने विभाग में सौंपी हैं, उनको पूरी तरह से क्रियान्वित करने की कृपा करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-16/सत्येन्द्र/4-7-19

श्रीमती गायत्री देवी: सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

महोदय, जल ही बिहार की सबसे बड़ी सम्पदा रही है । हिमालय से आने वाली सैंकड़ों नदियां हमारे खेतों को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है और उन नदियों से आने वाली बाढ़ तबाही का सबब भी बन जाती है । जल संसाधन विभाग अपने कार्य क्षेत्र में विकसित सिंचाई क्षमता को सत्त बनाये रखने, सिंचाई क्षेत्र में लगतार वृद्धि करने संबंधी उपायों से प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने हेतु प्रयासरत है । महोदय, सरकार द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु 3790 कि0मी0 तटबंध का निर्माण कराया गया है जिससे 39 लाख 96 हजार हे0 क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो गया है साथ ही साथ आगामी पांच वर्षों में 1676 कि0मी0 अतिरिक्त तटबंध का निर्माण कर 23.16 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है । महोदय, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी के अगुआई में बिहार का विकास हो रहा है। सरकार युद्धस्तर पर तटबंधों के मजबूतीकरण एवं उसका निर्माण करा रही है जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले के अन्तर्गत अधवारा नदी के दोनों तरफ तटबंध, सुपौल जिला में पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिलान्तर्गत वागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-2, समस्तीपुर, दरभंगा एवं खगड़िया जिला के बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 4 सम्मिलित है । महोदय, गोपालगंज जिले के 14 प्रखंडों, सारण जिले के 20 प्रखंडों तथा सिवान जिले के 19 प्रखंडों में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु पश्चिमी गंडक नहर के एक लाख 47 हजार हे0 ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्स्थापन एवं 1 लाख 58 हजार हे0 में नया सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य किया जा रहा है । महोदय, सरकार द्वारा सतही सिंचाई योजना के अन्तर्गत आहर, पईन का सफाई एवं वियर का निर्माण कराया जा रहा है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल अगुआई में जल संसाधन विभाग किसानों के लिए सिंचाई और बाढ़ की विनाशलीला से बचाव हेतु कई बेहतरीन कार्य कर रही है जिससे राज्य के लोग खुशहाल हो रहे हैं, वहीं पर बाढ़ से कम से कम क्षति किसानों को हो सके, इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा कई सराहनीय कार्य भी किये गये हैं । महोदय, किसानों को खेती के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के बघेला गांव में वेलवा घाट के समीप, मोहीउद्दीन पकड़ी में टिकमा नदी पर गोरौल में, मधुबनी जिला के विहुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव, धौंस नदी पर वलवा ग्राम के निकट, सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखंड में

कहचरीपुर ग्राम के झीम नदी पर, परिहार प्रखंड के रजवाड़ा गांव में हरदी नदी पर लाखों हे0 में सिंचाई क्षमता के वियर और स्लुईस गेट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सीतामढ़ी जिला के बारे में कुछ कहना चाहती हूॅ । सोनवरसा प्रखंड में बन रहे कहचरीपुर ग्राम में स्लुईस गेट का निर्माण जो हो रहा है उसमें घटिया सामग्री से काम कराया जा रहा है, उसको देखवा लीजिये और सोनवरसा प्रखंड के रजवारा ग्राम में स्लुईस गेट से किसान को पानी नहीं मिल रहा है और परिहार प्रखंड के रजवारा गांव में 4 साल पहले वियर बनाने की स्वीकृति भारत सरकार से मिली हुई है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है । लघु जल संसाधन विभाग के ढील के कारण अभी तक रजवारा में काम शुरू नहीं किया गया है । सोनवरसा प्रखंड के बाकें नदी में बालू भर गया है जिसको उड़ाही करने की आवश्यकता है । उन सभी कामों की ओर मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूॅ कि इन कार्यों को अविलम्ब कराने हेतु विभाग को निर्देश देने की कृपा करेंगे । हमारे विधान-सभा के परिहार एवं सोनवरसा प्रखंड में 40 नलकूप में से 38 काम नहीं कर रहा है और खराब है । सीतामढ़ी में विशेष रूप से जल प्रवंधन की आवश्यकता है । महोदय, आज जो सरकार की उपलब्धि है वह हमलोगों के सामने है । इसके दो साल पहले जो बाढ़ आयी थी, जरूर आयी थी, इसके पहले भी आती थी और जितना काम हुआ है इस सरकार में उतना कभी नहीं काम हुआ था । मैं गर्व के साथ कहती हूॅ और मैं धन्यवाद देती हूॅ आदणीय मुख्यमंत्री जी को कि जितनी व्यवस्था इस सरकार में हुई है, उतनी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी । हमलोग के यहां भी दो साल पहले बाढ़ आयी थी और जो-जो सामग्री हमलोग खोजे वह उपलब्ध हो गया, कोई कमी नहीं था । हमलोग के क्षेत्र में सीतामढ़ी में परिहार विधान-सभा है और वह नेपाल की बोर्डर पर है वहां ऐसा बाढ़ आया कि घर में पानी घुस कर खिड़की से निकल रहा था उस समय जब हम परिहार के ब्लौक में फोन किया तो वहां जो सामग्री उपलब्ध था जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जैसे निकालना था आदमी को वह सारी व्यवस्था हो गयी, उसमें कोई कमी नहीं हुई थी। सभी आदमी या तो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, काम होता है सबका और काम सभी जगह हुआ है इस सरकार में तो कम से कम धन्यवाद तो आपलोग जरूर दीजिये । जो काम करता है, देहात में एक कहावत है कि जो काम करता है उसको ईनाम दिया जाता है तो हमारी सरकार काम की है तो बोलने का भी अधिकार है । अधिकार तो सबको है आज सभी लोग कहते हैं

देश में, अरे देश में क्या हुआ है हमलोग भी जाते थे, आप लोग भी जाते थे वोट मांगने के लिए और जब हमलोग प्रचार में निकालते थे तो हर घर से आवाज आती थी एक ही, ऊपर देखना है नीचे नहीं देखना है । हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग चालीस में चालीस सीट दे दिये है और अगली बार भी आदरणीय विकास पुरूष नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और जितना सीट हमलोग लोकसभा में दिये, उतना सीट हमलोग चुनाव जीतकर फिर देंगे और सिर्फ एकतरफा हमलोग रहेंगे । आज पार्लियामेंट में देख लीजिये, कोई विरोध में बोलने वाला नहीं है,वहां कोई विरोधी नहीं है, इसी प्रकार 2020 में यहां कोई विरोधी नहीं रहेगा । काम करने वाला को वोट मिलता है, सोने वाला को नहीं मिलता है । जब आदमी चुनाव हार के आते हैं तो आदमी के दिल में दर्द होता है और यहां ठेहुना में दर्द हो रहा है, यह क्या हो रहा है कि घुटना में दर्द होता है, अरे दिल दिमाग में दर्द होता है तो जनता ने जो दर्द दिया है, वह छूटने वाला नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

टर्न–17/मधुप/04.07.2019

श्री विजय प्रकाश : महोदय, आज हमें कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका आपके माध्यम से मिला, माननीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से हमें मौका मिला, इसलिये हम अपने दल के नेता और आपको सहृदय धन्यवाद देना चाहते हैं।

आज जो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार के विरोध में जो बोलने का मौका मिला है, आज बजट 30 अरब से पार किया गया है लेकिन इस बजट से पूरे बिहार को कोई लाभ नहीं हो रहा है । यदि लाभ होने का रहता तो हमलोगों को, आपलोगों को भी याद होगा कि देश में सबसे बड़े नेता किसान के आदरणीय चौधरी चरण साहब हुआ करते थे और हमलोगों के यहाँ के स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, क्यों जल के लिए, हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते थे ? आज एन0डी0ए0 की सरकार में बैठे लोग उनके सपनों को चूर-चूर करने का काम किया है, उनके सपने को आज अधर में डालने का काम किया । आज दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी और एन0डी0ए0 के लोग जिस तरह से हँसी-हँसी करके सवालों का जवाब देते हैं.... (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : संजय जी, बोलने दीजिये न !

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ, हमलोगों की पार्टी के बारे में बोल रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा न !

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी, आप अपनी बात रखिये ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, आदरणीय चौधरी चरण साहब कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गाँव और किसान के खेतों से होकर गुजरता है । बेहतर खेती के लिए बेहतर जल प्रबंधन की आवश्यकता है । जब हमारे देश के किसान खुशहाल होंगे, हमारे गरीबों के पेट में अन्न मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगा, यहाँ तो सुशासन राज में है कि खेत सूखा पेट भूखा । वाह रे सुशासन बाबू !

आज हम कोसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, महोदय, हमने बजट का अवलोकन किया है, बजट में पहला बाढ़ नियंत्रण और दूसरा सिंचाई व्यवस्था की योजना है । बाढ़ नियंत्रण तो स्वाभाविक रूप से जिस इलाके में बाढ़ आती है, कोसी का इलाके में आती है, उसके लिए बजट अधिक से अधिक, या तो पूर्ण भी दिया जायेगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिंचाई का, एकदम पूरे बिहार में नगण्य है । आप बजट उठाकर देख लें कि 80-85 परसेंट पैसा यदि कोसी में दिया गया तो पूरे बिहार में कितना पैसा दिया गया है? इसको देख लिया जाय । देखकर इसका उपाय किया जाय कि ऐसा क्यों ? जब मार्च में काम पूरा करने के लिए योजना बनाई जाती है तो जुलाई-अगस्त तक बाढ़ आने की संभावना रहती है । कभी-कभी तो अक्टूबर-नवम्बर से ही शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि जो योजनाएँ बनती हैं, वह लूटने के लिए, खसोटने के लिए, संवेदकों के लिए और सरकार में बैठे नुमाइंदे के लिए बनती हैं, जिनके माध्यम से लूट-खसोट करके खत्म कर दिया जाता है । हम सरकार से जानना चाहते हैं, हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि कौन ऐसे संवेदक जो कोसी और जल संसाधन विभाग में पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करने का काम करें । यदि काम सही हो रहा है तो उनको सदन के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया जाय, यदि एक काम को खतम करके फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी उसी योजना को तीन महीना, छः महीना के बाद यदि शिलान्यास करने के लिए फिर जाते हैं तो क्या कारण है कि वही संवेदक फिर काम करता है ? उसपर क्या कार्रवाई की जाती है ? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं । माननीय मंत्री नये आये हैं, अच्छे मंत्री हैं,

जिस जिला से आते हैं, वहाँ की भाषा भी एक ऐसी भाषा रहती है कि गले से लगा लिया जाता है, यदि अपशब्द भी बोलते हैं तो बड़े प्रेम से बोला करते हैं । इसलिए महोदय, इनसे आशा और उम्मीद जगा है क्योंकि पिछले मंत्री जी जो किये हैं वह तो पूरे बिहार में जग-जाहिर है । (व्यवधान) पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेल लगाने के बाद चिकना होता है, पॉलिश से चिकना नहीं होता है । (व्यवधान) इतिहास गवाह होगा कि आज तक यदि कोई कह देगा कि विजय प्रकाश भी टेन्डर करता है......

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : विजय प्रकाश जी, आसन की ओर देखकर बोलिये ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सिंचाई व्यवस्था को दुधारू गाय के रूप में राज्य सरकार यूज न करे । जहाँ जल की व्यवस्था करनी है, जहाँ बाँध बनाना है, वहाँ सिंचाई विभाग के माध्यम से सिर्फ लूट-खसोट करने का काम किया गया है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : अनावश्यक टिप्पणी न करें ।

श्री विजय प्रकाश : इसपर माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे कि इसपर ध्यान देने का काम करें कि यह काम कैसे होगा । कहावत है कि जब अरबो-अरब का नुकसान हो जाता है, कहा जाता है कि जब-जब कोसी हँसती है, जब-जब कोसी अठखेलियाँ लेती हैं, तब-तब बिहार की अवाम रोने का काम करती है । महोदय, आपके माध्यम से इसपर माननीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि इसपर सचेत होइये । हरेक साल जब-जब कोसी हँसती है तब-तब बिहार का अवाम रोने का काम करती है, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है । इसके बारे में कोई उपाय करने का काम कीजिये कि क्या कारण है कि अरबो-अरब का काम हुआ है फिर भी आज तक छः महीना के बाद वही स्थिति आती है ।

हम पूछना चाहते हैं महोदय, आपके माध्यम से कि नेपाल से बात हुई थी हाई-डैम योजना की 2000 में, उसका आज तक क्या हुआ ? सप्त कोसी उच्च बाँध पर जो वार्त्ता हुई थी, पत्रों से आदान-प्रदान सरकार से हुई थी भारत सरकार और नेपाल सरकार में, उसका संयुक्त कार्यालय कहाँ है ? अभी तो डबल इंजन की सरकार है । 2014 में, आपको मालूम होगा, तत्कालीन भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी के माध्यम से इस कार्य को किया गया था, उसका आज क्या हुआ ? विराटनगर, धरान, जनकपुर,

लाइजनिंग कार्यालय काठमांडू में क्यों नहीं अभी तक खुला ? डबल इंजन की सरकार है ! क्या बात है कि जो योजना 2014 में बनाई गई थी, वह योजना आज कहॉं है ? उसका कार्यालय कहॉं है, हमें बताने का काम आप करें । महोदय, आपके माध्यम से हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि कुसहा के प्रलयकारी दृश्य से हम सीख क्यों नहीं लेते हैं ? कहॉं है सुशासन का नियंत्रण ? हमें बतायें कि इतना बड़ा कुसहा में प्रलयकारी बाढ़ आती है, उसपर नियंत्रण नहीं होता है, यही सुशासन बाबू हैं, 15 सालों से लगातार कौन-सा ऐसा कार्य किये हैं, जरा-सा उस योजना को गिनाने का काम करें । अभी माननीय सदस्य एक बता रहे थे दुर्गावती के बारे में, हमें बता दें कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में, जगदानंद जी के समय में और उस समय राज्य-मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी हुआ करते थे, जिस समय दुर्गावती बना, उससे एक इंच भी आगे बढ़ने का काम किया है ? हमें बतायें । (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : बैठ जाइये । बोलने दीजिये ।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यगण खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । सभी बैठ जाइये न । माननीय सदस्य अशोक जी, बैठ जाइये । माननीय सदस्य विजय प्रकाश जी, आप आसन की तरफ देखकर बोलिये । माननीय सदस्य अशोक जी, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, आज पूरा बिहार सूखाग्रस्त है । आज किसानों के ऑंखों में ऑंसू है, खेत सूखा है, गरीबों का पेट भूखा है । (व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी जवाब में सारी बात को कहेंगे ।

श्री विजय प्रकाश : इसीलिए कहा जाता है -

जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ ।
मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे बैठ ।

आपको एक दिन ऐसा मौका आयेगा, किनारे बैठकर रोना पड़ेगा और आपको कोई जगह नहीं देने वाला है ।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अब हम अपने क्षेत्र के मामले पर आना चाहते हैं । हम बताना चाहते हैं कि एक

सुपौल का मामला है, माननीय सदस्य हमारे बताये कि सुपौल का मामला है और कोसी तटबंध के अन्दर एक परसा माधव एवं गौराहा पंचायत है.....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य क्यों बतलायेंगे ? आप आसन को कहिये न! माननीय मंत्री जवाब में अपनी बात कहेंगे ।

टर्न-18/आजाद/04.07.2019

श्री विजय प्रकाश : हम बता रहे हैं, हमने बताने का काम किया । गांव के लोग आपके सुशासन से तंग आकर और अपने आपको हीन भावना से ऊपर उठकर के 5 कि0मी0 गांव में बॉध बनाने का काम किया गांव के लोगों ने, पंचायत के लोग अपने से 5 कि0मी0 बॉध बनाने का काम किया । माननीय सिचाई मंत्री से इसके बारे में यही उम्मीद है कि वह 5 कि0मी0 जो स्वयं गांव के लोग बॉध बनाये हैं, उसको आप सुरक्षा बॉध दे दें, यही आपसे उम्मीद है क्योंकि पिछले वाले मंत्री जी तो कुछ दिये नहीं । आपसे उम्मीद है कि आप दे सकते हैं इसलिए देने का काम करेंगे । हम पूछना चाहते हैं 14 वर्षों में जिन नहरों का निर्माण सिंचाई विभाग से कराने का काम किया, उसकी जर्जर स्थिति है, टे-लैंड तक पानी नहीं पहुॅच रहा है, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप पूरे बिहार में बता दीजिए कि जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो योजनायें, जो नहरें, जो वितरणी जितनी दूरी तक पटवन कराने का काम किया है, उससे एक डेग भी आप बढ़कर बनाने का काम किये हैं तो बताने का काम कीजिए । मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूॅ कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो वितरणी पहले तक बना है, वही तक है, जो नहरें जहां तक बनी है, वही तक है, जो डैम जहां तक बना है, उसका सिलटेशन भी आप साफ करने का काम नहीं किये और आप बताते हैं कि हम सुशासन बाबू है, यह दुर्भाग्य है। आप सुशासन बाबू के नाम पर ढ़ोल पीटकर इस बार जीतने वाले नहीं हैं । इसलिए माननीय महोदय आपसे आग्रह है कि जो हाई डैम की स्थिति है, हम महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र और जिला से आते हैं, जिला जमुई और बॉका मुंगेर डैमों की राजधानी कहा जाता है और वहां पर डैम सब जर्जर है । हम धन्यवाद देते हैं महागठबंधन की सरकार को, जो 18 महीने के लिए हमलोग जिस सरकार में साथ थे, हमारे इलाके में पहली बार 15 सालों

के दरम्यान में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, तब से हमारे यहां दो-तीन डैम है, जिसको कुकुरडैम कहा जाता है, वहां पर हमलोग उस समय 39 करोड़ रू0 देने का काम किये । खड़गपुर झील में हमलोगों ने उस समय 81 करोड़ रू0 देने का काम किये । हमलोग दूसरे डैम में 41 करोड़ रू0 देने का काम किये, क्या 15 सालों में महागठबंधन सरकार के पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किये हुए थे तो एक रूपया भी जमुई एवं बॉंका जिले में देने का काम किये हैं क्या, हमें बताये आज लोग नाम लूट रहे हैं । सभापति महोदय, जब केन्द्र में राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी थे तो मोकामा के टाल में अरबों रू0 देने का काम किये, बटेश्वर नदी में जो करोड़ों रू0 देने का काम किये और उसका उद्घाटन राज्य के सिंचाई मंत्री करते हैं और कहते हैं कि चूहा खा गया इसीलिए बटेश्वर का नहर टूट गया, यह दुर्भाग्य है, यह लानत है, यह शर्म करने वाली बात है, इसपर सरकार को शर्मिन्दा होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ ? भारत सरकार से पैसा लाया हुआ उसको लूट-खसोट कर मजा मारने का काम करते हैं । कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर की घटना घटी, उसी तरह से कहियेगा कि देख लेंगे, यह दुर्भाग्य है । इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय को बताना चाहते हैं कि पूरे इलाके में नहर, पोखर का जो काम है, उसको देखने का काम कीजिए । हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि समस्तीपुर, विरौल, विरोली से पखरोडवा पहरेला बॉंध पक्कीकरण का कार्य 6 माह की अवधि में पूरा होना था । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको जो है, आप गहराई से लेने का काम करेंगे । 6 माह की अवधि थी इसको पूरा कराने का लेकिन लगभग 2 वर्ष हो गया है । सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, इसमें कौन से संवेदक हैं, वे किसी भी पार्टी के हों, उसपर कार्रवाई करने का काम कीजिए, हम यह बताने का काम करते हैं । माननीय मंत्री महोदय, सौभाग्य हमारा है कि सदन में माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री भी बैठे हुए हैं । यदि दोनों ईमानदार हैं, यदि दोनों काम करने वाले हैं तो हमें एक सप्ताह में इसका जवाब चाहिए, मैं सदन में सभापति महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सर्वे का पईन जो बहराईन गावं से काकन गांव तक जाती है और इसपर आज से 6 माह पहले आर0ई0ओ0 के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग से इसको भरकर रोड बना दिया गया है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ , माननीय मंत्री जी इसको आप संज्ञान में लीजिए । सिंचाई विभाग के एजक्यूटिव इंजीनियर कहां सोये हुए थे, कहां सोये हुए थे

आपके एस0ई0 और कहां सोये हुए थे आपके कमीश्नर, जिनके विभाग का पईन वर्षो-वर्ष से सर्वे में है लेकिन उसपर रोड बना दिया गया । आप दोनों एक-एक प्रति सर्वे का ले लीजिए, हम इसको लाये हैं, आप इसको देखवा लीजिए और जॉच करा लीजिए कि इस पईन पर क्यों रोड बनाया गया, क्यों अनियमितता बरती गई ? मेरे माध्यम से आपके विभाग में, आपके एजक्यूटिव इंजीनियर को 20 बार अपने पैड पर पत्र लिखकर भेजने का काम किया और वहां जाकर संवेदक कहा करते थे कि हम जो है उस अप्लीकेशन को खींच लिया हूँ, विभाग को पता नहीं चल पायेगा । यह दुर्भाग्य है, यह आपके लिए लानत है, इसको आप देखने का काम कीजिए । सदन के माध्यम से हम दोनों विभाग के माननीय मंत्री को देने का काम करते हैं, इसको लिया जाय और गहराई से देखा जाय । इसको हम सदन के पटल पर भी रखना चाहते हैं ।

सभापित महोदय, हम लघु सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या हुआ हमारे जल संरक्षण का, लघु सिंचाई का क्या हाल है, पूरा चौपट है । लघु सिंचाई में आज जिन कामों को होना था, आज आप देख लीजिए चेक डैम की क्या स्थिति है ? नलकूप की क्या स्थिति है, क्या कारण है कि आज व्यवस्था में खिंचाई हो रहा है । सिंचाई कम और माल खिंचाई अधिक हो रहा है । यही है सुशासन बाबू, यही है न्याय के साथ विकास, यही है सबका साथ और सबका विकास, पता चला कि संवेदक करोड़पति हो रहा है, अरबपति हो रहा है और सरकार के नुमाईन्दे करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं और आम लोग जो है, वह बदहाल और फटेहाल है, यह दुर्भाग्य है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय प्रकाश : हम एक मिनट और लेना चाहते हैं महोदय आपसे, जब आपको देखे हैं कि आसन पर बैठे हैं तो हमारा हिम्मत बढ़ा कि आप हमें दो मिनट टाईम अधिक देने का काम करेंगे ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आपकी नजर दूसरे तरफ चली जाती है, मेरी ओर देखें ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, हम पूछना चाहते हैं माननीय लघु सिंचाई मंत्री महोदय से कि हमारे जमुई जिला में लगभग 15 से 20 योजनायें चल रही है, जिसको हम रिकोमेंड करके देने का काम किये हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और जो तत्कालीन मंत्री को भी धन्यवाद देते हैं, हम पूछना चाहते हैं ....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए । आपकी बात विस्तार से आ गयी है, अब आप समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी ।

श्री ललन पासवान : सभापित महोदय, जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूॅ । मैं आपको बधाई देता हूॅ कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया । महोदय, पीने का पानी, जीने का पानी और खेतों का पानी, न कि हमारे लिए बल्कि सम्पूर्ण मानव और जीवों के लिए अतिमहत्वपूर्ण है । हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को कि जो बाढ़ और सुखाड़ जिससे पूरा बिहार जो 17 जिला था, वह आज 27 जिला में तब्दिल हो गया है लेकिन कुसहा भी जब टूटता है तो बिहार के बाढ़ पीड़ितों को अंतिम व्यक्ति तक उसका मुआवजा और राहत कार्य पहुॅंचाया जाता है । ...... क्रमशः ....

टर्न-19/ज्योति/04-07-2019

क्रमशः

श्री ललन पासवान : और दुर्गावती योजना भी भी लंबित रहती है 40-55 साल कौंग्रेस के शासन काल में और 15 साल शक्ति यादव जी के राज में लेकिन दुर्गावती नहीं बनी इसलिए मैं कह रहा था कि दुर्गावती योजना 15 साल शक्ति यादव जी के राज में और दुर्गावती में पानी नहीं दिए, पीने का पानी भी नही दिए । यह बात छोड़िये पशु और इन्सान दो घूट पानी के लिए तरसता था महोदय, और बिहार में जल संसाधन विभाग ने 2000 में और 2000 के पहले 90-95, 2000 में जो सिंचाई की क्षमता थी, चार पॉंच गुना बिहार में उसकी सिंचाई क्षमता बढ़ी । खड़े हो जाईये और आज जिस इन्द्रपुरी जलाशय.....

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): नहीं, नहीं, अपनी बात आप जारी रखिये, अप निदेशित नहीं करिये।

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान : ये लगे रहे इन्द्रपुरी बराज पर, पैरेलल नहर के सवाल पर । कई बार बैठक भी हुई थी ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । शांति से सभी लोग सुनिये ।

श्री ललन पासवान : पैरेलल नहर नीतीश कुमार की अगुआई में 600 क्यूसेक्स पानी की बढ़ोत्तरी इन्द्रपुरी जलाशय में जो टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता था, बक्सर टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम, पूरे नहर का निर्माण नीतीश कुमार और जल संसाधन वर्तमान सरकार के अगुआई में हुआ । यह 15 साल और 55 साल और सौभाग्य है कि आजादी के बाद मने इतने दिनों के बाद कदवन जलाशय परियोजना- तीन राज्यों का उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के दोनों पहाड़ को जोड़ने वाली, इससे 150-200 गांव विस्थापित होंगे । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रयास से गाड़ी लाईन पर चढ़ी हुई है । 160 फीट ऊंची, 450 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता मेरे ही कंस्टीचुएन्सी और मेरे नौहट्टा में मटिआंव में उसका निर्माण होना है इसलिए अशोक जी बता रहे थे 2020 में, मुझे भी जानकारी है कि अंतिम डी.पी.आर. का परिणाम अब आने वाला है । इसलिए, दरअसल कभी कभी जब गड़बड हो जाता है कि शक्ति यादव जी 22 थे और नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो हो गए 80 इसलिए जल्दी जल्दी छपियाते हैं, इसलिए इनको परेशानी लगती है कि आगे क्या होगा ? इसलिए सिंचाई मंत्री को और सरकार को हम कोटिश: बधाई देना चाहते हैं और सरकार ने कई परियोजनाओं का परिणाम चाहे वह कहलगांव का हो, चाहे बटेश्वर योजना हो, चाहे पंप नहर योजना चौसा हो कई स्वीकृत योजनाएं लंबित थी आजादी के लंबे दिनों से, जिस पर कभी कोई नजर नहीं डाला, उस पर जल संसाधन विभाग और माननीय नीतीश कुमार जी ने नजर ही नहीं डाला बल्कि उसको कार्य योजना में शामिल करने का शुरुआत किया । महोदय, मेरे यहां दुर्गावती की चर्चा कर रहे थे । 386 गांव, 1976 के 14 जनवरी का शुरुआत था, अवधेश बाबू की सरकार थी । उस समय जगजीवन बाबू सिंचाई मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में और उस समय से लेकर आजतक माननीय नीतीश कुमार के ही अगुवाई में उसका अंतिम परिणाम मिला। यह ठीक बात है कि पूरी तरह योजना पूरी नहीं हुई है लेकिन पानी मिलना किसानों को 386 गांवों का शुरु हो गया है । राईट कैनाल और लेफ्ट कैनाल दोनों में और वितरणी के बारे में हम माननीय मंत्री जी से कहना भी चाहेंगे कि पिछले दिनों दो कंपनियॉं टेण्डर निकाली गयी थी ब्लैक लिस्टेड हो गयी थी पुन: उसने कोर्ट से जीत लिया और उसको अवसर मिला था हंसराज को । हमारे 127 वितरणियों में पूरा वितरणी बन कर तैयार नहीं हुयी, टेल एंड तक पानी नहीं गया है और आग्रह करेंगें आपसे राईट और लेफ्ट कैनाल दोनों में नंदनवा

बन रहा है और आपने टेण्डर किया, विभाग ने किया है कि बार बार टूट जाता था और कई जगह गुप्ता धाम जाने वाले मार्ग में दुर्गावती में कई पुल पुराने पुल हैं पहले से बने हुए थे, चाहे विश्रामपुर- मोहम्मदपुर के रास्ते में पचावरा वाला घाट में और पर्यटक लाखों लाख पर्यटक, सावन शुरु हाने वला है उधर जाते हैं लेकिन वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको बनवाने का काम करें । अभी 32 करोड़ का टेण्डर विभाग ने निकाला है जो ताराचंडी से लेकर अंतिम छोर कैमूर का आखिरी एंड तक जहॉ सड़क आप बना रहे हैं उसपर थोड़ा नियंत्रण रखें और देखें कि बढ़िया से बन जाय कि दुर्गावती जलाशय बहुत ही महत्वपूर्ण हमलोगों के लिए लाईफ लाईन है, नहीं तो सुखाड़ और मुआर काटते काटते और दो घूंट पानी के लिए तरसते तरसते लोग तंग और तबाह रहे हैं आजादी के 70 वर्षो में इसलिए उस पर हम कहना चाहते हैं कि वितरणी यथाशीघ्र बन जाय और जो बन रहा है उसपर जरा निगरानरी हो कि अच्छे से बना दिया । गाराचौबे एक नहर जाती है जो हमलोगों को जाकर जोड़ती है कैमूर जिला को, मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से पहले भी मिला था और आपको जरुर लिखकर नहीं दिया था लेकिन अरुण बाबू कमीशनर बैठे हुए हैं तो उनको जरुर हमलोगों ने कहा था कि ये वितरणी जाती है गाराचौबे, यह दो जिलों को जोड़ती है और इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि अगर आप बना भी रहे हैं पक्का यहॉ से नौबतपुर वाली आपने पक्की सड़क बनायी है और गाराचौबे को अंतिम छोर तक अगर वह बन जाता तो वह दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क है। हमलोग न्योता वगैरह पुराने जाते हैं वह इतनी खराब हो गयी है । हम आग्रह करेंगे कि उसको आप बनवा देते । मेरे यहॉ कसेरुआ पंचायत है सासाराम प्रखंड के अंतर्गत वह आता है खैरागांव का हमारा चार पुल आप बनवाये हैं । विभाग ने बनाया है लेकिन खैरा पुल कभी भी टूट जायेगा तो वहॉ आने जाने का एक सौ गांव का, दरिगांव बाजार में जाने का रास्ता है कसेरुआ पंचायत का खैरा पुल उच्च स्तरीय नहर पर हम आपसे आग्रह करेंगे । खुरमाबाद राजवाहा की सफाई हो जाती मलवाड़ रजवाहा की सफाई का हम आपसे आग्रह करेंगे और महादेवा जलाशाय और मगरदा जलाशय के लिए लघु सिंचाई मंत्री से आग्रह करेंगे कि महादेव जलाशय सासाराम का बहुत पुरानी नदी आती है पहाड़ से वह लंबित है वह बन जाता तो कम से तीन से चार हजार कहा जा सकता है तीन चार हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती महादेवा जलाशय से और बहुत छोटी योजना थी जो आज बड़ी हो गयी है । हम इसके लिए क्वेश्चन भी डाले थे। मगर 1962 में हमारा जन्म भी

नहीं हुआ था मगरदाह नौहट्टा में डैम बना हुआ है लघु सिंचाई विभाग से वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : आग्रह हम आपसे करेंगे कि बनवा दीजिये और दूसरा आग्रह हम कहेंगे कि हमारे यहॉ कई नदियॉ नौहट्टा, रोहतास और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हमारे यहॉ सोन एक तरफ कैमूर पहाड़ी है, दूसरी तरफ सोन नदी नीचे बहती है जहॉ कोई सिंचाई का साधन नहीं है । माननीय नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचायी है पहाड़ से लेकर नीचे तक और बिजेन्द्र यादव जी माननीय मंत्री ने ..

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): अपनी बात समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान एक मिनट में बस महोदय। पूरे कटाव से लिफ्ट एरीगेशन बंद हो चुका है । पहले लगता है कि 1980-85 में चल रहा था, लिफ्ट एरीगेशन हो जाय, कोई नहर नहीं है सिर्फ बिजली पर सिंचाई है और कई जगह महादेवा जलाशय परियोजना, बगल में महादेवा डैम बन जाय और टिटिहरी नदी पर परछा के पास है चेक डैम बन जाता और कोरियारी गांव के पास अवसान नदी पर बन जाता तो उन इलाके में जहॉ पर बिजली पर सिंचाई होती है, वनवासी और आदिवासी के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता क्योंकि सोन नदी के बगल में जो कटाव का गांव है अगर सुरक्षा दिवार नहीं आपने बनाया तो हमें लगता है अगर जिस तरह से पिछली बार आयी थी बाढ़ अगर आयी तो रसूलपुर, नारायण चक, अकबरपुर से लेकर यदुनाथपुर तक लगता है कि पच्चास गांव कभी भी सोन के गोद में जा सकते हैं । हम आपसे सुरक्षा की मांग करते हुए जो इस विभाग की मांग है उसका समर्थन करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ, 9 मिनट ।

श्री सिद्धार्थ : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहॉ पर बोलने का अवसर दिया । कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर मिला है । ईश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की तो उसने 70 प्रतिशत से भी ज्यादा पानी दिया, विकसित शरीर में भी 60 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है ।

क्रमशः

टर्न-20/04.7.2019/बिपिन

श्री सिद्धार्थ : क्रमशः बिहार की आबादी में 80 प्रतिशत् से भी ज्यादा लोग सीधे-सीघे कृषि पर आधारित हैं और कृषि के लिए सबसे आवश्यक चीज है सिंचाई । आज पूरे विश्व

की आबादी करीब आठ अरब है और आगे आने वाले 20 से 30 वर्ष में 2050 में 10 अरब हो जाएगी । जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील मुल्क हैं पानी की खपत बहुत ज्यादा है और वर्तमान सरकार सड़कों के निर्माण में ज्यादा और नहरों के निर्माण में कम ध्यान दे रही है । बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सड़क के निर्माण में ज्यादा बजट दिया जा रहा है, नहरों के जीर्णोद्धार और निर्माण में और पक्कीकरण में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है ।

आज पटना जिला में पटना कैनाल में समय से पानी नहीं मिलने के कारण हजारों एकड़ भूमि का जो फसल है वह हर साल बर्बाद हो जा रहा है । पटना जिला जो कि बिहार की राजधानी है वहां की यह स्थिति है । इंद्रपुरी बराज के पूर्वी छोर बगदाद लक से होते हुए पटना ग्रामीण इलाकों में जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए वह करीब दो हजार क्यूसेक सप्लाई होनी चाहिए पटना जिला में और बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि मात्र 800 से 900 क्यूसेक पानी आज ग्रामीण पश्चिम पटना इलाका में सप्लाई किया जा रहा है । यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आज क्या जल संसाधन विकास विभाग के नजर में पटना जिला नहीं है ? हजारों एकड़ भूमि का फसल किसानों का जो साल भर मेहनत करके जो प्रयास करते हैं वह पालीगंज प्रखंड, बिहटा प्रखंड, बिक्रम, नौवतपुर प्रखंड, फुलवारी प्रखंड मनेर प्रखंड में उचित मात्रा में पानी भी नहीं जा पा रहा है, आधा भी पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है । पिछले सबार भी मुझे अवसर मिला था, इस बात को मैंने कहा था कि अरवल के पास सोन कैनाल से एक हजार क्यूसेक पानी अगर लिफ्ट कर दिया जाए और पटना ग्रामीण पश्चिम इलाका में एक लिफ्ट मशीन बना दिया जाए तो निश्चित रूप से किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है उसको रोका जा सकता है । सड़कों के पक्कीकरण में हजारों-हजार करोड़ रूपए सरकार के पास है ढोल पीटा जा रहा है कि हजारों यह सड़क बना दीजिए, वहां बना दीजिए और क्या इस नहर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं है ? क्या आवश्यक नहीं है कि पिफ्ट मशीन बनाया जाए और पटना जिला को उचित मात्रा में पानी दिया जाए । हजारों हजार एकड़ जमीन का जो फसल बर्बाद हुआ है उसे बर्बाद होने से रोका जाए । क्या यह चिंता का विषय नहीं है ? आज आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि पटना जिला सबसे ज्यादा उपेक्षित जिला रहा है जल संसाधन विभाग के द्वारा । औरंगाबाद हो, गया हो, हर जगह कुछ-न-कुछ योजना दे दिया गया लेकिन पटना जिला में यही माना गया कि पटना जिला का मतलब पटना टाउन होता है । पटना ग्रामीण पटना जिला में लोगों के नजर नहीं आया । शहर में रहने वाले लोग को पीने के पानी की समस्या है और गांव में

रहने वालों को खेती से लेकर नहाने से लेकर हर काम के लिए पानी की आवश्यकता है । आज यह स्थिति हो गई है पटना पश्चिमी ग्रामीण में कि जल स्तर इतना नीचा हो गया है कि पीने के पानी की भी उपलब्धता नहीं है । एक्कीसवीं सदी में विकास का कितना भी ढिंढोरा हमलोग पीट लें यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आगे हाने वाले समय में जिस जमीन के लिए लड़ाई होता था और हत्या होता था पानी पीने के लिए झगड़ा हो रहा है और मारामारी हो रहा है । साफ पानी तक मुहैय्या नहीं करवा पा रहे हैं हमलोग बिहार की राजधानी पटना ग्रामीण में । बहुत यही उदासीन है जल संसाधन से लेकर लघु सिंचाई या पी.एच.इ.डी. किसी भी विभाग का ले लीजिए तो पूरे पटना ग्रामीण में बहुत उदासीन रवैया है । जितने भी नलकूप है हमारे पटना ग्रामीण इलाके में सारे-के-सारे बंद हैं । मोटर खराब हो गया उसके लिए पैसा नहीं है, स्टार्टर बिगड़ गया उसके लिए पैसा नहीं है । पूरे मेंटेनेंस करने के लिए भी सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है । आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी बहुत ही आवश्यक चीजें हैं हमारे क्षेत्र के जो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । पूरा पटना पश्चिम इलाका खेती प्रधान, सिंचाई प्रधान इलाका है । एक आर. पी. चैनल-4 है जो कि जीतन छपरा से जमालपुर तक जाता है । मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी नहर उराही कराकर इसका पक्कीकरण करा दिया जाए । आज यह नहर की यह स्थिति है कि जहां कि भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ थी वह नहर आज जंगल बन गया है । दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है नौवतपुर लक से मंझौली वितरणी का । इसका भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नहर उराही करके इसका पक्कीकरण करा दिया जाए । बटाने दाया मुख्य नहर एवं उसके वितरणियों के द्वारा जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत भी अभी तक उसकी राशि स्वीकृत नहीं हुई है । इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि कृपा करके इसकी स्वीकृति दे दिया जाए । पूरे बिहार में प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत सभी जिलों में कई तरह के योजनाओं का डी.पी.आर प्राप्त होने के उपरांत भी एक भी जिला में योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है । निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इसे स्वीकृति दी जाए कि आगे काम बढ़ सके । कुटुम्बा प्रखंड के जमीन्दारी बांध का भी जीर्णोद्धार का काम और...

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री सिद्धार्थ : उसके वितरणियों का भी उराही नहीं होने के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पर रहा है । आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इस

समस्या का भी उपाय ढूंढा जाए । मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

सभापति : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम । दो मिनट ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आभारी रहूंगा ।

महोदय, मैं जितनी बातें कहूंगा, उन बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, मंत्री जी को जो कहना है और जो करना है, वही होगा । आज बिहार ही नहीं, पूरे देश में जल संकट गहरा गया है । बिहार के बहुत सारे गांव हैं जहां पानी का तल नीचे चला गया है और चापाकल बंद हो गया है । कहीं बहुत सारी नदियां सूख गई है। पहली बार सिवान में झरही नदी सूख गया है । ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि संकट गहराता जा रहा है लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि सरकार अपने हाथ अपनी पीठ भी थपथपा रही है । इसकी चिंता नहीं है कि यह संकट गहरा रही है तब कहीं-न-कहीं हम फेल्योर हैं । इसीलिए मैंने कहा कि मैं कुछ भी कहूंगा, समय काफी कम हो गया है, मुझे उम्मीद थी कि समय हमको मिलेगा । मेरे क्षेत्र में मैरवां प्रमंडल में नहरों का टेंडर वर्ष 2014-15 में हुआ महोदय कि सभी नहरों को कंक्रीट किया जाए और 2014-15 से आज 2019 हो गया महोदय लेकिन उसपर काम मात्र सात प्रतिशत हुआ है । अब आप इससे विचार कर सकते हैं कि यह सरकार किसान के प्रति कितनी चिंतित है । किसान त्राहिमाम कर रहा है । खेतों को पानी नहीं मिल रही है । आज लोगों ने मौसम के रूख को देख कर बिचड़ा भी नहीं डाल रहे है, इसलिए कि नहर में पानी है ही नहीं और बारिश की संभावना नहीं है । अब जो किसान इस साल धान नहीं लगाएगा, उसकी आमदनी दोगुनी होगी या कि उसकी संकट दोगुनी होगी, यह जांच उस समय होगा जब समय आएगा ।

सभापति : अपनी बात को कंक्लुड कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, मैं कंक्लुड कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखा जाए । हमलोग संख्या बल में कम हैं और सबसे छोटी पार्टी हैं, इसलिए समय थोड़ा रहना चाहिए, इसपर ध्यान रखा जाए ।

सभापति : कंक्लुड करिए ।

श्री सत्यदेव राम: तो यह हालात है । अभी ...

सभापति : समाप्त करें ।

टर्न : 21/कृष्ण/04.07.2019

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, लघु सिंचाई योजना के तहत मैं कहना चाहाता हूं कि जो भी उद्वह योजना चली थी, महोदय, ट्यूब-वेल मेरे यहां लगभग 25 है लेकिन 25 में से मात्र 3 ही चालू है और वह भी हफ्ता में मात्र एक दिन ही चलता है । महोदय, सुन लिया जाय ।

इसका जवाब सरकार को देना चाहिए । हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग पर सरकार विचार करे ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आप की बात आ गयी, अब आप समाप्त करें ।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, दो मिनट का समय है, इसलिए मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र गोविंदगंज के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र का 75 से 80 प्रतिशत नहर से जुड़ा हुआ है । मैं सरकार के मुखिया, सरकार के मंत्री और सरकार के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उस तेजपुरवा वितरणी का जितने भी सड़े हुये गायब फाटक का तीन-चार दिन दुरूस्त कर दिया गया है, उसके लिये मैं पदाकारियों और सरकार के मुखिया को बधाई देता हूं ।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तेजपुरवा जो वितरणी है, उसमें बहुत साल पहले करीब 2003 के आस-पास एक बार नगदाहा और सखवा गांव का तटबंध टूटा था और उसके बाद एक रिंग बांध बना, जो नहर के एक साईड में बांध दिया गया है, 50-60 फीट इधर और 50-60 फीट कुछ दूरी पर नहर को बंद कर दिया गया है । उसके लिये मैंने कई बार सदन में भी इस बात को उठाया हूं, परन्तु दुर्भाग्य से वह नहर चालू नहीं हुआ है, जिससे करीब डेढ़ से दो दर्जन गांवों में नहर का पानी नहीं जा रहा है, करीब दस साल से पन्द्रह साल से पानी नहीं जाने के कारण लोग नहर का अतिक्रमण भी कर रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नगदाहा तटबंध जो टूटा था और वहां जो रिंग बांध बांधा गया था, नहर को चालू करवा दिया जाये और मेरे विधान क्षेत्र में जो तेजपुरवा वितरिण है, उस नहर का अगर पक्कीकरण करवा दिया जाय, जो हमेशा टूट जाता है, जिससे उसमें पानी कम छोड़ा जाता है, मेरे विधान सभा का सौभाग्य है कि अगर नहर में पानी रहेगा तो वहां पर सूखे की उतनी समस्या नहीं रहती है । लेकिन वहां पर पिछले कई वर्षों से

पटवन में किसानों को दिक्कत हो रही है । नये मंत्री हैं, मैं इनसे पूरा विश्वास रखता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस को जल्द से जल्द चालू करा दिया जाये और नहर को जैसे गोपालगंज जिला के बगल में जैसे पक्कीकरण करा दिया गया है, मेरे यहां भी नहर को पक्कीकरण करा दिया जाये क्योंकि वहां पर कम पानी में भी किसानों के खेतों की अच्छी पटवन हो सकती है ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री राजू तिवारी : एक मिनट और दिया जाय । मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनरेगा के द्वारा बहुत सारे नहरों की सफाई होती है । अगर विभाग से तालमेल करके मनरेगा के तहत नहर के झाड़,बाधक चीजें आदि की सफाई करवाते भी है तो पटवन की व्यवस्था दुरूस्त हो जायेगी । आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र की नहर की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद । 5 मिनट में आप अपनी बात कहकर समाप्त करेंगे ।

श्री शमीम अहमद : माननीय सभापति महोदय, आज मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग के विरोध में और कटौती प्रस्ताव पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आज जब हमारे इस बिहार राज्य में 2017 में जब बाढ़ आयी थी, जिससे लगभग 3000 करोड़ का नुकसान हुआ था, लगभग 200 इंसान मारे गये और लगभग 650 पशु मारे गये और कितने के घर को नुकसान हुआ और फसलों की कितनी बर्बादी हुई । लेकिन बाद में हम फिर सुस्त पड़ जाते हैं । बाढ़ के बाद हमारे पदाधिकारी, हमारा विभाग और हमारी सरकार सो जाती है कि चलो हम बाढ़ से रक्षा, सुरक्षा कर लिये । लेकिन हम कोई नीति नहीं बना पाते । हमे तय करके चलना पड़ेगा कि हर साल जून और जुलाई माह में बाढ़ का आना लगभग तय है और जब कभी नहीं आया तो उसका हम इंतजार नहीं करें । हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए । महोदय, चूंकि समय बहुत कम है, जिस तरह के नुकसान बाढ़ से हो रहे है और हम कह रहे हैं कि हमारा बिहार विकास कर रहा है लेकिन सिर्फ रोड बन जाने से बिहार का विकास नहीं हो पायेगा । आज भी यहां के 80 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं और आप किसानों के लिये इतना कम बजट लाकर आप उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं । घटाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं ।

इसीलिये हम कटौती का प्रस्ताव लाकर चेतावनी दे रहे है कि जिस तरह आप सड़कों की योजनायें में राशि बढ़ा रहे हैं, उसी तरह इस में भी राशि बढ़ाकर किसानों के हित में कार्य करें ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस विभाग को दो भागों में बांटा गया है -कृषि विभाग और बाढ़ नियंत्रण । जब यहां सुखाड़ होता है तो हमारे सारे खेत सूखे रहते हैं, कहीं से पानी खेतों को नहीं मिल पाता है । महोदय, हमारे क्षेत्र में इनरवा दोन से पानी आता है जो छोड़ादानों से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है । जब बाढ़ आती है तो वह बाल्मीकी नगर से इनरवा होते हुये आता है जिससे टोटल नहर ध्वस्त हो जाता है और नहर का पानी बर्बाद हो रहा है । हमारे यहां तियर नदी है, वहां पर पहले डैम था, जो बाढ़ से ध्वस्त हो गया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वहां पर डैम बनाकर मधुबन कैनाल, लखौरा वितरणी कैनाल, ढाका कैनाल को पानी दे करके वहां के खेतों को सिंचित कर सकते हैं ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि बाढ़ आने के पूर्व हमारा प्लानिंग होना चाहिए । जब बाढ़ आती है तो आने-जाने का रास्ता नहीं रहता है जिससे वहां पर एन0डी0आर0एफ0 की टीम वहां नहीं पहुंच पाती है, वहां पर मेडिकल की टीम नहीं पहुंच पाती है । इसलिए बाढ़ आने से पहले उस एरिया को चिन्हित करके वहां पर एक ऊचां रोड बनाया जाय, जिससे लोग वहां पर बाढ़ के दिनों में पहुंच पाये । वहां पर डाक्टर और दवा आदि की व्यवस्था पहले से किया जाय, वहां हॉस्पीटल्स हो और वहीं पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना करके वहीं से नियंत्रित करने का काम करें ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें । महोदय, जब बाढ़ आती है तो हम मवेशियों के लिये हम कुछ नहीं कर पाते हैं । जब बाढ़ आती है तो मवेशियों के लिये चारा नहीं मिल पाता है तो वहां पर पहले से पशु चारा की व्यवस्था की जाय ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप समाप्त करें ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों के अगल-बगल में जितने भी गांव हैं, उन गांवों में मजबूत बेडवार बनवा दिया जाय क्योंकि जब बाढ़ आती है तो वह गांव का अस्तित्व ही खत्म कर देता है ।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बंजरिया प्रखंड है जहां पर पांच जगह बेडवार की स्वीकृति मिली लेकिन निधि की कमी की वजह से उसको छांट दिया गया । महोदय, इस विभाग में एक बाढ़ निरोधक टीम बनायी गयी । मैं देखता हूं कि जब पानी ज्यादा हो जायेगा तो बोरे में बालू रखकर वहां डाले जाते हैं जो एक लूट खसोट की योजना है । इसलिए इस योजना को खत्म करके पहले ही चिन्हित कर लिया जाये, जहां पर हर साल कटाव होता है या कटाव होने की संभावना है, उन जगहों को हम पहले से ही मजबूत कर लें जिससे उस गांव का अस्तित्व खतरे से बाहर रह सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

टर्न-22/अंजनी/दि0 04.07.19

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री राजीव नंदन, आपका समय पांच मिनट है।

श्री राजीव नंदन : सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के लिए पेश जल संसाधन विभाग में विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जल संसाधन विभाग की जब चर्चा होती है, बरसात का समय आता है तो बिहार दो भाग में बंट जाता है । हमारा उत्तरी बिहार पानी से डूबा रहता है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ का डंस झेल रहा होता है । हम क्या अपने पानी को जिस क्षेत्र में हमारा बाढ़ है, उस पानी को क्या हम दक्षिणी बिहार में गया, नवादा, औरंगाबाद जिन क्षेत्रों में सुखाड़ है, उस क्षेत्र में ले जा सकते हैं क्या ? हमारा क्रुड वायल, जिसे पेट्रोलियम पदार्थ का क्रुड वायल हम दो हजार किलोमीटर से, अरूणाचल से लेकर बरौनी तक ला सकते हैं तो हम तीन सौ किलोमीटर, चार सौ किलोमीटर कोसी का पानी, गंगा का पानी जो बरसात के समय में प्रचुर मात्रा में रहता है तो उसको दक्षिण बिहार में जैसे गया है, नवादा है, जहानाबाद है, जमुई है, बांका है, मुंगेर है, इन जिले के सारे लोग सुखाड़ को झेलते है, तो उस पानी को यहां नहीं लाया जा सकता है ? क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं ? इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने जो बजट लाया है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था है, बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था है, हम तो अगली बार से इस बजट में चाहेंगे कि जल संरक्षण की भी व्यवस्था हो, प्रदूषण

नियंत्रण की भी व्यवस्था हो, हमारी नदियों में गटर के नालों का पानी बेतहासा गिराया जा रहा है, जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, क्या हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं और सरकार जो काम कर रही है, जिस क्षेत्र में जल है, उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, वह सराहनीय हैं लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में पानी, बरसात के समय में देखने के लिए नहीं मिलता है, पीने के लिए नहीं मिलता है, उन क्षेत्रों में बांध की आवश्यकता है । हमारे यहां चारू पहाड़ है, गुरवा और औरंगाबाद के बीच में पड़ता है, वहां पर 20 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ है, उस पहाड़ के वर्षा का पानी ऐसे ही नालों में बह जाता है । अगर हम तीन सौ मीटर का बांध वहां बना दें, हथिया दह नाला से जो पानी बहता है, पांच वर्ग किलोमीटर का पानी इसी तरह से निकल जाता है । प्रस्ताव पिछली बार भी आया था, हमारे प्रश्न पर वहां गया हुआ है लेकिन वन विभाग का अड़चन आ गया है तो क्या हम इस सदन से चर्चा करके उन नियमों को शिथिल करके जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं । कृषि के लिए हम कर सकते हैं । इन सब विचारों पर हमें आना चाहिए । अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने 1972 में आज से 45-46 साल पहले नोर्थ कोयल परियोजना प्रारंभ किया, पुनपुन परियोजना प्रारंभ किया, उसका क्या हुआ हश्र ? 45 वर्षों के बाद वह लूट का अड्डा बना रहा और आपने किसानों के हित को 50 सालों तक पीछे ले गये । आपको नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने इन 45 वर्षों के बाद किसानों के लिए सोचा और नोर्थ कोयल परियोजना और पुनपुन परियोजना को पहली बार रखा है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राजीव नंदन : यह किसानों के लिए बात है, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, बांका के बारे में बोल रहे थे, हनुमना डैम में आपने क्या किया, हनुमना डैम से हमारा हजारों एकड़ जमीन सिंचित होती थी....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अपनी बात समाप्त करेंगे राजीव जी ।

श्री राजीव नंदन : हनुमना डैम में एक दिन में सात-सात हत्यायें हुई और आज के बाद वह पर्यटन स्थल वीरान स्थल में बन गया । किस समय हत्या हुई थी ? याद है वह समय ?

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य राजीव जी, आप अपनी बात को समाप्त करें। आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री राजीव नंदन : हत्या करनेवाले पर कानूनी कार्रवाई होगी । हमारी सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी । हत्या में वे लोग शामिल नहीं हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और उस समय में हत्यायें वहां होती थी, जो लोग सरकार का अंग हुआ करते थे और सरकार के संरक्षण में हत्यायें होती थी ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : राजीव जी, आप अपना भाषण समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । आपका समय दो मिनट है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे बहुत कम समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । धन्यवाद इसलिए कि आज जल संसाधन विभाग पर चर्चा चल रहा है और पक्ष और विपक्ष के लोग, पक्ष एक तरफ सरकार की तरफ बात कर रहे हैं और विपक्ष आंख मूंदकर विरोध में बात कर रहे हैं । हम कहना चाहते हैं कि बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभाले थे और उसके पहले जब इस विभाग का नाम लोग जानते थे तो लूट जल संसाधन विभाग के नाम से जाने जाते थे । लूट होता था, बाढ़ आता था, बिना तटबंध दिये हुए उसके पैसे निकाले जाते थे । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में तटबंध को मजबूत करने का काम किया गया, तटबंध को सुदृढ़ करने का काम किया गया ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति-शांति । टोका-टोकी न करें । माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : और इतना ही नहीं, बिहार का चाहे गंगा नदी से पार करनेवाला हो, चाहे कोसी नदी हो, चाहे फल्गू नदी हो, सभी के तटबंध को मजबूत करने का काम किया गया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं । बधाई इसलिए कि आज बिहार में जिस तरह से सात निश्चय बना, उसी तरह से कृषि रोड मैप में 12 निश्चय में जल संसाधन विभाग को शामिल किया गया ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप अपने भाषण को कनकलुड करेंगे ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : आज जल संसाधन विभाग के बदौलत किसानों के समृधि को बढ़ाने का काम किया गया । अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ । जल संसाधन विभाग ने नालन्दा और हमारे क्षेत्रों में खासकरके चाहे मालीसार योजना का सवाल हो या ...

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : चाहे वह उदेरा स्थान का सवाल हो, चाहे मंडई वीयर का सवाल हो, चाहे रारल वीयर का सवाल हो, चाहे इस्लामपुर तेलहारा वितरणी का सवाल हो, सभी नहरों को पक्कीकरण करने का काम किया गया है.....

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करेंगे माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : और हम कहना चाहते हैं कि जो बचे हुए काम हैं चाहे वी0एल0स्कीम भारथुनन्दना हो, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि बी0एल0स्कीम भारथुनन्दना को पक्कीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के इस जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । मैं हृदय से अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक सुशील कुमार मोदी जी का मै हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सदन में मुझे बोलने का मौका मिला । महोदय, ज्यादातर नदियां हिमालय से निकलती है और हिमालय की गोद से निकली हुई नदियां ज्यादातर गंगा, यमुना, गोदावरी, गंडक, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, मंदाकिनी कई एक ऐसी नदियां हैं, जो प्रायः हिमालय से गुजरती है ।

अध्यक्ष : विद्या सागर जी, आपके पास समय था एक मिनट । आप नर्मदा, कावेरी में फंसियेगा तो बिहार की नदी पर कब बोलियेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : बोल लेता हूँ श्रीमान् । हमारे यहां परमाण नदी है ।

अध्यक्ष : तो आप परमाण नदी की न बात कीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : वर्तमान समय में महानंदा श्री फेज का जो बेसिन के लिए पैसा देने की बात थी और 800 करोड़ रूपया की स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी, इसमें रिंग बांध बनाना था...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : उस योजना का क्या हुआ, यह मैं सदन से जानना चाहता हूँ । मेरा सीताधार एक चैनल है, सीताधार नदी कभी इस जमाने में बहा करती थी । मैंने पिछले विधान सभा सत्र में तारांकित प्रश्न के द्वारा इस बात को उठाया था कि उस नदी का पूरा अतिक्रमण हो गया है । इसके बावजूद भी जो निगरानी टीम गयी, जांच की और जांच संतोषप्रद नहीं रहा । मैं चाहूंगा कि पुनः एक बार सीताधार का जो अतिक्रमण हुआ है, उसका एक बार पुनः निरीक्षण कर लिया

जाय और अतिक्रमण मुक्त करके सीताधार को फारवीसगंज जैसे शहर में मेरे विधान सभा शहर को बाढ़ से मुक्त किया जाय ।

... क्रमशः.....

टर्न-23/राजेश/4.7.19

श्री विद्यासागर केशरी, क्रमशः महोदय, इसके साथ ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग से जितना भी रोड बना है, कम से कम उसका मरम्मति करा दिया जाय, मैं सदन से और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन समय नहीं है, मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्षः अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस बहस में हमारे माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी, निरंजन कुमार मेहता जी, अशोक कुमार सिंह जी, राजेश कुमार जी, कुमार सर्वजीत जी, सुबोध राय जी, श्रीमती गायत्री देवी जी, विजय प्रकाश जी, ललन पासवान जी, सिद्धार्थ जी, सत्यदेव राम जी, राजू तिवारी जी, शमीम अहमद जी, राजीव नन्दन जी, चन्द्रसेन प्रसाद जी और विद्यासागर केशरी जी ने अपने-अपने विचार रखे और जो इन्होंने सुझाव दिया, वह निश्चित रुप से महत्वपूर्ण सुझाव हैं और जो भी इसमें विभाग को या हमें टेक-अप करना हमलोग इसको करेंगे, जो भी इसमें इनिसिएटिव लेना होगा, निश्चित रुप से उसको हमलोग लेंगे । माननीय सर्वजीत जी यहॉं पर एक, दो सुझाव दिये थे और बोल रहे थे खास करके, वे एक बॉध के बारे में बता रहे थे गया जिला का, तो वह 1973 से 77-78 में जो किसानों को पानी मिलता रहा, उतना पानी अभी किसानों को नहीं मिल रहा है, यह उन्होंने कहा था और यह वर्ष 2005 के पूर्व बिहार में 2148 हेक्टेयर क्षेत्र में लोगों को सिंचाई क्षमता मिलती थी, सिंचाई के इस ऑकड़े में काफी वृद्धि हुई है और इस वर्ष 2018-19 में 2656. 54 हजार हेक्टेयर में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है और दूसरा उनका एक और था तिलैया ढ़ाढर योजना, इस योजना में ओरिजनली 34700 हेक्टेयर में एरिगेशन देना था, दो लाख फीट पानी झारखंड राज्य से नहीं मिलने के कारण जल संसाधन विभाग, भारत सरकार के पास जो ट्रिब्यूनल है, उसमें वर्ष 2018 में गया हुआ है, इस योजना को बाईफरकेट करके इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और 6900 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई सुविधा

मिलेगी, इस योजना का काम दिसम्बर, 2019 में पूरा हो जायेगा और इससे सिंचाई की सुविधा दिसम्बर, 2019 से होना शुरु हो जायेगा । ऐसे ही एक विषय उठाये थे विजय प्रकाश जी, सप्तकोशी डैम का, हमलोगों का भी एरिया है, पूरा कोशी को लोग शैरो, दुखद, कोशी से किसी को अच्छा भाव नहीं आता है और यह कोई तूफान लेकर ही आयेगा, ऐसी भावना हमेशा कोशी के बारे में रहती है और यह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही सुनते रहे हैं कि कोशी में डैम बनेगा, तो उसको ले करके हमने पिछले दिनों दिल्ली भी गया था, जो मंत्री थे उनसे मिला था और जो नये मंत्री बने हैं और विराटनगर में इसका ऑफिस बना हुआ है और इसका डी0पी0आर0 फाइनल होना है, भारत सरकार के रिप्रजेनटेटिव है, नेपाल सरकार के रिप्रजेनटेटिव है लेकिन बिहार का कोई भी रिप्रजेनटेटिव उसमें नहीं है, हमलोगों ने आग्रह किया उनसे कि बिहार का भी रिप्रजेनटेटिव उसमें होना चाहिए, अगर उसमें कोई सहयोग करना हो बिहार को, तो वह उसमे सहयोग करेगा और वह शायद इसमें कंसीड्रेशन कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग भी 31 अगस्त, 2019 को बुलायी है, जो ज्वायंट एक्सपर्ट का मीटिंग होने वाला है और उसके बाद इसका डी0पी0आर0 फाइनल हो जायेगा, वहॉ नेपाल में थोड़ी समस्या है कि वहॉ के जो लोकल लोग हैं, डी0पी0आर0 में जब डिलिंग करने जाता है, तो उसको वे रोकते हैं, उनका कहना है कि उस समय जो पेमेन्ट तय हुआ था, तो वह पेमेन्ट उन्हें नहीं मिला है और जबकि एम0ई0ए0 का मानना है और हमने दिल्ली में भी पता किया, तो पता चला कि उस समय पेमेन्ट दे दिया गया था, तो यह सब कन्फ्यूजन को ले करके और यह सही बात है कि जब तक कोशी में डैम नहीं बनेगा, तब तक उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बनी रहेगी, तो हमलोग निश्चित तौर पर अपनी तरफ से, चूंकि इसमें भारत सरकार को परशू करना है और वे इसको परशू करते रहेंगे और जिन सदस्यों ने सुझाव दिया है, हमने उसे नोट किया है, जहॉ कुछ जांच की बात आयी है, निश्चित रुप से विभाग उन सब चीजों को देखेगा ।

मैं खास करके इस विषय में जो मौजूदा जलवायु परिवर्तन अभी कोई भी अखवार, कोई भी टी0भी0, कोई भी बहस देखिये, तो सारा जगह जल संकट और जलवायु परिवर्तन की ही बात आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कन्सर्न को देखते हुए, यह सिर्फ इसी देश की ही बात नहीं है, यह ग्लोबल फेनोमेना हो गया है, आज फ्रांस में कल आपलोग टी0भी0 में देखे होंगे, पहले लोग यूरोप में गर्मी में जाते थे और आज फ्रांस में 46 डिग्री से ज्यादा टेम्प्रेचर

हो गया, जो कभी भी कोई सोचता नहीं था । हमलोग मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं, मिथिलांचल क्षेत्र में अगर एक बार चापाकल कों दबाते थे, तो एक जग पानी भड़ जाता था, आज हाल यह है कि उसका वाटर लेवेल इतना नीचा चला गया है कि पूरा दरभंगा में जो कभी कोई सोचता नहीं था कि दरभंगा में भी वाटर लेवेल नीचा चला जायेगा और आज हाल यह है कि पीने के पानी की समस्या वहॉ पर है और अभी मैं दरभंगा गया था तो लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी का हर घर नल का जल योजना नहीं होता तो शायद पीने के पानी की और भयंकर समस्या हमलोगों को झेलना पड़ता, इसी नल जल योजना से हमलोगों को पीने के पानी की सुविधा मिली, तो इतना बड़ा कन्सर्न मुख्यमंत्री का, इशू तो आज आ रहा है जल संकट का और 2016 में ही इन्होंने सोच लिया कि पाईप वाटर सप्लाई से लोगों को पानी पिलाना है और आज 2019 में हमलोग बैठे हुए हैं, तो आप सोचिये कि तीन साल पहले से बिहार सरकार इस योजना को लागू करके और पाईप वाटर सप्लाई से गॉवों में भी लोगों को पीने का पानी मिलेगा, यह कहॉ उस समय किसी को यह समझ में भी नहीं आता था, लोग समझता था कि यह तो शहर में मंत्री, विधायक और अफसर के लिए था लेकिन आज गॉवों में लोगों को पीने का पानी मिल रहा है जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इसी महीने की 13 जुलाई को इसी पर डिबेट भी रखा है और शायद यह पूरे दिन का है और आसन के द्वारा भी कहा गया था कि इतना बड़ा बहस है, शायद देश में पहली बार सारे विधायक, एम0एल0सी0 और सारे लोग इस विषय पर अपनी बात को रखेंगे और उसपर डिसकश करेंगे और सही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है, तो यह सही में यह केवल बिहार ही नहीं, जो हमलोग समझ पा रहे हैं, अगर हमलोग चेते नहीं अभी, तो अगली जेनरेशन हमलोगों को माफ नहीं करेगा, इतनी बड़ी संकट जल की आने वाली है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर ही विभाग में दो पार्ट किया गया, एक सिंचाई का पार्ट और एक जो फ्लड का जो मैनेजमेंट है, उसको ले करके है । महोदय, जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व मध्यम एवं वृहद् योजनाओं का विकास, रख-रखाव, संचालन एवं बाढ़ सुरक्षात्मक एवं जल निकासी के कार्यो का संवादन करना है । इस योजना में बिहार में 53.53 लाख हेक्टेयर के विरुद्व अब तक हमलोग 30 लाख हेक्टेयर के आस-पास सिंचाई सृजन कर पाये हैं और करीब साढ़े 23 लाख हेक्टेयर सिंचाई सृजन और हमलोगों को करना है । महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना

चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से अब तक डेढ़ दशक की अवधि में बिहार राज्य में सिंचाई सृजन की कुल क्षमता करीब साढ़े तीन लाख हेक्टेयर बढ़ी है और विभाग के अंदर 1975 से लंबित पड़ी दुर्गावती जलाशय योजना वर्ष 1978 से लंबित पड़ी बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना एवं वर्षों से लंबित पड़ी उदेरास्थान बराज योजना एवं अन्य कई सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण कर कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । वर्तमान में 53 लाख हेक्टेयर जो उच्चतम अल्टीमेट सिंचाई क्षमता एवं 30.4 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में बड़ा गैप है । इस गैप को दूर करने के लिए राज्य सरकार कई महत्वाकांक्षी योजना यथा इन्द्रपूरी जलाशय योजना, कोशी मिची लिंकिंग योजना, सकरी नाटा लिंकिंग योजना, पश्चिमी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना, पूर्वी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना फेज-2, कुंदर बराज योजना, कुंडघाट जलाशय योजना, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का अवशेष कार्य, सुगर्वे वियर योजना का विस्तारीकरण कार्य एवं अन्य योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु सतत् प्रयत्नशील है ।

क्रमश:

टर्न-24/सत्येन्द्र/4-7-19

श्री संजय कुमार झा,मंत्री:(क्रमश:) इन योजनाओं के कार्यान्वयन से भूगर्भ जल स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी जिसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा । राज्य सरकार दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दे रही है । इस क्रम में जमुई जिलान्तर्गत कुण्डघाट जलाशय योजना, लखीसराय जिलान्तर्गत कुन्दर बराज योजना, मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर झील का जीर्णोद्धार, बांका जिलान्तर्गत चंदन जलाशय योजना का डिसिल्टिंग कार्य, कैमूर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पम्प नहर योजना, ढ़ड़हर पम्प नहर योजना, पटना जिलान्तर्गत दरघा नदी पर बेर्रा बराज का निर्माण, रोहतास जिलान्तर्गत कॉव जलाशय योजना, बक्सर जिलान्तर्गत मलई बराज योजना और जहानाबाद जिलान्तर्गत मंडेई वियर योजना एवं अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दे रही है । वर्ष 2019-20 में कुल 77.279 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत बिहुल नदी पर वीयर निर्माण का कार्य, दरभंगा जिला में गरौल वीयर सिंचाई योजना, कमला

नदी के बघेला घाट पर वीयर सिंचाई योजना, टिकमा नदी पर वीयर सिंचाई योजना, ये जो लास्ट तीन योजना है वह सिद्दिकी साहब के क्षेत्र में है जो कटौती प्रस्ताव आज का लेकर आये हैं, सिंचाई की योजना को लेकर के । पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन..

अध्यक्षः लगता है कि आप मंत्री जी, सिद्दिकी साहब के क्षेत्र की योजना का जिक्र कर रहे थे इसीलिए आज वे नहीं मूव किये, वे चले गये, ललित जी मूव कर दिये । सिद्दकी साहब तो आपको इस मायने में छूट देकर चले गये हैं ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्रीः लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना का आधुनिकीकरण, कुण्डघाट जलाशय योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, कर्मनाशा नदी पर जैतपुर पम्प नहर योजना, दरघा नदी पर बेर्रा बराज का निर्माण, लवाईच-रामपुर बराज सिंचाई योजना के अधीन अतिरिक्त सिंचाई सृजन कार्य ,नालंदा जिला में पंचाने नदी पर देकपुरा वीयर निर्माण कार्य, मंडई वीयर योजना आदि का कार्यान्वयन प्रगति पे है। वर्ष 2019-20 में 1,12,814 हे0 क्षेत्र में Lost Irrigation Potential को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है । इसके अन्तर्गत पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन का अवशेष कार्य, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के रिड्यूस डिस्टेंस से 268.40 तक लाईनिंग कार्य, लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण का कार्य, खड़गपुर झील के डिसिल्टेशन का कार्य, आंजन जलाशय का पुनर्स्थापन का कार्य, सूर्यगढ़ा पम्प नहर का जीर्णोद्धार कार्य, सकरी नदी पर दरियापुर वीयर के पुनर्स्थापन का कार्य, उदेरास्थान बराज के नहर प्रणालियों का लाईनिंग कार्य, सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पुनर्स्थापन कार्य आदि प्रमुख हैं । वर्ष 2004-05 में जहां जल संसाधन विभाग का कुल योजना व्यय 361.66 करोड़ था वह वर्ष 2018-19 में ये बढ़ कर 2964.14 करोड़ हो गया है जो लगभग 720 प्रतिशत का बढ़ोत्तरी है । वर्ष 2005 से 2018-19 में ये 720 प्रतिशत का बढ़ोत्तरी हुआ है जिसको सराहनीय माना जायेगा । महोदय, नदी जोड़ योजना, कोसी-मेची लिकिंग योजना, ये नदी लिकिंग योजना जो है । केन बथवा एक पहला सेंक्शन हुआ मध्य प्रदेश में और दूसरा कोशी-मेची लिकिंग योजना से अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियां इस चार जिलों के 21 ब्लौक में 2,10,516 हे0 क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इस योजना पर लगभग 4900 करोड़ रू0 खर्च होगा और ये जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, यह योजना उसके पास पेंडिंग था, उनका कुछ शर्त्त था जो नेशनल वाटर डेवलपेंट बोर्ड के पास पेंडिंग था, मैं भी जाकर

मिला है भारत सरकार में, पहली बार मंत्री जी से मिलकर आया और मिलने के बाद जो कुछ डेटा वे मांगे थे वह डेटा उनको उपलब्ध करा दिया गया है और बिहार कैडर के वहां पर सिक्रेटरी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन में ये योजना वहां से क्लियर हो जायेगा जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए होगी । अभी तक इंटरलिकिंग ऑफ रिवर का काम केनबथवा के बाद दूसरी योजना बिहार का ये शुरू होगा और इससे पूरा जो आपका सीमांचल एरिया है, वह पूरा एक ग्रीन एरिया होगा, ये जो चारों जिला मैंने बताया वह उसमें आपको ये हो जायेगा और हमलोग ये भी कोशिश करेंगे कि अगर नेशनल प्रोजेक्ट में, इससे फल्ड की क्वांटिटी भी उससे घटेगी और हमलोग कोशिश करेंगे कि अगर भारत सरकार उसको नेशनल प्रोजेक्ट में लेता है, केनबथवा को भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट में ले लिया है और उसका जो कंडीशन है कि अगर 2 लाख हे0 से ऊपर जमीन का अगर इरीगेशन फैसिलिटी है तो उसको वह नेशनल प्रोजेक्ट में ले सकती है तो उसमें 90 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है लेकिन एक बार 15 दिन के बाद पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस आ जाता है तो हमलोग ये भी भारत सरकार में इस चीज को भी प्रसू करने का काम करेंगे । दूसरा, सकरी नाटा लिकिंग योजना, यह दूसरी महत्वपूर्ण योजना-सकरी नदी पर बकसोती बराज से नहर निकालकर आहर पईन को जोड़ते हुए नाटा नदी में जलान्तरण की योजना है । यह योजना केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति की प्रक्रिया में है । इस योजना में सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण कर 20 हजार हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सकरी नदी पर पूर्व से निर्मित पौरा वीयर योजना में जल की उपलब्धता को बढ़ाते हुए 31,370 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है इसके अतिरिक्त नाटा नदी पर निर्मित वीयर को बराज में परिवर्तन करते हुए 17,438 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है । इस प्रकार इस योजना से कुल 68,808 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिसका लाभ नावादा, नालंदा, शेखपुरा एवं जमुई जिला के किसानों को मिलेगा । इस योजना के अन्तर्राज्जीय पहलुओं पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28-6-18 को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक में सकरी एवं नाटा सब-बेसीन में क्रमशः 159 एम0सी0एम0, मिलियन क्यूबिक मीटर एवं 16.59 मिलियन क्यूबिक मीटर जल के उपयोग को सीमित करते हुए बकसोती बराज

को पुनरीक्षित बराज परियोजना को पुनरीक्षित करने हेतु निदेशित किया गया है जिसके आलोक में डी0पी0आर0 को रिभाईज करके उसका काम प्रक्रियाधीन है। बूढ़ी गंडक नून बया गंगा लिंक योजना, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा राज्य की अन्य नदी की जोड़ की योजनाओं की संभावना पर कार्य किया जा रहा है । इसमें मुख्य रूप से बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक योजना है । इस योजना के डी0पी0आर0 पर केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व के प्रस्ताव के अनुरूप बाढ़ शमन (Flood Moderation) ही रखा जाय । इस आलोक में नेशनल डेवलपमेंट वाटर ऑथिरिटी के द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है । फरक्का बराज के कुप्रभाव के रूप में बिहार में उत्पन्न गाद की समस्या । बिहार राज्य में गंगा नदी कीं पूरी लम्बाई 445 कि0मी0 है, इसमें अत्यधिक गाद जमाव से जिसकी पुष्टि विभिन्न तकनीकी प्रतिवेदनों से होती है । गाद की समस्या के चलते गंगा की अविरलता क्षीण हो रही है जबकि गंगा के निर्मलता जिस पर मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि गंगा की निर्मलता उसकी अवरिलता के बिना संभव नहीं है । गाद की समस्या की विकरालता को समझने एवं इसके समाधान सुझाव हेतु दो सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन 25-26 फरवरी, 2017 और दूसरा 2018-19 में मई, 2017 को एक पटना में और एक नई दिल्ली में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था एवं उसके फलाफल को आवश्यक कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग, भारत सरकार को भेजा गया । ज्ञात हो कि गंगा नदी के तल में अत्यधिक सिल्ट के जमा होने से इसका तल निरंतर ऊंचा होता जा रहा है । परिणामत: भागलपुर में गंगा नदी का स्तर सिर्फ भागलपुर ही नहीं पटना तक उसमें सिल्टेशन के वजह से उसका हाईट बढ़ रहा है । जहां वर्ष 2013 में भागलपुर में गंगा नदी में 34.50 मीटर था जो उच्चतम बाढ़ स्तर था, एच0एफ0एल0 था उसका वह वर्ष 2016 में 21 से0मी0 बढ़ गया । उसी तरह पटना के गांधी घाट में गंगा नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर जो एच0एफ0एल0 है वह वर्ष 1994 से 50.27 मीटर था वह वर्ष 2016 में बढ़कर 25 से0मी0 बढ़ गया । (क्रमश:)

टर्न-25/मधुप/04.07.2019

...क्रमश:...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : स्पष्ट है कि फरक्का बराज संरचना में मोडिफिकेशन की नितांत आवश्यकता है, उसका जो भी वे-आउट निकले लेकिन बिहार उससे सफर कर

रहा है, जब बिहार के पटना तक यह स्थिति आ गई है तो कोई न कोई उसका रास्ता निकालना पड़ेगा जो वहाँ इससे सिल्टेशन हो रहा है । सिल्ट का बहाव बराज के डाउन-स्ट्रीम में नियमित रूप से हो सके एवं गंगा नदी के तल स्तर की ऊंचाई की वृद्धि पर अंकुश लग सके । यह जरूर प्रयास विभाग के द्वारा किया जायेगा ।

बिहार राज्य में बाढ़ की विकरालता - इसी इशू पर एक कमिटी बनी एच0बी0 पाण्डया की अध्यक्षता में जिसमें 11 सदस्य थे, बिहार के भी 5 सदस्य थे लेकिन दोनों में एकमत नहीं हो पाया, बिहार के लोगों का जो मत था, वह भिन्न था जो भारत सरकार में जो कमिटी के लोग थे, इनलोगों को भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया इसीलिये उससे कोई फलाफल नहीं निकल पाया है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार के अन्दर विभिन्न नदियों से यह आवश्यक है कि बिहार में बाढ़ एवं गाद की समस्या के निराकरण हेतु वास्तविक स्थलीय स्थिति के अनुरूप अध्ययनोपरांत ठोस कार्रवाई की जायेगी ।

जल संरक्षण एवं इसका बेहतर उपाया - मूलतः बिहार को एक जल-सम्पन्न प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आप जो चाहते हैं, बिना बोले भी कर सकते हैं । मंत्री जी आप अपना वक्तव्य जारी रखिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जल के प्रति हमारी पारंपरिक व सांस्कृतिक अवधारणाओं में संचय एवं संरक्षण महत्वपूर्ण रहे हैं । तथापि विगत वर्षों में जल भंडारण के ह्रास की गति काफी तेज हुई है । जल संकट एक वैश्विक व राष्ट्रीय संकट के रूप में हमारे सामने आया है। कृषि एवं अन्य कार्य के लिए भूगर्भीय जल के दोहन के साथ-साथ नदियों एवं वर्षा से प्राप्त जल के समुचित प्रबंधन के अभाव में देश के अनेको-अनेक हिस्सों की तरह बिहार के लिए भी यह संकट गहराता जा रहा है ।

जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रणाली विकसित करने के प्रति हमें सामूहिक रूप से संकल्पित होने की आवश्यकता है। इस कार्य में वृहद् जनभागीदारी सुनिश्चित करना, जल संरक्षण एवं संवर्धन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना, जन संचार, कृषक समूहों व नागर समाज की सहभागिता से जल संसाधन के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना विभाग की आगामी सोच व दृष्टिकोण के कुछ मुख्य आयाम हैं ।

यहाँ पर मैं सदन का ध्यान चेन्नई शहर के वर्त्तमान जल संकट की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनडेटरी है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब जी, आपसे यही काम न हम शांतिपूर्वक करने का अपील कर रहे थे ! काहे को बेकार का बोलकर जाते हैं ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : वहाँ पिछले 3 वर्षों में नॉर्थ इस्ट मॉनसून के फेल करने एवं पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण इस शहर के 4 मुख्य जलाशयों की स्थिति यह है कि उनका जल संग्रहण 1 प्रतिशत से भी कम हो गया है एवं वहाँ के निवासियों का जीवन दुरूह हो गया है । नीति आयोग के ऑकड़े के अनुसार चेन्नई समेत भारत के 21 मुख्य शहर सन् 2020 तक जीरो-डे अर्थात् नगण्य भू-गर्भ जल की स्थिति में होंगे ।

जल के संरक्षण हेतु लगभग 2300 साल पहले मौर्य काल में विकसित परम्परागत सिंचाई प्रणाली यथा आहर पईन सिंचाई प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है । इस कार्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद होगी एवं भू-गर्भ जल स्तर में वृद्धि होने से कृषकों को सिंचाई की सुविधा सुगमता पूर्व मिल सकेगी । चेक डैम के निर्माण से भू-गर्भ जल स्तर में वृद्धि होगी जिसपर विभाग द्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मुंगेर जिलान्तर्गत रतनी चेक डैम, खैरा ग्राम के निकट 4 अदद चेक डैम, पहाड़ियों से नि:सृत झरनों पर आधारित योजना, भागलपुर जिलान्तर्गत अम्बा ग्राम में नलकूप का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी एवं भाकपा(माले) के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहते हुए सदन से वाक-आउट किया गया)

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 21 जून, 2019 को विभाग के क्रियाकलापों और प्राथमिकताओं की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा उद्घोषित सुझाव व मार्गदर्शन से स्पष्ट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एवं भूगर्भीय जल के भंडारण को विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल करना अनिवार्य हो गया है ।

विभाग जल के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु वैश्विक रूप से किए जा रहे आधुनिक तकनीकों को आत्मसात करने के प्रति भी कृतसंकल्पित

है तथा आवश्यकतानुसार इस दिशा में विशेषज्ञों से परामर्श एवं वैश्विक स्तर पर नए-नए तकनीकों के ग्रहण हेतु भी सभी अपेक्षित कार्रवाई करेगा ताकि राज्य जल प्रबंधन में एक मॉडल के रूप में देश में अपना स्थान बना सके ।

अपशिष्ट जल के बेहतर उपयोग हेतु पटना स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट यथा बेउर, करमलीचक, सैदपुर, कंकड़बाग, पहाड़ी एवं दीघा से निःसृत जल के उपयोग के लिए डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है, जो रूपए 307.84 करोड़ की योजना है एवं जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है ।

बाढ़ प्रक्षेत्र : तटबंध निर्माण- जल संसाधन विभाग के द्वारा बाढ़ की समस्या के निदान के लिए बिहार राज्य के अन्दर 3790 किलोमीटर तटबंध एवं नेपाल भाग में 68 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कराया गया है । तटबंध द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना बाढ़ शमन की एक अप्लकालीन योजना है। बाढ़ के दीर्घकालीन समाधान हेतु नेपाल में कोसी, कमला एवं बागमती नदियों पर जलाशय का निर्माण फ्लड कुशण के साथ किया जाना आवश्यक है जिससे कि नदियों से आने वाली सिल्ट को रोका जा सके एवं बाढ़ की अवधि में इन नदियों से नियंत्रित जलश्राव का प्रवाह हो सके । सप्तकोसी हाईडैम के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर विराटनगर नेपाल में जल संसाधन मंत्रालय, भरत सरकार के द्वारा एक कार्यालय खोला गया है । जल्दी ही इसपर, डी0पी0आर0 के काम के लिए हमने भी अनुरोध किया है और उसपर काम चल रहा है ।

बाढ़ 2019 की जो तैयारी है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के दौरान नदियों के व्यवहार एवं आक्राम्यता की समस्या के आलोक में संवेदनशील स्थलों की पहचान कर 208 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई है । इन योजनाओं में से 202 अदद योजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है । 06 योजना का काम जिसमें संरचना निर्माण एवं ड्रेजिंग का काम शामिल है, को बाढ़ 2019 के पश्चात् 15 अक्टूबर के बाद इस काम को पूरा कर लिया जायेगा ।

बाढ़ 2019 का सामना करने के लिए सभी आक्राम्य स्थलों पर यथासंभव बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण कर लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, एस0ओ0पी0 बना हुआ है डिपार्टमेंट में, उस एस0ओ0पी0 में सारा डिटेल कि क्या फौलो करना है इंजीनियर्स को, जो लोग बैठे हुये हैं, उसमें 3790 कि0मी0 जो हमारा बॉंध है, उसमें हरेक 1 कि0मी0 पर एक होमगार्ड का

रहना आवश्यक है, 15 जून के बाद उनका पदस्थापन हो गया है, चौकीदार को रहना है, उनका पदस्थापन हो गया है । चौकीदार अपने गॉव में नहीं रहे, बगल के एरिया में रहे, उसकी व्यवस्था की गई है । मोबाइल वैन जो ट्रैक्टर और ट्रौली के साथ रहता है उसमें हैलोजन लाईट, उसमें पत्थर जो होता है वह, सैंड, सीमेंट का जो बोरा होता है वह, 10 मजदूर । वह हरेक जगह बाढ़ के समय में उसका मूवमेंट रहे कि कभी कोई क्राइसिस हो तो वहॉ पर रहे । वहॉ पर बाढ़ में जगह-जगह पर शेड बनाकर जो इंजीनयर्स वगैरह हैं, वह भी वहॉ रात में रहकर फ्लड मोनिटरिंग को वहॉ पर देखते हैं और बाढ़ नियंत्रण आदेश 2019 के तहत सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/अभियंताओं को यह निदेशित किया गया है कि सभी आक्राम्य स्थलों पर कार्यान्वित किये जाने वाले संघर्षात्मक कार्यों के बारे में विभागीय वरीय पदाधिकारियों के अलावा जिला पदाधिकारी, डी0डी0सी0, एस0डी0ओ0, बी0डी0ओ0, सी0ओ0 और जो लोकल जन-प्रतिनिधि हैं, उनको भी जानकारी दे दिया जाय कि कहॉ-कहॉ काम हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध कर दीजिये । बाकी, माननीय मंत्री जी का जो लिखित वक्तव्य है वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजनाओं के लिए मॉगी गई बजट में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है वो बिहार के समग्र उत्थान का अवरोधक एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प ''न्याय के साथ विकास'' के मार्ग को अवरूद्ध करने वाला, जनहित से कोसों दूर एवं मात्र राजनीतिक मंशा के तहत लाया गया मॉग है, जो कदापि स्वीकार्य नहीं है । सिंचाई की सुविधा पहुँचाने में कटौती का प्रस्ताव दिया जाना बिल्कुल ही किसान विरोधी एवं राज्य हित के विपरीत है । ...

क्रमशः...

टर्न-26/आजाद/04.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि जल संसाधन विभाग सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रबंधन जैसे मुख्य कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ जल

संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता और इससे संबंधित जरूरी निकायों के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित करने हेतु कृतसंकल्पित हूँ ।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कटौती प्रस्ताव को वापस लिया जाय और बजट को पारित किया जाय ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रू0 से घटाई जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च,2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 36,52,30,15,000/- (छत्तीस अरब बावन करोड़ तीस लाख पन्द्रह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 4 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 30 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 05 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

मांग संख्या–49, जल संसाधन विभाग के वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के दौरान माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के अभिभाषण हेतु सामग्री

सिंचाई

- मौजूदा जलवायु परिर्वतन की वैश्विक समस्या के साथ–साथ गहराते जल संकट के बीच राज्य में भयंकर सूखे की संभावना उत्पन्न हो गई है, जिसका प्रभाव पिछले वर्षों की अपेक्षा और विकट होने का अनुमान है। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा विधान मंडल के माननीय सदस्यों की एक विशेष सभा इसी महीने की 13 तारीख को आहूत करने के पीछे मूल उद्देश्य आसन्न सूखाड़ से निबटने की हमारी तैयारी को पूर्ण तथा सुदृढ़ करना है। इस क्रम में सिंचाई की वर्त्तमान व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है।
- वैश्विक जलवायु परिर्वतन से बिहार भी अछूता नहीं है एवं इसका प्रतिफल के रूप में तापमान में वृद्धि हो रही है तथा भू–जल का स्तर भी निरंतर गिरता जा रहा है। फ्रांस जैसे ठण्डे देश में भी इस वर्ष अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाढ़ प्रवण मिथिलांचल क्षेत्र, जो मीठे भू–जल का एक बड़ा भंडार हुआ करता था वहाँ भी भू–जल का स्तर काफी नीचे चला गया है एवं गर्मी के दिनों में पेय जल का संकट गहराता जा रहा है। इस समस्या पर शीघ्र विचार आवश्यक है अन्यथा स्थिति और भयावह हो सकती है।

- जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व वृहद् एव मध्यम सिंचाई योजनाओं का विकास, रख–रखाव, संचालन तथा बाढ़ सुरक्षात्मक एवं जल निकासी कार्यों का सम्पादन करना है। वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना से संभावित ultimate ~~ईष्टतम्~~ सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध अब तक 30.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका है। महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से अब तक डेढ़ दसक की अवधि में राज्य में सिंचाई की कुल सृजित क्षमता बढ़ कर 30.04 लाख हेक्टेयर हो गया है। विभाग के अंतर्गत 1975 से लंबित पड़ी दुर्गावती जलाशय योजना, वर्ष 1978 से लंबित पड़ी बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना एवं वर्षों से लंबित पड़ी उदेरास्थान बराज योजना एवं अन्य कई सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण कर कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- वर्त्तमान में 53.53 लाख हेक्टेयर ultimate ~~ईष्टतम~~ सिंचाई क्षमता एवं 30.04 लाख हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में बड़ा गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए राज्य सरकार कई महत्त्वकांक्षी सिंचाई योजनाएँ यथा इन्द्रपुरी जलाशय योजना, कोसी मेची लिंकिग योजना, सकरी–नाटा लिंकिग योजना, पश्चिमी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना, पूर्वी गंडक नहर विस्तारीकरण योजना फेज–2, कुंदर बराज योजना, कुण्डघाट जलाशय योजना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य, सुगरवे वीयर योजना का विस्तारीकरण कार्य एवं अन्य योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से भू–गर्भ जल स्तर में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी, जिसका लाभ आम जन–मानस को मिलेगा। राज्य सरकार दक्षिण बिहार के

सूखाग्रस्त इलाकों में अवस्थित कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दे रहा है। इस क्रम में जमुई जिलान्तर्गत कुण्डघाट जलाशय योजना, लखीसराय जिलान्तर्गत कुंदर बराज योजना, मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर झील का जिर्णोद्धार कार्य, बांका जिलान्तर्गत चंदन जलाशय योजना का डिसिलटिंग कार्य, कैमूर जिलान्तर्गत कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पम्प नहर योजना, ढ़ड़हर पम्प नहर योजना, पटना जिलान्तर्गत दरधा नदी पर बेर्रा बराज का निर्माण, रोहतास जिलान्तर्गत कॉव जलाशय योजना, बक्सर जिलान्तर्गत मलई बराज योजना, जहानाबाद जिलान्तर्गत मंडई वीयर योजना एवं अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष बल दे रहा है।

वर्ष 2019–20 में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन

वर्ष 2019–20 में कुल 77,279 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। जिसके अंतर्गत बिहुल नदी पर वीयर निर्माण का कार्य, दरभंगा जिला में गरौल वीयर सिंचाई योजना, कमला नदी के बघेला घाट पर वीयर सिंचाई योजना, टिकमा नदी पर वीयर सिंचाई योजना, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन, लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना का अधुनिकीकरण, कुण्डघाट जलाशय योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पम्प नहर योजना, दरधा नदी पर बेर्रा बराज का निर्माण, लवाईच–रामपुर बराज सिंचाई योजना के अधीन अतिरिक्त सिंचाई सृजन कार्य, नालन्दा जिला में पंचाने नदी पर देकपुरा वीयर निर्माण कार्य, मंडई वीयर योजना आदि का कार्यान्वयन प्रगति में है।

Reduce Distance

ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन

वर्ष 2019–20 में 1,12,874 हे० क्षेत्र में Lost Irrigation Potential (ह्रासित सिंचाई क्षमता) को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन का अवशेष कार्य, पूर्वी सोन उच्च स्तरीय मुख्य नहर के R.D. ~~कि०मी० 0.~~ 00 से 268.40 तक लाईनिंग कार्य, लोउर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण का कार्य, खड़गपुर झील के डिसिल्टेशन का कार्य, आंजन जलाशय के पुनर्स्थापन का कार्य, सूर्यगढ़ा पम्प नहर का जीर्णोद्धार कार्य, सकरी नदी पर दरियापुर वीयर के पुनर्स्थापन का कार्य, उदेरास्थान बराज के नहर प्रणालियों का लाईनिंग कार्य, सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पुनर्स्थापन कार्य आदि प्रमुख हैं।

योजना व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि

वर्ष 2004–05 में जहाँ जल संसाधन विभाग का कुल योजना व्यय रु० 361.66 करोड़ था वह वर्ष 2018–19 में बढ़ कर रु० 2964.14 करोड़ हो गया है। इस प्रकार योजना व्यय में कुल 720 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसे सराहनीय माना जाएगा।

नदी जोड़ योजना

कोसी–मेची लिंकिग योजना

कोसी बेसीन एवं महानंदा बेसीन की नदियों को जोड़ते हुए जलान्तरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना कोसी–मेची लिंक योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियां जिले के कुल 21 प्रखंडों के 2,10,516 हे० क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना पर रु० 4900 करोड़ की लागत आएगी। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की तकनीकि सलाहकार

समिति (TAC) की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त हुई है कि इस पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert appraisal committee) की दिनांक 20.11.2018 को आयोजित 20वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने निमित मैं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से स्वयं दिनांक–17.06.2019 को मिलकर आग्रह किया हूँ। जिसका परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से वांछित आँकड़े पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वत्तन मंत्रालय, भारत सरकार को उसी शाम भेज दिया गया है। इस योजना की स्वीकृति पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से शीघ्र अपेक्षित है।

महोदय, मैं सदन को यह विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि Linking of River **योजना के तहत्** पूरे भारत में केन–बेतवा परियोजना के पश्चात् हमारे राज्य की कोसी–मेची लिकिंग परियोजना दूसरी नदी जोड़ परियोजना है, जो कार्यान्वित होने जा रहा है। यह योजना सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा। यह योजना National Project **में सम्मिलित होने की सारी अर्हतोओं को पूरी करता है। इस परिस्थिति में भारत सरकार से इस योजना को** National Project **के तहत् सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है।**

2 Lakh hectre सिंचाई
90% central funding
10% State

सकरी नाटा लिंकिग योजना

दूसरी महत्वपूर्ण योजना–सकरी नदी पर बकसोती बराज से नहर निकालकर आहर पईन को जोड़ते हुए नाटा नदी में जलान्तरण की योजना है। यह योजना केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इस योजना में सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण कर 20,000 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ सकरी नदी पर पूर्व से निर्मित पौरा वीयर योजना में जल की उपलब्धता को बढ़ाते हुए 31,370 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त नाटा नदी पर निर्मित वीयर को बराज में परिवर्तन करते हुए 17,438 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को पुनर्स्थापित किया जाना है। इस प्रकार इस योजना से कुल 68,808 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जिसका लाभ नवादा, नालंदा, शेखपुरा एवं जमुई जिला के किसानों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्राज्यीय पहलुओं पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2018 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में सकरी एवं नाटा सब–बेसीन में क्रमशः 159.20 MCM एवं 16.59 MCM जल के उपयोग को सीमित करते हुए बकसोती बराज परियोजना को पुनरीक्षित करने हेतु निदेशित किया गया जिसके आलोक में DPR को पुनरीक्षित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

Million cubic Meter

बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक योजना

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा राज्य की अन्य नदी की जोड़ की योजनाओं की संभावना पर कार्य किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक योजना है। इस योजना के DPR पर केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा सुझाव दिया

गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व के प्रस्ताव के अनुरूप बाढ़ शमन (Flood Moderation) ही रखा जाए। इसके आलोक में NWDA द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

फरक्का बराज के कुप्रभाव के रूप में बिहार में उत्पन्न गाद की समस्या

बिहार राज्य में गंगा नदी की पूरी लम्बाई 445 कि०मी० में अत्यधिक गाद जमाव है जिसकी पुष्टि विभिन्न तकनीकी प्रतिवेदनों से होती है। गाद की समस्या के चलते गंगा की अविरलता क्षीण हो रही है, जबकि गंगा की निर्मलता उसकी अविरलता के बिना संभव नहीं है। गाद की समस्या की विकरालता को समझने एवं इसके समाधान/सुझाव हेतु 2–सम्मेलन, प्रथम दिनांक 25–26 फरवरी, 2017 को पटना में तथा द्वितीय 18–19 मई, 2017 को नई दिल्ली में बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया एवं उसके फलाफल को आवश्यक कार्रवाई हेतु जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेजा गया है।ज्ञात हो कि गंगा नदी के तल में अत्याधिक सिल्ट के जमा होने से इसका तल निरंतर ऊँचा होता जा रहा है, परिणामतः भागलपुर में गंगा नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) **जहाँ वर्ष 2013 में 34.50 मी० था वह वर्ष 2016 में 21 से०मी० बढ़ कर 34.71 मी० हो गया। उसी तरह पटना के गाँधी घाट में गंगा नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) वर्ष 1994 में 50.27 मी० था वह वर्ष 2016 में 25 से०मी० बढ़ कर 50.52 मी० हो गया। स्पष्ट है कि फरक्का बराज संरचना में Modification की नितांत आवश्यकता है ताकि सिल्ट का बहाव फरक्का बराज के Down Stream में नियमित रूप से हो सके एवं गंगा नदी के तल स्तर की ऊचाई की वृद्धि पर अंकुश लग सकें।**

बिहार राज्य में बाढ़ की विकरालता एवं गाद की समस्या के निदान हेतु सुझाव देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के सेवानिवृत अध्यक्ष श्री ए0 बी0 पाण्डया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय एक समिति गठित की गई। इस समिति में बिहार राज्य का पक्ष रखने के लिए भी 5 सदस्य रखे गये। समिति की अनुशंसा में अध्यक्ष एवं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित सदस्यों एवं बिहार राज्य राज्य का पक्ष रखने से संबंधित सदस्यों के विचार में मतैक्य नहीं हुआ। बिहार राज्य के अंदर विभिन्न नदियों से संबंधित जलीय आँकड़े, जो केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर संधारित होता है एवं फरक्का बराज से संबंधित वॉछित आँकड़े समिति के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया। यह आवश्यक है कि बिहार में बाढ़ एवं गाद की समस्या के निराकरण हेतु वास्तविक स्थलीय स्थिति के अनुरुप अध्ययनोंपरान्त ठोस कार्रवाई की जाय।

जल संरक्षण एवं इसका बेहतर उपयोग

मूलतः बिहार को एक जल–सम्पन्न प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है। जल के प्रति हमारी पारंपरिक व सांस्कृतिक अवधारणाओं में संचय व संरक्षण महत्वपूर्ण रहे हैं। तथापि, विगत वर्षों में जल भंडारण के ह्रास की गति काफी तेज हुई है। जल संकट एक वैश्विक व राष्ट्रीय संकट के रूप में हमारे सामने है। कृषि एवं अन्य कार्य के लिए भूगर्भीय जल के दोहन के साथ–साथ नदियों एवं वर्षा से प्राप्त जल के समुचित प्रबंधन के अभाव में देश के अनकों–अनेक हिस्सों की तरह बिहार के लिए भी यह संकट गहराता जा रहा है।

जल के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रणाली विकसित करने के प्रति हमें सामूहिक रूप से संकल्पित होने की आवश्यकता है। इस कार्य में वृहद् जनभागीदारी

सुनिश्चित करना, जल संरक्षण एवं संवर्धन की संस्कृति को प्रोत्साहित करना, जन संचार, कृषक समूहों व नागर समाज की सहभागिता से जल संसाधन के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना विभाग की आगामी सोच व दृष्टिकोण के कुछ मुख्य आयाम हैं।

यहा पर मैं सदन का ध्यान चेन्नई शहर के वर्त्तमान जल संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ Rain Water Harvesting mandatory **है, वहाँ पिछले 3 वर्षों में** North East Monsoon **के** Fail **करने एवं पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण इस शहर के 4 मुख्य जलाशयों की स्थिति यह है कि उनका जल संग्रहण 1 प्रतिशत से भी कम हो गया है एवं वहाँ के निवासियों का जीवन दुरूह हो गया है। नीति आयोग के आँकड़ें के अनुसार चेन्नई समेत भारत के 21 मुख्य शहर सन् 2020 तक** ZERO DAY-**अर्थात् नगन्य भू–गर्भ जल– की स्थिति में होगें।**

लगभग 2300 साल पहले

जल के संरक्षण हेतु मौर्य काल में विकसित परम्परागत सिंचाई प्रणाली यथा आहर पईन सिंचाई प्रणाली को **पुनर्जीवित** (Revive) **किया जाना आवश्यक है। इस कार्य से** Rain Water Harvesting **(वर्षा जल संरक्षण) में मदद होगी एवं भू–गर्भ जल स्तर में वृद्धि होने से कृषकों को सिंचाई की सुविधा सुगमता पूर्वक मिल सकेगी। चेक डैम के निर्माण से भू–गर्भ जल स्तर में वृद्धि होती है जिस पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मुंगेर जिलान्तर्गत रतनी चेक डैम, खैरा ग्राम के निकट 4 अद्द चेक डैम, पहाड़ियों से निःसृत झरनों पर आधारित योजना, भागलपुर जिलान्तर्गत अम्बा ग्राम में नलकूप का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया गया है।**

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 21 जून, 2019 को विभाग के क्रियाकलापों और प्राथमिकताओं की समीक्षा बैठक में उनके द्वारा उद्घोषित सुझाव व मार्ग दर्शन से स्पष्ट है कि वर्षाजल के संरक्षण (Rainwater harvesting), अपशिष्ट जल प्रबंधन (Waste water management) एवं भूगर्भीय जल के भंडारण को विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल करना अनिवार्य हो गया है।

विभाग जल के बेहतर प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु वैश्विक रूप से किए जा रहे आधुनिक तकनीकों को आत्मसात करने के प्रति भी कृतसंकल्पित है तथा आवश्यकतानुसार इस दिशा में विशेषज्ञों से परामर्श एवं वैश्विक स्तर पर नए–नए तकनीकों के ग्रहण हेतु भी सभी अपेक्षित कार्रवाई करेगी ताकि राज्य जल प्रबंधन में एक मॉडल के रूप में देश में अपना स्थान बना सके।

अपशिष्ट जल के बेहतर उपयोग हेतु पटना स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट यथा बेउर, करमलीचक, सैदपुर, कंकड़बाग, पहाड़ी एवं दीघा से निःसृत जल के उपयोग के लिए डी०पी०आर० तैयार किया गया है, जो रुपए 307.84 करोड़ की योजना है एवं जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

बाढ़ प्रक्षेत्र

तटबंध निर्माण

जल संसाधन विभाग के द्वारा बाढ़ की समस्या की निदान के लिए बिहार राज्य के अन्दर 3790 किलोमीटर तटबंध एवं नेपाल भाग में 68 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कराया गया है। तटबंध द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना बाढ़ शमन की एक अल्पकालीन

योजना है। बाढ़ के दीर्घकालीन समाधान हेतु नेपाल में कोसी, कमला एवं बागमती नदियों पर जलाशय का निर्माण फ्लड कुशण के साथ किया जाना आवश्यक है जिससे कि नदियों से आने वाली सील्ट को रोका जा सके एवं बाढ़ की अवधि में इन नदियों से नियंत्रित जलश्राव का प्रवाह हो सके। सप्तकोसी हाईडैम के निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार कर बिराटनगर नेपाल में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक कार्यालय खोला गया है। परंतु इस कार्य हेतु बिहार से किसी प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 17.06.2019 को मिलकर सप्तकोसी हाईडैम के डी.पी.आर. तैयारी कार्य में तेजी लाने हेतु आग्रह किया हूँ और इस कार्य में बिहार से किसी प्रतिनिधि को सम्मिलित करने हेतु भी अनुरोध किया हूँ।

बाढ़ 2019 की तैयारी

- बाढ़ 2018 के दौरान नदियों के व्यवहार एवं आक्राम्यता की समस्या के आलोक में संवेदनशील स्थलों को पहचान कर कुल 208 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान की गई है। इन योजनाओं में से 202 अदद योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष बचे 06 अदद योजनाएं जिनमें संरचना निर्माण एवं ड्रेजिंग कार्य सम्मिलित है को बाढ़ 2019 के पश्चात् पूर्ण कर लेने का कार्यक्रम है।

- बाढ़ 2019 का सामना करने के लिए सभी आक्राम्य स्थलों पर यथावश्यक बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का भंडारण कर लिया गया है। बाढ़ प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं के द्वारा स्थल पर कैम्प निर्माण स्थल पर श्रमिकों एवं अभियंताओं को ठहरने के लिए कैम्प की व्यवस्था कर लिया गया है। इसके अलावे अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में तटबंध के प्रत्येक

- कुछ में Dredging करना है बाढ़ के बाद होगा
- Anti flood Sluice के Gate बदलने का निर्माण है

किलोमीटर पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। बाढ़ नियंत्रण आदेश 2019 के तहत सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों अभियंताओं को यह निदेशित किया गया है कि सभी आक्राम्य स्थलों पर कार्यान्वित किये जाने वाले बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के बारे में जानकारी विभागीय वरीय पदाधिकारियों के अलावे संबंधित जिला पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को भी दी जाय।

टाल विकास योजना

बिहार राज्य का 9.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित है, जिसमें 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल निकासी का कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है। अब तक 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सका है एवं शेष क्षेत्र के लिए योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।

बिहार सरकार द्वारा पटना, नालंदा, शेखपुरा एवं लक्खीसराय जिले में कुल 1.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 7–टालों के समूह से जल निकासी एवं जल के बेहतर आर्थिक उपयोग हेतु रु० 1892 करोड़ रूपये की लागत राशि पर डी०पी०आर० तैयार किया गया है। इस डी०पी०आर० पर टाल क्षेत्र के कृषकों का सुझाव आमंत्रित किया गया है। जिसके आलोक में डी०पी०आर० को अंतिम रूप दे कर इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का कार्यक्रम है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया हूँ कि उत्तर कोयल जलाशय योजना के तर्ज पर Long Term Irrigation Fund (L.T.I.F) के अंतर्गत जल जमाव से मुक्ति की इस योजना पर 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करें।

बाढ़ प्रबंधन कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग

आधुनिक तकनीक का उपयोग विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसका प्रतिफल के रूप में कोसी तथा बागमती–अधवारा बेसीन के लिए 72 घंटे लीड टाइम के बाढ़ पूर्वानुमान निर्गत करना संभव हुआ है। साथ ही गंडक नदी के लिए भी प्रायोगिक रूप से 72 घंटे लीड टाइम के बाढ़ पुर्वानुमान निर्गत करने की तकनीक विकसित कर ली गई है। Centre of Excellence के तहत् एक गणितीय प्रतिमान केन्द्र (MMC) की स्थापना अनिसाबाद, पटना में की गई है। सुपौल जिला के वीरपुर में भौतिक प्रतिमान केन्द्र (PMC) की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है। National Hydrology Project के तहत् पटना में वॉटर नॉलेज केन्द्र की स्थापना की जानी है। Real Time Data Acquisition System के अन्तर्गत पाँच बेसिनों एवं 18 जलाशयों में Hydromet Instruments के अधिष्ठापन का कार्यक्रम है जिससे नदियों एवं जलाशयों का वास्तविक समय आधारित आँकड़ों का संग्रहण हो पाएगा। विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र के अपग्रेडेशन हेतु 20.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- सभापति महोदय, विपक्ष के मेरे माननीय विद्वान मित्रों ने जल संसाधन विभाग के महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजनाओं के लिए माँगी गई बजट में जो कटौती प्रस्ताव लाया है वो बिहार के समग्र उत्थान का अवरोधक एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प "न्याय के साथ विकास" के मार्ग को अवरूद्ध करने वाला, जनहित से कोसों दूर एवं मात्र राजनीतिक मंशा के तहत् लाया गया मांग है, जो कदापि स्वीकार्य नहीं है। सिंचाई की सुविधा पहुचाने में कटौती का प्रस्ताव दिया जाना बिलकुल ही किसान विरोधी एवं राज्य हित के विपरीत है।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व जल प्रबंधन जैसे मुख्य कार्यों के निर्वहन के साथ–साथ जल संरक्षण के प्रति सामाजिक जागरूकता और इससे संबंधित जरूरी निकायों के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित करने हेतु कृतसंकल्पित है।